चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

09 सितंबर–15 सितंबर 2013

मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं

फोटो–प्रभात पाण्डेय

कोयला घोटाले से जुड़ी गायब फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या यह सीबीआई की जांच को बाधित करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने का एक प्रयास है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का मतलब साफ है कि फाइलों को गायब करना सबूत मिटाने के बराबर है. भारत में सबूत मिटाना कानूनन जुर्म है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सकती है. जेल जाना पड़ सकता है.

क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिसंबर में जेल जाएंगे? क्या मनमोहन सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, जिन्हें जेल जाना होगा? यह सवाल दुखद है, लज्जाजनक है और चिंतित करने वाला है और इसलिए इसे उठाना आज सबसे जरूरी है. कोयला घोटाले में सरकार का जो अबतक का रवैया सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का रहा है, इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है. आजाद भारत के इतिहास में सीबीआई और सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आ रही है, वह सरकार के लिए न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि देश के प्रजातंत्र के लिए भी खतरनाक है. एक तरफ सच को साबित करने पर अड़ी देश की अदालत है तो दूसरी तरफ सवाल के घेरे में आए प्रधानमंत्री हैं. कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है, यह समझना जरूरी है. चूंकि हमने देश में सबसे पहले कोयला घोटाले को 29 अप्रैल, 2011 को उजागर किया था, इसलिए हमें इस केस को लेकर मनमोहन सिंह के जेल जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं.

मनीष कुमार

कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब हो गईं. ये फाइलें कहां गईं? क्या इन फाइलों को जमीन खा गई या कोई भूत लेकर गायब हो गया? ये फाइलें कब गायब हुईं? कहां से गायब हुईं? इन फाइलों में क्या था? क्या भारत सरकार के दफ्तर चोरों का अड्डा बन चुके हैं? या फिर इन फाइलों को गायब कर के किसी को बचाया जा रहा है? नोट करने वाली बात यह है कि कोयला घोटाला उस वक्त हुआ, जब मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे. कोयला खदानों के हर विवादित आबंटन पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं. एक तरफ सरकार है, जो सच को छुपाना चाह रही है, सीबीआई जांच में बाधा पैदा कर रही है और दूसरी तरफ अदालत है, जो कह रही है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को दंडित किया जाएगा. दिसंबर महीने में कोयला घोटाले की जांच पूरी हो जाएगी. जैसे टूजी घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर लिख कर ए राजा को गिरफ्तार किया था, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को मनमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखनी होगी. उन्हें गिरफ्तार करना होगा और बाद में उन पर मुकदमा चलेगा. इस घोटाले के केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो क्या दिसंबर में भारत को एक शर्मनाक इतिहास का मुंह देखना पड़ेगा?

कोयला घोटाले में सरकार अदालत की निगरानी में चल रही जांच को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है. सीबीआई कोयला मंत्रालय से कुछ सवाल पूछती है या फिर जानकारी मांगती है तो कोयला मंत्रालय उसे उपलब्ध नहीं कराता है. इससे भी शर्मनाक तो यह है कि सीबीआई की रिपोर्ट को सरकार बदल देती है. अगर सीबीआई किसी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करना चाहती है तो सरकार कहती है कि सीबीआई को सरकार से अनुमति लेनी होगी. हद तो यह है कि कोयला घोटाले से जुड़ी 236 फाइलों में 186 फाइलें उपलब्ध नहीं हैं. सरकार के मुताबिक, इन दस्तावेजों में 7 फाइलें और 173 आवेदन हैं, जो अभी उपलब्ध नहीं हैं. ये दस्तावेज कहां हैं, इसकी जांच के लिए सरकार की तरफ से एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सरकार की इस कमेटी पर भरोसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यह एक एक्सटरनल कमेटी है, जिससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन फाइलों को ढूंढने के लिए समय दिया है और फिर भी गुम फाइलें नहीं मिलीं तो सीबीआई में शिकायत दर्ज की जाएगी. मुकदमा चलेगा. जिम्मेदारी तय की जाएगी. यह मामला गंभीर है.

कोयला घोटाले से जुड़ी गायब फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या यह सीबीआई की जांच को बाधित करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने का एक प्रयास है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का मतलब साफ है कि फाइलों को गायब करना सबूत मिटाने के बराबर है. भारत में सबूत मिटाना कानूनन जुर्म है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सकती है. जेल जाना पड़ सकता है. यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि यह कोर्ट की अवमानना भी है. सुप्रीम कोर्ट लगातार आदेश दे रही है. फाइलों को कोर्ट में जमा करने का निर्देश देती रही है. कोर्ट इस बात पर नाराज है कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलें कोयला मंत्रालय से उपलब्ध नहीं कराई जा रहे हैं. जो फाइलें जांच के लिए जरूरी हैं, वह या तो गायब हो गई हैं या फिर उपलब्ध नहीं हैं. सरकार के इस रवैये से नाराज होकर जस्टिस लोढ़ा ने यहां तक कह दिया कि क्या यह रिकॉर्ड नष्ट करने की कोशिश है? सच तो वैसे भी बाहर आ के रहेगा, लेकिन यह इस तरह से नहीं चल सकता. जांच कैसे आगे बढ़ेगी. जो फाइलें गायब हुई हैं, वह शायद सबसे महत्वपूर्ण हों. इतना कहने के बावजूद अगर सरकार, सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री यह दलील दें कि फाइल की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो उन्हें बताना होगा कि यह किसकी जिम्मेदारी है.

> **कोयला खदानों के आबंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय की काफी सक्रिय भूमिका रही. हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े दस्तावेज को सरकार गायब घोषित करने पर तुली है. अगर सरकार गायब फाइलों को उपलब्ध नहीं करा सकती है तो इन फाइलों के गायब होने की जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री की बनती है. सिर्फ इसलिए नहीं कि मनमोहन सिंह उस वक्त कोयला मंत्री थे, बल्कि यह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी भी है. प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. कोर्ट का रवैया अगर सख्त हो गया तो इस केस से जुड़े लोगों को जेल हो सकती है.**

समझने वाली बात यह है कि कोयला घोटाले के केंद्र में मनमोहन सिंह हैं, क्योंकि यह घोटाला तब हुआ, जब मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे. उन्हीं के द्वारा ऐसी कंपनियों को कोयला खदानें आबंटित की गईं, जो इसके योग्य नहीं थीं. अयोग्य कंपनियों के आवेदन पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि बिना उनके हस्ताक्षर के किसी भी कंपनी को खदान आबंटित नहीं की जा सकती है. जिस वक्त कोयला खदानों का आबंटन किया जा रहा था, उस वक्त इससे जुड़े लोगों को यह मालूम था कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी हो रही है. कोयला सचिव लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख रहे थे कि कोयला खदानों की नीलामी हो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला सचिव के सुझावों को क्यों दरकिनार कर दिया. अगर प्रधानमंत्री ये कहें कि उन्हें कोयला सचिव की चिट्ठी के बारे में मालूम नहीं था तो कौन विश्वास करेगा. 173 अवेदन पत्र गायब हैं. सवाल यह है कि इन आवेदन पत्रों की जांच कहां हुई. उस वक्त इन आवेदनों की जांच-परख और उन कंपनियों की योग्यता की जांच कौन कर रहा था. हकीकत यह है कि कोयला खदानों के आबंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय की काफी सक्रिय भूमिका रही. हैरानी की बात यह भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े दस्तावेज को सरकार गायब घोषित करने पर तुली है. अगर सरकार गायब फाइलों को उपलब्ध नहीं करा सकती है तो इन फाइलों के गायब होने की जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री की बनती है. सिर्फ इसलिए नहीं कि मनमोहन सिंह उस वक्त कोयला मंत्री थे, बल्कि यह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी भी है. और प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. अभी कोर्ट का रवैया सख्त नहीं है, लेकिन अगर सख्त हो गया तो इस केस से जुड़े लोगों पर सबूत मिटाने का मुकदमा चल सकता है. उन्हें जेल हो सकती है.

यह इसलिए संभव है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि अगर फाइलें गायब हुई हैं तो क्या सरकार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की गई है

(शेष पृष्ठ 2 पर)

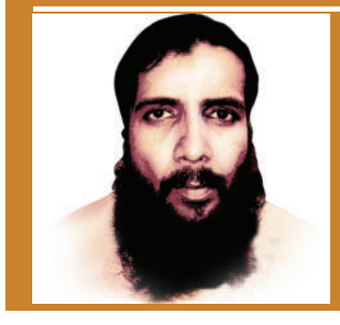

सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी से बचता रहा भटकल

03

लौटकर भाजपा मंदिर पर आई

06

मुसलमानों को धोखा दे रही है कांग्रेस

07

साईं की महिमा

12

मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं

पृष्ठ एक का शेष

या नहीं. हकीकत यह है कि सरकार ने यह तो दुनिया को बता दिया कि फाइलें गायब हो गईं, लेकिन यह नहीं बताया कि पुलिस में कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है. अब तो सरकार ही बता सकती है कि इतने महत्वपूर्ण केस की फाइलें गायब हो जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराने के पीछे क्या राज है. वैसे ये मामला जांच का विषय है, लेकिन कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कराई गई, क्योंकि फाइलें गायब नहीं हुईं, बल्कि गायब करा दी गई होंगी या फिर फाइलों को गायब बताया जा रहा है. शायद यही शक सुप्रीम कोर्ट को भी है. इसलिए तीनों जज जब सीबीआई द्वारा दी गई फाइलों की लिस्ट देख रहे थे, तब तीनों जजों ने एक राय से सरकार को चेतावनी दी है कि आप इस तरह दस्तावेजों पर नहीं बैठ सकते. सीबीआई की जांच के लिए जो दस्तावेज जरूरी है, उसे उपलब्ध कराना होगा. उन दस्तावेजों को न देने का कोई तर्क नहीं है. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सीबीआई के पास मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा. कोर्ट ने सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल वाहनवती को यह भी चेतावनी दी है कि इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है. इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये फाइलें गायब हुईं हैं या फिर गायब कर दी गईं हैं और आप सीबीआई में इसकी शिकायत कब दर्ज करा रहें, ये हमें बताइए. अब गेंद सरकार के पाले में है. अगर सरकार इन फाइलों को उपलब्ध कराती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय के कारनामे सामने आएंगे और अगर उपलब्ध नहीं कराती है तो मुकदमा चलेगा. जिम्मेदारी तय होगी. चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली हरेक सुनवाई कांग्रेस पार्टी के लिए किरकिरी का सबब बन सकती है. सवाल यह है कि मनमोहन सिंह को बचाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी यह रिस्क लेगी या मनमोहन सिंह को बचाने के लिए तत्काल लोकसभा भंग कर देगी या कोई कारण बताकर प्रधानमंत्री बदल देगी?

हिंदुस्तान की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट विश्वास की आखिरी उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो झूठे आरोप लगाए और जिसे राजनीतिक जवाब देकर टाला जा सकता है. अदातल तो सच का पता लगाती है. दूध का दूध और पानी का पानी करती है. अदातल फैसला करती है और जब तक फैसला नहीं देती, तब तक वो इशारा देती है. कोयला घोटाले में अब तक सुप्रीम कोर्ट से जो इशारे मिल रहे हैं, वह खतरनाक है.

वैसे प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश पहले भी हुई है. 26 अप्रैल, 2013 को सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया. इसमें सीबीआई ने बताया कि कोयला घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सरकारी नुमाइंदों के सामने 8 मार्च को प्रस्तुत की गई थी. ये महानुभाव थे कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ज्वॉइंट सेक्रेटरी और कोयला मंत्रालय के ज्वॉइंट सेक्रेटरी. हैरानी की बात यह है कि इससे पहले सरकार व सीबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि स्टेटस रिपोर्ट किसी को दिखाई नहीं गई है. देश के अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने कोर्ट के सामने यह झूठ बोला था कि स्टेटस रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी है. कोई नेता या अधिकारी कोर्ट में झूठ बोले, यह गुनाह है, लेकिन देश का प्रथम न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले तो यह गुनाह के साथ-साथ महापाप है, लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री की अंतर्रात्मा सोती रही और वाहनवती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

सरकार की झूठ का पर्दाफाश हो गया. जिसके खिलाफ जांच हो रही हो, उन्हीं को जांच रिपोर्ट दिखाया जाए तो इसका क्या मतलब है? सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? इस मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय का ज्वॉइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी क्या कर रहा था? वह किसकी अनुमति से इस मीटिंग में आया था? अगर कोई यह कहे कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो यह एक मजाक ही समझा जाएगा. अगर किसी प्लानिंग के तहत उस अधिकारी को इस मीटिंग में नहीं भेजा गया तो इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

हैरानी की बात तो यह है कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के चहेते कानून मंत्री, कोयला मंत्रालय व पीएमओ के अधिकारियों को सिर्फ दिखाया ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट को बदल भी दिया. यह तो चोरी और सीनाजोरी का ज्वलंत उदाहरण है. सीबीआई की जांच रिपोर्ट को बदल देना अगर अपराध नहीं है तो अपराध होता क्या है? रिपोर्ट को बदला गया, यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि 29 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने इस बात को माना कि सीबीआई की ओरिजिनल रिपोर्ट में 20 फीसद बदलाव किए गए हैं. क्यों बदला गया और अगर बदल भी दिया तो झूठ क्यों बोला? सरकार ने यह क्यों कहा कि रिपोर्ट को बदला नहीं गया, बल्कि रिपोर्ट का व्याकरण ठीक किया गया. मतलब साफ है कि सरकार कोयला घोटाले में कोर्ट में झूठ बोलती आई है. जिनकी आंखो में शर्म थी, वे इस केस से हट गए और जो बच गए, वे डटे रहे. अगले ही दिन इस मामले में सरकार की तरफ से दलील देने वाले एडिशनल सोलिसिटर जनरल हरीश रावल ने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की बात से शर्मशार होकर इस्तीफा दे दिया. जब रिपोर्ट बदलने वाली बात उजागर हुई तो हंगामा मच गया. सरकार की तरफ से मनगढ़ंत दलीलें दी गईं, लेकिन मीडिया और विपक्ष के दबाव के कारण मनमोहन सिंह को अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अश्विनी कुमार को पिछले दरवाजे से एक बार फिर से सरकार में शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जापान की यात्रा के लिए अश्विनी कुमार को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है. मनमोहन सिंह की अश्विनी कुमार से नजदीकियां और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी का इस मीटिंग में होना, इस बात के संकेत हैं कि सीबीआई जांच को बाधित करके किसे बचाने की कोशिश हो रही है. कोयला घोटाले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों वाली बेंच में चल रही है. इस बेंच के तीनों जज जस्टिस आर एम लोढ़ा, जस्टिस बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की नजर इन गतिविधियों पर जरूर होगी.

यह मामला सिर्फ गैरकानूनी कोयला खदानों के आबंटन का नहीं है. सरकारी नियमों के अनुसार, कोयले के ब्लॉक आबंटित

फोटो–प्रभात पाण्डेय

करने के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनकी साफ़ अनदेखी कर दी गई. ब्लॉक आबंटन के लिए कुछ सरकारी शर्तें होती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऐसी ही एक शर्त यह है कि जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होना है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद (और यदि वन क्षेत्र में ऐसी खदान है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है) खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है (जिसमें अगर वन क्षेत्र हो तो पहले की तरह ही छह महीने की छूट मिलती है). अगर इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर खदानों से कभी कोयला निकाला ही नहीं गया. तो सवाल यह है कि नियमों के उल्लंघन पर इन कंपनियों के खिलाफ मनमोहन सिंह ने क्यों एक्शन नहीं लिया. दोषी कंपनियों के लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किए गए. मनमोहन सिंह को इन सवालों के जवाब देने होंगे. नोट करने वाली बात यह है कि चौथी दुनिया ने सबसे पहले कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था और हमने दावा किया था कि यह घोटाला 26 लाख करोड़ का है. हमारे पास अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत आज भी मौजूद हैं. हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि यह घोटाला 26 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार ने 52 लाख करोड़ रुपये का कोयला निजी कंपनियों के साथ मिलकर बंदरबांट किया है.

कोर्ट ने सरकार को सभी गायब फाइलों को उपलब्ध कराने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. सीबीआई कोयला मंत्रालय को जरूरी फाइलों की लिस्ट देगी और सरकार दो सप्ताह के अंदर यह बताएगी कि वो फाइल कहां हैं. अगर कोयला मंत्रालय फिर भी कहता है कि कुछ फाइलें गायब हैं तो सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा. अब तक केवल 37 कंपनियों की ही जांच हुई है और बाकी 132 कंपनियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि कोयला घोटाले की जांच दिसंबर तक पूरी होनी है. जिस तरह से फाइलें गायब हो रही हैं. मंत्रालय से जवाब नहीं मिल रहा है और जिस गति से जांच आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि दिसंबर तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी. इस बीच कोर्ट से जांच के लिए छह महीने का वक्त भी मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ-साफ मना कर दिया है और यह निर्देश दिया है कि जांच को दिसंबर तक खत्म करना ही है. मतलब यह कि कोर्ट कोयला घोटाले की जांच व सुनवाई दिसंबर तक खत्म करने का मन बना चुकी है. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि किसी भी कीमत पर इस मामले में सच्चाई को सामने लाया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी.

हिंदुस्तान की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट विश्वास की आखिरी उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो झूठे आरोप लगाए और जिसे राजनीतिक जवाब देकर टाला जा सकता है. अदातल तो सच का पता लगाती है. दूध का दूध और पानी का पानी करती है. अदातल फैसला करती है और जब तक फैसला नहीं देती, तब तक वह इशारा देती है. कोयला घोटाले में अब तक सुप्रीम कोर्ट से जो इशारे मिल रहे हैं, वह खतरनाक हैं. कहीं देश की जनता का यह दु:स्वप्न सच न हो जाए कि देश के प्रधानमंत्री को किसी घोटाले में जेल जाना पड़ जाए. अगर ऐसा होता है तो यह भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक पन्ना होगा. ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 27
दिल्ली, 09 सितंबर–15 सितंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

भूपेंद्र हुड्डा का अफसर प्रेम

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मशहूर है कि वे अपने पसंदीदा अधिकारियों को अपने करीब ही रखते हैं. ऐसे में जब उन्होंने प्रधान सचिव छत्तर सिंह को दिल्ली भेजा तो लोगों के लिए यह चौंकाने वाला फैसला था. 1980 बैच के आईएएस अधिकारी छत्तर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं. छत्तर सिंह को रिटायरमेंट के पहले ही तीन महीनों का सेवा विस्तार मिल चुका है. जो लोग हवा का रुख समझते हैं, उनका मानना है कि छत्तर सिंह को दिल्ली भेजकर केंद्र में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं. अब छत्तर सिंह के जाने के बाद हरियाणा के अधिकारियों में इस पद को पाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो जाएगा. कहा जा रहा है कि छत्तर सिंह के जाने के बाद हुड्डा अधिकारियों को उनके समपदस्थ रखना चाहते हैं और ये दो अधिकारी उनके करीबी एसएस ढिल्लन और के के खंडेलवाल हो सकते हैं. ■

निलंबन पर एकजुटता दिखाई

नेताओं द्वारा किए जा रहे निलंबन और ट्रांसफर आदेशों से आजिज आकर अधिकारी वर्ग अब सरकार से कुछ-कुछ अपनी असहमति भी जाहिर कर रहा है. इस सप्ताह के शुरू में प्रेक्षकों ने महसूस किया कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने इस इच्छा के साथ एकजुटता दिखाई है कि सब मिलकर सरकार से यह निवेदन करें कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों के निलंबन के अधिकार में बदलाव करे. जानकारों के मुताबिक, यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है. सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि निजी सचिव एस के सरकार से मिले. इस संदर्भ में उन्होंने सुधारों पर चर्चा की और सुझाव भी दिए. ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएसन के सचिव संजय के भूसरेड्डी के मुताबिक, सुझाव में यह कहा गया कि है कोई भी अधिकारी जिसका निलंबन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, उस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को नेताओं की ओर से कोई आश्वासन मिल पाएगा? ■

केरल में बाबुओं की कमी

तिरुवनंतपुरम में आईएएस अधिकारियों की कमी हो गई है. मुख्य सचिव ए के भारत भूषण के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि यहां से ज्यादातर अधिकारी डेपुटेशन पर जा रहे हैं. हालात को देखते हुए दो मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानंदन और वित्त सचिव वी पी जॉय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को भी वापस बुलाने पर विचार कर रही है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और अवधि पूरा होने के बाद भी लौट नहीं रहे हैं. अब केरल सरकार राज्य कैडर से जुड़े अधिकारियों को तभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजेगी, जब उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी उपलब्ध हो. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

जी मोहन अगले इस्पात सचिव होंगे

1979 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस जी मोहन कुमार अगले इस्पात सचिव होंगे. इसे लेकर कई दिनों से अटकले लग रहीं थी. मोहन कुमार फिलहाल जल संसाधन मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं. यह पद स्वर्गीय 1979 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस एस मचेन्द्रनाथन की जगह खाली हुआ था.

शेफाली संस्कृति मंत्रालय से जुड़ सकती हैं

1985 बैच की आईआरएस शेफाली शाह के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त होने की संभावना है. उनको मंत्रालय एक नया पद बनने के कारण नियुक्त किया गया है.

संजय गृह मंत्रालय में सयुक्त सचिव होंगे

1984 बैच के आईआरएस संजय कुमार मिश्रा गृह मंत्रालय में सयुक्त सचिव के रुप में कार्यभार संभाल सकते हैं. मिश्रा वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में (विदेशी कर और कर अनुसंधान) संचुक्त सचिव हैं. वे 1984 बैच के बिहार कैडर के आईएएस दीपक कुमार की जगह लेंगे.

संजीव मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो सकते हैं

1988 बैच के आईसीएस संजीव मिश्रा गृह मंत्रालय के तहत निदेशक, वित्त राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नियुक्त हो सकते हैं. संजीव 1982 बैच के आईडीएस टी एस कृपानिधि के जगह यह पद संभालेंगे.

दर्शन कोलंबो उच्चायोग में होंगे

1995 बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस दर्शन सिंह कोलंबो (श्रीलंका) में जल्द ही भारतीय उच्चायोग में काउंसलर के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली को बम धमाकों से दहलाने की ख्वाहिश रखने वाला भटकल हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों और बिहार पुलिस को पिछले कुछ महीनों से बेहद शातिराना तरीके से चकमा देने में कामयाब रहा. जब ख़ुफ़िया एजेंसियों को इस बात की खबर मिली कि यासीन भटकल बिहार–नेपाल सीमा पर देखा गया है और उसके कहीं आस–पास रहने की ही खबर है, तब महीने भर से सेंट्रल एजेंसी की टीमें बॉर्डर पर यासीन की टोह में लग गईं.

गिरफ्त में आतंकी

सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी से बचता रहा भटकल

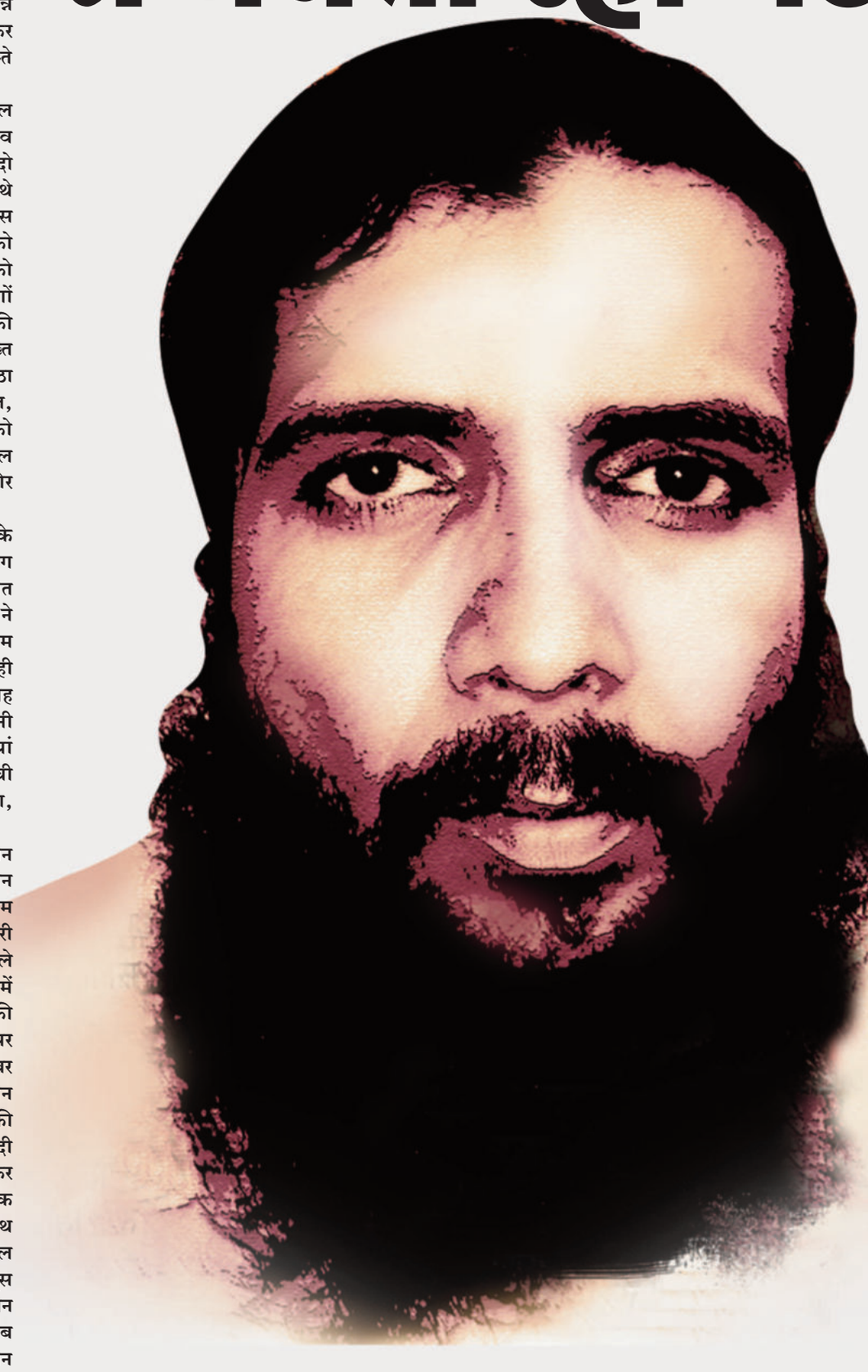

आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी से देश की सुरक्षा एजेसियां और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बेहद उत्साहित हैं, लेकिन अगर भटकल की सात साल की जेहादी ज़िन्दगी और उसके द्धारा की गई दहशतगर्दी पर नज़र डालें तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली और उनकी कुशलता पर कई सवाल खड़े होते हैं.

रूबी अरुण

यासीन भटकल के पकड़े जाने का श्रेय लेती और एक–दूसरे की पीठ थपथपाती खुफिया एजेंसियों आईबी, एनआईए और एसएसबी के अधिकारी इस बात पर खामोश हैं कि पहले भी कई बार पकड़े जाने के बावजूद यासीन भटकल की शिनाख्त बतौर आतंकवादी क्यों नहीं हो पाई थी? बार–बार यासीन भटकल अलग–अलग नामों से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने में सफल क्यों हो जाता था? भटकल पिछले काफी समय से दरभंगा में रह रहा था. उसने वहां शादी भी की. फिर भी बिहार पुलिस को उसके बारे में कोई भी जानकारी पहले हासिल क्यों नहीं हो पाई, जबकि दरभंगा में ही रहते हुए भटकल ने कई आतंकी वारदातों को देश के विभिन्न हिस्सों में अंजाम दिया. यासीन भटकल हकीम बनकर दरभंगा में छिपा रहा और यहीं से वह नेपाल के रास्ते नकली नोटों का कारोबार चलाता रहा.

दरअसल, यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल न होने, एक–दूसरे से सूचनाएं साझा न करने और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है. जिस आतंकी पर देश भर में दो दर्ज़न से ज्यादा बम धमाकों का आरोप हो, जिसके माथे डेढ़ सौ लोगों के खून का इलज़ाम हो और जिस पर दस लाख रुपयों का इनाम हो, ऐसे कुख्यात आतंकवादी को हमारे देश की पुलिस नहीं पहचानती. सुरक्षा एजेंसियों को उसकी निशानदेही नहीं मिलती, जबकि वह आम लोगों की तरह मज़े में ज़िन्दगी गुजारता है और हिन्दुस्तान की खुफिया एजेंसियों और राज्यों की पुलिस उसकी शिनाख्त तक नहीं कर पातीं. हमारे इसी कमज़ोर तंत्र का फायदा उठा कर भटकल दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर आदि जगहों पर बम धमाकों को अंजाम दे आता था. सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल जाता था और वारदात के बाद खुफिया एजेंसियां लकीर पिटती रह जाती थीं.

यासीन भटकल चार साल पहले कोलकाता पुलिस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था. दिसंबर 2009 में एक महिला की शिकायत पर नकली नोटों के कारोबार के एक मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया. उस समय यासीन ने अपना नाम कार्तिक मलिक बताया और अपने को कोलकाता का ही निवासी बताया था और इसी आधार पर चकमा देकर वह भाग निकला था. समय–समय पर यासीन भटकल अपनी पहचान बदलता रहा और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां धोखा खाती रहीं. जब जनवरी 2010 में भटकल ने रांची से अपना पासपोर्ट निकलवाने के लिए आवेदन किया था, तो उसमें उसने अपना नाम अंजार हुसैन लिखा.

कोलकाता पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद यासीन भटकल काफी समय तक दरभंगा में रहा था. इस दौरान नेपाल भी उसका आना–जाना रहा. दिल्ली को बम धमाकों से दहलाने की ख्वाहिश रखने वाला भटकल हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों और बिहार पुलिस को पिछले कुछ महीनों से बेहद शातिराना तरीके से चकमा देने में कामयाब रहा. जब ख़ुफ़िया एजेंसियों को इस बात की खबर मिली कि यासीन भटकल बिहार–नेपाल सीमा पर देखा गया है और उसके कहीं आस–पास रहने की ही खबर है, तब महीने भर से सेंट्रल एजेंसी की टीमें बॉर्डर पर यासीन की टोह में लग गईं. नेपाल बॉर्डर पर यासीन के होने की निशानदेही फसीह महमूद ने की, जिसकी गिरफ्तारी सऊदी अरब में हुई थी और जिसे एनआईए की टीम भारत लेकर आई थी. फसीह महमूद यासीन के पैत्रिक गांव कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है और उसने यासीन के साथ पढ़ाई की है. फसीह की दी गई सूचना के बाद सेंट्रल एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से यासीन को ट्रेस करना शुरू किया, पर मुश्किलें यहां भी थीं, क्योंकि यासीन मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था. उसे जब ज़रूरत होती, वह पीसीओ से फोन करता और पहचान छुपाने में तो इसे महारथ हासिल है ही. इसलिए खुफिया एजेंसियां और पुलिस तो दूर, आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन में भी कोर ग्रुप को छोड़कर इसके असली नाम की खबर नीचे काम करने वाले आतंकियों को नहीं होती थी, जिसका सबूत है 26 जुलाई, 2008 का अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट. आईएम ने जब अहमदाबाद को अपना निशाना बनाने की ठानी तो इसके कमांडर यासीन भटकल ने इस खास ऑपरेशन के लिए अपना नाम शाहरुख रख लिया. खास बात ये थी कि आईएम की तरफ से किए गए तब तक के सबसे बड़े धमाके को अमलीजामा पहनाने वाले ज्यादातर आतंकियों को पता नहीं था कि शाहरुख के नाम से इस ऑपरेशन में सक्रिय शख्स यासीन भटकल है. जब इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने आईएम से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो उन्होंने इस ऑपरेशन के सरगना के तौर पर शाहरुख का ही नाम लिया. अहमदाबाद पुलिस इस बात पर माथापच्ची करती रही कि आखिर ये शाहरुख नाम का शख्स है कौन, जिसने 26 जुलाई, 2008 को शहर के 18 अलग–अलग जगहों पर धमाके करवा कर 58 लोगों की जान ले ली. शाहरुख नाम यासीन भटकल का ही था. इसका खुलासा तब हुआ, जब दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के बाद आईएम का आतंकी सैफ पुलिस की पकड़ में आया. सैफ ने पुछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यासीन भटकल ने ही अपना नाम शाहरुख रख लिया था. यासीन भटकल जब दिसंबर 2009 में कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में आया था, तब भी वह अपने को बुल्ला कार्तिक मलिक बताकर पुलिस को झांसा देने में कामयाब रहा और फिर जमानत लेकर निकल भागा. यही नहीं, बीस जनवरी 2010 को जब उसने पासपोर्ट के लिए रांची में आवेदन किया, तो उस आवेदन पत्र में अपना नाम लिखा अंजार हुसैन. ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि यासीन का असली नाम मोहम्मद अहमद सीदीबप्पा है. यासीन भटकल विस्फोटकों के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा करने में भी अहम भूमिका निभाता है. मसलन, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के लिए जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, उसे यासीन भटकल ने ही मंगलौर में अपने आतंकी साथियों को मुहैया कराया था. इसका खुलासा भी सैफ से पूछताछ के दौरान हुआ.

यासीन शातिराना और खौफनाक चाल चलता रहा और हमारी जांच और सुरक्षा एजेंसियां आपस में झगड़े करती रहीं. वह मुंबई के भायखला इलाके में एटीस कार्यालय के ठीक बगल में किराए के कमरे में महीने भर रह कर मुंबई के दादर, ओपेरा हाउस और झवेरी बाज़ार में धमाके करवाता रहा और मुंबई तथा दिल्ली पुलिस आपसी खींचतान में उलझी रही.

13 फ़रवरी, 2010 को यासीन भटकल ने पुणे के जर्मन बेकरी में विस्फोट करवाया. 17 तारीख को कर्नाटक पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया. यासीन की तस्वीरें सीसीटीवी के फुटेज से भी मिलीं. फिर भी जांच एजेंसियों की लापरवाही की इन्तहा ये रही कि यासीन ने मुंबई में कई जगहों पर बम विस्फोट कराए. वह दुबारा फिर पुणे गया और वहां के जंगली महाराज रोड पर 12 अगस्त, 2012 को तीन अलग–अलग जगहों पर बम धमाके करवाए. 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए बम धमाकों में भी भटकल का हाथ होने के सबूत मिले हैं. इसके बावजूद यासीन भटकल बेरोक–टोक अपने आतंक के धंधे को अंजाम देता रहा.

हमारी सुरक्षा एजेंसियों की आपसी खींचतान का नतीज़ा देखिए कि दिल्ली पुलिस ने लगभग डेढ़ साल पहले भटकल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली थी. इस काम के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई भी पहुंच चुकी थी. पर अंतिम समय में मुंबई पुलिस ने एक छोटे गुर्गे नाकि को पकड़ लिया, जिससे यासीन सतर्क हो गया और फरार हो गया. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया.

अब, जब यासीन गिरफ्तार हो चुका है, तब उन सभी राज्यों के बीच यासीन को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की होड़ लग गई है, जहां भटकल ने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था. उम्मीद की जा रही है कि भटकल से होनेवाली पूछताछ में कई और भी वारदातों के खुलासे होंगे तथा दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकियों को भी पकड़ने में मदद मिलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का सह–संस्थापक आतंकी यासीन भटकल पूछताछ के दौरान ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है. उसने अपने भारत आने के मकसद के बारे में मुंह नहीं खोला है. हां, उसने इतना ज़रूर बताया है कि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है. जब से वह गिरफ्तार हुआ है, लगातार भारत के खिलाफ ज़हर उगल रहा है. उसका कहना है कि अभी इंडिया को बाद में पता चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है. भटकल की इस धमकी को अनायास नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके खतरनाक मंसूबों को देखकर आने वाले दिनों में किसी बड़ी साजिश से इन्कार नहीं किया जा सकता. हालांकि अभी वह एनआईए की रिमांड में रहने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इस दरम्यान खुफिया एजेंसियों को उन आतंकियों की धरपकड़ में जरूर मदद मिलेगी, जो देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए खतरा बन चुके हैं. साथ ही पाकिस्तान में फल–फूल रहे आतंकी संगठनों की भारत के खिलाफ चल रही प्लानिंग के बारे में भी पता चल सकेगा, क्योंकि भटकल के सीधे ताल्लुक लश्कर–ए–तैयबा से है, जिसका पूर्व कमांडर मोहम्मद हाफिज़ सईद है. खुफिया अधिकारियों के अनुसार, नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन का गठन लश्कर–ए–तैयबा के भारत में फ्रंट के रूप में किया था. भटकल पहले सिमी का सक्रिय सदस्य भी था, लेकिन सिमी के कुछ सक्रिय कमांडरों के पकड़े जाने के बाद भटकल ने उससे नाता तोड़ दिया और अपने खुद के संगठन आईएम का गठन किया. यह संगठन साइकिल या स्कूटर के जरिये टिफिन में बम रख कर धमाके करने में एक्सपर्ट है. भारत में नये आतंकियों की भर्ती और नये हमलों की साजिशों को वही अंजाम तक पहुंचाता था. उसकी तलाश 12 राज्यों की एटीएस को थी, लेकिन वह पकड़ से बाहर था. सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह एक छलावा बन गया था. यासीन भटकल बाकायदा ट्रेंड इंजीनियर है, लेकिन वह आधुनिक तकनीक से दूर ही रहता था. दूसरे आतंकियों की तरह वह कम्प्यूटर–लैपटॉप या मोबाइल कम ही इस्तेमाल करता था. उसका एक और सिद्धांत था. देश के अलग–अलग हिस्सों में घूमो और आतंक के नेटवर्क में शामिल लोगों से सीधी बात करो. इतना ही नहीं, यासीन वेष बदलने में भी माहिर था. शायद यही वजह थी कि तमाम आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने वाली सुरक्षा एजेंसियां उसे अपने जाल में नहीं फंसा पा रही थीं. ■

> अगर सरकार या पार्टियों द्वारा सस्ता प्याज बेचना किसी तरह का प्रभाव डाल सकता है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी भी सस्ते दाम पर प्याज बेच रही हैं. प्याज फैक्टर दिल्ली की सत्ता पर क्या असर डालता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजधानी में महंगा प्याज ही अकेला मुद्दा नहीं है. दिल्ली की जागरूक जनता शीला सरकार से पिछले पंद्रह सालों का हिसाब मांग सकती है.

विधानसभा चुनाव

दिल्ली की जनता किसे चुनेगी निज़ाम

इस साल के नवंबर में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है. कांग्रेस पंद्रह सालों से दिल्ली की सत्ता पर विराजमान है. शीला दीक्षित और उनकी पार्टी चौथी बार दिल्ली में वापसी का दावा कर रही है तो बीजेपी शीला से गद्दी छीनकर वापसी के प्रयास में लगी है. बेतहाशा बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त हैं तो पिछले वर्षों में हुए बेलगाम भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की छवि पर कालिख भी लगा दी है. आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहने वाले निचले वर्ग के लोगों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास कर रही है. इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली-पानी और विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना है. क्या शीला दीक्षित वापसी करेंगी? क्या भाजपा सत्ता में आएगी? या जनता केजरीवाल पर भरोसा जताएगी?

कृष्णकांत

प्याज के बढ़े दामों को मुद्दा बनाकर चौदह साल पहले भाजपा से सत्ता छीनने वाली शीला दीक्षित की सरकार ठीक चुनाव से पहले उसी मुसीबत में फंस गई है. प्याज की कीमतों को नियंत्रित न कर पाने के बाद शीला सरकार दिल्ली में स्टाल लगाकर सस्ते दामों में प्याज बेच रही है. लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता सिर्फ अस्सी रुपये की जगह चालीस रुपये में प्याज बेचने के नाम पर वोट देगी? अगर सरकार या पार्टियों द्वारा सस्ता प्याज बेचना किसी तरह का प्रभाव डाल सकता है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी भी सस्ते दाम पर प्याज बेच रही हैं. प्याज फैक्टर दिल्ली की सत्ता पर क्या असर डालता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजधानी में महंगा प्याज ही अकेला मुद्दा नहीं है. दिल्ली की जागरूक जनता शीला सरकार से पिछले पंद्रह सालों का हिसाब मांग सकती है. महंगाई और भ्रष्टाचार केंद्र के साथ हर राज्य की शाश्वत समस्या है. बिजली, पानी, बढ़ते अपराध, स्वच्छ प्रशासन आदि मुद्दों पर भी जनता अपना मत व्यक्त कर सकती है. अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली का मतदाता इन सभी मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखकर वोट करेगा या फिर इन्हें दरकिनार कर देगा? इन सवालों के बीच यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन कार्यकाल में जिन मुद्दों को आगे करके चुनाव जीता, उनपर कितना काम किया? अन्ना आंदोलन की परिणति से निराश होकर आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे. वे तमाम भ्रष्टाचार समेत तमाम मसलों पर काफी आक्रामक भी हैं. सभी पार्टियों की घोषणाओं से लगता है कि उनके मुद्दे लगभग एक जैसे होने वाले हैं.

बिजली होगा प्रमुख मुद्दा

यह मजेदार है कि देश की राजधानी समेत पूरे देश में साठ-पैंसठ सालों से हर चुनाव में बिजली-पानी ही मुख्य मुद्दा होता रहा है और यह समस्या सुरसा के मुंह की तरह साल-दर-दर बढ़ती ही रही है. पार्टी बनाने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतों को मुद्दा बना दिया था. केजरीवाल ने महंगी बिजली का विरोध करते हुए लोगों से बिल न भरने की अपील की. जिन लोगों के कनेक्शन बिल न भरने के कारण काट दिए गए, उसे केजरीवाल ने खुद जाकर जोड़ा. उनका वादा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे बिजली के दाम आधे कर देंगे और चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति करेंगे. अब स्थिति यह है कि आप के साथ-साथ भाजपा और कांग्रेस ने भी बिजली के मुद्दे को पहली प्राथमिकता में रखा है. भाजपा की दिल्ली इकाई ने भी एलान किया है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो बिजली की कीमतों में 30 फीसदी की कमी कर देगी. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी किसी भी रैली में दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर अपना बखान करने से नहीं चूकतीं. उनका कहना है कि दिल्ली में बिजली की खपत सबसे ज्यादा है. सरकार प्रति व्यक्ति 1450 यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति कर रही है. शीला ने सीमित घरेलू बिजली खर्च में सब्सिडी देकर जनता को लुभाने की कोशिश भी की है.

सबकी सूची में है भ्रष्टाचार और महंगाई

अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्तारूढ़ शीला सरकार को भाजपा और आप दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार और महंगाई पर घेरने की कोशिश करेंगी. कॉमनवेल्थ घोटाला, शीला पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने संबंधी लोकायुक्त रिपोर्ट, जनता से झूठा वादा करने को लेकर लोकायुक्त की नसीहत, बढ़ी प्याज की कीमतें, खाद्य वस्तुओं के बेतहाशा बढ़ते दाम आदि को लेकर शीला पर हमले होंगे तो सभी दल अपने-अपने तरीके से लुभावने वादे करेंगे. हालांकि, विभिन्न सर्वेक्षणों में शीला दीक्षित ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी है, लेकिन पिछले वर्षों में कांग्रेस पार्टी के खाते में बेहताशा भ्रष्टाचार ही दर्ज हुए हैं. भाजपा भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली और सुशासन का मुद्दा आगे करके चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुकी है. आप पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे अन्ना आंदोलन से ही निकलकर अस्तित्व में आई है. इसलिए अगले चुनाव में भ्रष्टाचार पर काफी शोर-शराबा होने के आसार हैं. केजरीवाल ने तो काफी पहले ही 71 चुनावी मेनीफेस्टो की घोषणा कर डाली थी. राजधानी के राजनीतिक गलियारे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही इस पार्टी का कहना है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र का अलग मेनीफेस्टो तैयार करेगी ओर एक मेनीफेस्टो पूरी दिल्ली का होगा. आप ने भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ अवैध कालोनियों को मुद्दा बनाया है. केजरीवाल का कहना है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे दिल्ली की सभी 1649 मलिन बस्तियों को एक साल के भीतर नियमित कर देंगे. भाजपा ने कहा है कि शहर की छह सौ से ज्यादा मलिन बस्तियों में रह रहे परिवारों को फ्लैट मुहैया कराएगी. जाहिर है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के मुद्दे भी आप से ज्यादा अलग नहीं रहने वाले हैं. कांग्रेस अपनी पिछली तीन कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर दोबारा जनादेश मांगेगी. पूरी दिल्ली में जगह-जगह होर्डिंग लगाकर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है.

मोदी भी होंगे मुद्दा

अगले चुनावों में नरेंद्र मोदी भी एक अहम मुद्दा हैं. भाजपा आगामी सभी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार को खत्म करने और विकास और सुशासन मुहैया कराने के लिए मोदी को कए विकल्प के तौर पर पेश करेगी. वह अभी से मोदी मॉडल का शोर मचा रही है. इसमें पार्टी को कोई सफलता मिलेगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी का दमखम अभी तक गुजरात के बाहर देखने को नहीं मिला है. हालांकि, भाजपा मोदी और उनके मॉडल को अंतिम विकल्प के रूप में पेश करेगी तो कांग्रेस मोदी को सांप्रदायिक करार देकर भाजपा को घेरने के साथ मुस्लिम मतदाताओं पर दांव चलेगी. यह कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली विधानसभा सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है. इसके परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव के भी समीकरण तय करेंगे.

किंगमेकर बन सकते हैं केजरीवाल

दिल्ली मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा का गढ़ है और अब तक मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों में होता रहा है. लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में प्रवेश कर रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है. दिल्ली में यह पहली बार है, जब किसी पार्टी की स्थापना के बाद इतने कम समय में इतनी तेजी से लोकप्रियता मिली हो. चुनावी सर्वे तो यहां तक कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है और यदि केजरीवाल सत्ता में नहीं आते हैं तो किंगमेकर की भूमिका में जरूर रहेंगे. अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए यह पहला मौका है जब वह किसी चुनाव में भाग ले रही है. इसलिए उनकी जीत-हार उनका भविष्य तय करेगी. इस अस्तित्व की लड़ाई में केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली के गली-कूचों में भारी संख्या में कार्यकर्ता तैयार कर लिए हैं और वे भाजपा-कांग्रेस से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. जबसे केजरीवाल ने पार्टी बनाई है, वे लगातार गली-मोहल्लों में सभाएं कर रहे हैं. उनके कार्यकर्ता लोगों को अपना एजेंडा समझा रहे हैं. वे बदलाव के नाम पर वोट मांग हर रहे हैं. उनकी यह अपील जनता कितना सुनती है, यह चुनावी नतीजे बताएंगे. क्योंकि कोई पार्टी जो अभी-अभी गठित हुई है और लोकप्रिय होने की प्रक्रिया में है, उसके बारे में अभी से अंतिम निर्णय देना नासमझी होगी.

चुनावी नारे में आया आम आदमी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी का नारा लग रहा है. दिल्ली के बाहरी इलाकों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से मुद्दे तो पहले भी चुनाव में उठते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली के निचले तबके और आम जनता से गहरे तौर पर जुड़े मसलों को उठा रही है. वह आम आदमी का नारा दे रही है. कांग्रेस खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर अपने को निचले तबके का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है तो भाजपा भी यह बताने की कोशिश कर रही है कि उसे आम आदमी की चिंता है. इन राजनीतिक शोर-शराबों के बीच आम आदमी क्या सोचता है, यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है.

मिनी लोकसभा चुनाव

राजधानी होने के कारण दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है. यहां हर लगभग हर राज्यों के लोग रहते हैं. इसलिए दिल्ली चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव की झलक होंगे. जो पार्टी दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में कामयाब होगी, उसे लोकसभा में भी बढ़त हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है. भाजपा पिछले तीन कार्यकाल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और दो कार्यकाल से केंद्र में विपक्ष में बैठ रही है. दिल्ली समेत पांच राज्यों में होने वाले चुनाव यदि भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए आत्मविश्वास हासिल होगा. वहीं कांग्रेस अपनी धूमिल छवि के बावजूद भी अगर इन राज्यों में सत्ता में आती है तो वह लोकसभा में लोकप्रिय पार्टी के तौर पर दावा ठोंकेगी. जबकि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके पक्ष में देश भर में अच्छा संदेश जाएगा. लेकिन वास्तव में क्या होगा, यह जनता तय करती है, जिसके लिए हमें अभी कुछ महीनों का इंतजार करना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

मध्य प्रदेश कांग्रेस में काफी समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया को संगठन की कमान सौंपे जाने की मांग हो रही थी, लेकिन सिंधिया की गंभीर रुचि न होने के वजह से यह जिम्मेदारी आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के कंधों पर आई, लेकिन न तो संगठन में उनका अपेक्षित प्रभाव बन सका, न ही पार्टी में लाइलाज गुटबाजी का ठोस निदान निकल पाया.

मध्य प्रदेश

बिहार

मोदी-नीतीश बैर का असर किसानों पर

नरेंद्र मोदी के नाम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कदर भड़कते हैं कि वे बिहार पर मोदी की परछाईं भी नहीं पड़ने देना चाहते. नौ-दस सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात एग्रीकल्चरल समिट-2013 में बिहार के चुने हुए किसानों को हिस्सा लेना था, लेकिन बिहार सरकार ने इससे हाथ खींच लिए और किसानों को गांधीनगर भेजने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया. ऐसा करके नीतीश ने भाजपा को बैठे-बिठाए एक मुद्दा दे दिया है.

सरोज सिंह

बिहार में दूसरी हरित क्रांति लाने का संकल्प लेने वाले किसान इन दिनों अजीब उलझन में फंस गए हैं. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार व नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रंजिश की कीमत उन्हें अपने लहलहाते खेतों में भी चुकानी होगी. हर किसी को याद होगा कि लालू प्रसाद यादव की आलोचना का जब भी मौका आता था तो नीतीश कुमार यह बात जरूर कहते थे कि लालू प्रसाद विकास से वैसे ही भड़कते हैं जैसे कोई सांड़ लाल कपड़ा देखकर भड़कता है. अब नीतीश कुमार के आलोचक खासकर भाजपाई यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर वैसे ही भड़कते हैं जैसे कोई सांड़ लाल कपड़ा देखकर भड़कता है. यह बात उन दिनों इसलिए कही जा रही है कि नौ व दस सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात एग्रीकल्चरल समिट-2013 का आयोजन हो रहा है. इसमें देश भर के चुने हुए किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक के अलावा गुजरात में इस क्षेत्र में हुए सफल प्रयोग से रूबरू कराने का कार्यक्रम है. इसके अलावा जाने माने कृषि वैज्ञानिक व विशेषज्ञ किसानों को सफलता का मंत्र देंगे. नरेंद्र मोदी ने समिट में आने वाले किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का भी फैसला किया है. इसी कड़ी में बिहार के भी 76 किसानों को सम्मानित किया जाना था. ये ऐसे किसान हैं जिन्हें बिहार सरकार भी सम्मानित कर चुकी है. इन किसानों को चुनने और भेजने का जिम्मा बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार-प्रशिक्षण संस्थान को सौंपा गया था. संस्थान इस काम में लग भी गया था. कृषि विभाग से भी सहयोग मिल रहा था, पर अचानक यह प्रकिया रोक दी गई और बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए.

ऐसा क्यों हुआ इसे समझने में लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. बिहार सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक रंग चढ़ना था और वह तेजी से चढ़ने लगा. सुशील मोदी कहते हैं कि यह विचार के स्तर पर दिवालियापन का नमूना है. लगता है सरकार अब बिहार के लोगों के गुजरात जाने पर भी रोक लगा देगी. भाजपा अपने स्तर से किसानों को गुजरात भेजेगी. भाजपा के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि किसानों को गुजरात नहीं भेजना यह साबित करता है कि बिहार सरकार मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है. इस तरह के आयोजनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. देशभर के प्रगतिशील किसान इस समिट में जा रहे हैं. किसी राज्य सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर नीतीश सरकार को पता नहीं कौन सा डर सता रहा है. गिरिराज सिंह कहते हैं कि यह गलत परंपरा की शुरुआत है. भाजपा ने अब अपने स्तर से किसानों को भेजने का फैसला किया है. किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जर्नादन शर्मा योगी कहते हैं कि भाजपा ने हरेक जिले में किसानों के चयन का काम शुरू कर दिया है. भाजपा किसान मोर्चा बिहार सरकार के अड़ियल रवैये का करारा जबाव देगा. योगी का कहना है कि किसानों को सरकार द्वारा न भेजना यह साबित करता है कि बिहार सरकार दूसरी हरित क्रांति लाने का बस नाटक कर रही है. किसान व राज्य आगे बढ़े, इसकी कोई चिंता सरकार को नहीं है. मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश सिंह भी मानते हैं कि बिहार सरकार केवल नरेंद्र मोदी का नाम आ जाने से ऐसे कदम उठा रही है. किसान वहां जाकर कुछ सीख कर ही आएंगे और बिहार का नाम ही रौशन करेंगे पर बिहार सरकार ऐसा नहीं चाहती है. धान की खेती में विश्व रिकार्ड बनाने वाले किसान सुमंत कुमार का कहना है कि राजनीति से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है. हम किसान तो चाहते हैं कि दुनिया में कृषि के क्षेत्र में कौन-कौन से नये रिसर्च हो रहे हैं, कौन-कौन सी नई तकनीक आ रही है, इन चीजों को जानें-समझें. भाजपा नेता अरविंद सिंह कहते हैं कि सुमंत को तो पंजाब सरकार भी सम्मानित कर चुकी है, पर इस समय तो बिहार सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई थी, पर अब गठबंधन टूटने की कीमत इन किसानों को चुकानी पड़ रही है. सिंह कहते हैं कि किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है. भाजपा यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है.

इस सारे विवाद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य की स्थिति अत्यंत गंभीर है. पिछले कुछ दिनों से बाढ़ का कहर भी तेज हो गया है. इसे लेकर सरकार चिंतित है. इससे निपटने के लिए कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों की बैठक आठ और नौ सितंबर को बुलाई गई है. ऐसे में किसानों को गुजरात भेजना संभव नहीं है.

राजनीतिक विश्लेशक बताते हैं कि सरकार की इस तरह कार्रवाइयों से किसानों को जो नुकसान हुआ, वह तो हुआ ही, राजनीतिक रूप से जदयू को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. किसान गुजरात जाते, वहां से कुछ सीख कर और सम्मानित होकर आते, इससे जदयू के राजनीतिक सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सरकार ने असहयोग का रवैया अपनाकर भाजपा को बैठे-बैठे एक मुद्दा दे दिया. भाजपा अब जिलों में किसान यात्रा निकालकर लोगों को यह समझाने में लग गई है कि नीतीश सरकार किसानों का भला नहीं चाहती है. भाजपा अब अपने स्तर से किसानों का चयन कर इन्हें गुजरात भेजने के काम में लग गई है. संदेश यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने किसानों का भी राजनीतिकरण कर दिया. अब तो यह कहा जाएगा कि सबौर में जो किसान गए, वे जदयू समर्थक हैं और जो गुजरात गए वे भाजपाई हैं. अब सवाल उठता है कि किसान करें तो क्या करें. बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि वे न तो सबौर जाऐंगे न गांधीनगर. अब कोई उन्हें ये तो बताए कि राजनीति की जो फसल नेता लोग उगाना चाहते हैं, इसमें उनका फायदा है और किसानों का नुकसान है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सबौर और गांधीनगर में कहां ज्यादा राजनीतिक फसल उगती है. यह भी हो सकता है कि दोनों जगह सूखा ही रहे. ■

मध्य प्रदेश

क्या सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल पाएंगे?

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में दो बार भाजपा से पटखनी खाने वाली कांग्रेस पार्टी भीतर की गुटबाजियों से निजात पाकर एकजुटता प्रदर्शित करने में लग गई है. ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान दी गई है तो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी कमलनाथ ने संभाली है. अटकलें हैं कि यदि पार्टी को बहुमत मिलता है तो सिंधिया मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार होंगे, साथ में यह सवाल भी है कि कार्यकर्ताओं से कटकर रहने वाले सिंधिया क्या कांग्रेस की कमान संभाल सकेंगे?

अरविंद वर्मा

लंबे समय से जबर्दस्त गुटबाजी की वजह से पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा के हाथों करारी हार झेलती आ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आखिरकार पार्टी में प्रभावी गुटों में न सिर्फ एकजुटता का फार्मूला ढूंढ लिया, बल्कि इसे अमलीजामा पहनाने की कवायदें भी शुरू कर दी हैं. इन कवायदों के शुरुआती क्रम में गुटों में विभाजित पार्टी नेताओं के बीच परस्पर एकता का प्रदर्शन किया जाना है. ऐसे में प्रमुख नेताओं मसलन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, सुरेश पचौरी एवं अजय सिंह राहुल को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. ये सभी मिलकर दो कार्यकाल से सत्ता पर काबिज भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोकने की कवायद करेंगे. चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है तो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी कमलनाथ ने संभाली है. विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने का काम सुरेश पचौरी के जिम्मे आया है. जबकि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने का दायित्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को दिया गया है. सर्वविदित है की मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के नाम पर कार्यकर्ताओं में निचले स्तर तक गुटबाजी और इसके चलते पार्टी की खस्ता हालत की शिकायतें आम हैं. यह सब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे के समय भी उजागर हो चुका है. इसी का नतीजा है कि प्रदेश के प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद के स्थान पर मोहन प्रकाश को नियुक्त किया गया और अब पार्टी में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जगह-जगह सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. आयोजनों का मकसद कार्यकर्ताओं तक एकजुटता का संदेश पहुंचाना है.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पार्टी का एक धड़ा काफी समय से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश संगठन की कमान सौंपे जाने हेतु दबाव बना रहा था. इस मामले में संभवत: सिंधिया की भी गंभीर रूचि नहीं रही, लिहाजा यह जिम्मेदारी आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के कंधों पर आई. लेकिन न तो संगठन में उनका अपेक्षित प्रभाव बन सका, न ही पार्टी में लाइलाज गुटबाजी का ठोस निदान निकल पाया. इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने के प्रयासों के सिलसिले में नित नये फार्मूलों की खोजबीन भी जारी रही. आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सिंधिया को बतौर मुख्यमंत्री पेश किए जाने की भी मांग उठी. दिग्विजय सिंह ने भी इस पर अपनी सहमति दी, लेकिन खुद सिंधिया आदिवासी मुख्यमंत्री की हिमायत में कांतिलाल भूरिया का नाम लेने लगे. प्रदेश में पार्टी नेतृत्व को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला. पार्टी का आलाकमान भी मप्र में किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं रहा, न ही इनमें से किसी में अपनी दिलचस्पी जाहिर की. राज्य कांग्रेस में जारी गुटबाजी को लेकर पार्टी जो कमजोरियां अनुभव करती आ रही थी, इससे निजात पाने की कोई पुख्ता तरकीब तब भी नहीं मिल पाई. बस पार्टी के आला नेताओं को बार बार एक मंच पर प्रस्तुत होने और एकजुटता दिखाने संबंधी ऊपरी निर्देश प्राप्त होते रहे. इन निर्देशों के मुताबिक ऐसे श्रंखलाबद्ध आयोजनों का दौर जारी है.

इस फार्मूले पर कमलनाथ की ओर से यह भी कहा गया है कि जिस तरह वे दिग्विजय को आगे लाए थे, उसी तरह इस बार सिंधिया को आगे बढ़ाया है. कमलनाथ के इस बयान का अर्थ यह निकाला जा रहा है कि कमलनाथ समेत सिंधिया के करीबी चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की तो कमान संभालेंगे ही, यदि कांग्रेस बहुमत जुटाकर भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोकने में कामयाब हो गई तो मुख्यमंत्री का सेहरा भी सिंधिया के सिर बंधेगा. क्योंकि दिग्विजय एक बार फिर अपने को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बता रहे हैं. ऐसे में इसके भी संकेत नहीं हैं कि सिंधिया के नाम पर उन्हें कोई आपत्ति होगी. अब कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय अगर एक राय हो जाते हैं तथा सुरेश पचौरी इनसे बाहर नहीं जाते, तब कांतिलाल भूरिया हों या अजय सिंह अथवा अन्य नेता, सबके पास सिंधिया को समर्थन देने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता. इनमें सत्यदेव तो पहले ही सिंधिया के कसीदे पढ़ चुके हैं.

अब यह माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी संगठनात्मक एकजुटता का अग्रणी चेहरा बनाकर भाजपा की शिवराज बिग्रेड से विधानसभा में भिड़ने हेतु कमर कसकर तैयार हो रही है. परंतु जानकारों के मुताबिक यह सब फिर भी इतना आसान नहीं है. पार्टी को सत्ता से बाहर हुए दस साल का लंबा अरसा हो चुका है. पार्टी में कमलछाप कांग्रेसियों का खुलकर जिक्र होता है. इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने भाजपा से चुनावी मुकाबले के लिए सबसे बड़ी चुनौती है टिकटों का आबंटन. इस चुनौती से पार पाने को पार्टी को अभी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कहना मुश्किल है. जो टिकिट से वंचित रह जाएंगे वे दावेदार, उनके समर्थक तथा उनके आका क्या गुल खिलाएंगे, यह देखने की बात होगी. खुद अपनी जड़ें काटने की आदत के चलते इस स्थिति तक पहुंचने के बाद भी क्या ऐसे कांग्रेसी अपनी आदत से बाज आएंगे?

सिंधिया को राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का मुख्य चेहरा बनाए जाने से पार्टी का बड़ा तबका उत्साहित होने लगा है. इनमें ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो मानने लगे हैं कि टिकट आबंटन को लेकर पार्टी की चाहे जैसी प्रक्रिया चल रही हो, सिंधिया की अनुकंपा अब सबसे बड़ा संबल हो सकती है. इसके उलट बहुतेरे दावेदार अभी से यह मानने लगे हैं कि सिंधिया की सूची से पहले ही बाहर होने का नतीजा उन्हें टिकट मिलने की संभावना पर विपरीत असर डालेगा. कमलनाथ के करीबी उनमें और सिंधिया में तालमेल के बूते जुगाड़ तलाशने में जुटने लगे हैं. वहीं सुरेश पचौरी समर्थक अपने आका से मिलने वाले आगे के संकेतों के लिए प्रतीक्षारत हैं. अलबत्ता दिग्गी राजा के अनुयाइयों को उनके विधानसभा चुनावों से दूरियां दर्शाने के बाद भी उनके अचूक दांव-पेंचों का भरपूर आसरा है, जिनकी वजह से वे किसी भी समय पलड़े को अपने पक्ष में करने की कला के माहिर समझे जाते हैं.

ऐसे परिदृश्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर लाया गया फार्मूला भविष्य में भाजपा और शिवराज सिंह के मुकाबले हेतु कितना कारगर हो सकेगा, इसकी जांच परख राज्य के राजनीतिक क्षेत्रों और प्रेक्षकों के मध्य अभी से होने लगी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सिंधिया की अगुवाई को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के रूप में आदिवासी समाज का अपमान बता दिया है. हालांकि, कांग्रेस के आला नेता यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलने की स्थिति में चुने हुए विधायक ही अपना नेता चुनेंगे. कोई हेलीकॉप्टर से आकर इनका नेता नहीं बन सकेगा. प्रदेश में हर तरफ सिंधिया को कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की कमान दिए जाने पर कांग्रेस के भीतर और बाहर इन सवालों के उत्तर तलाशे जाने लगे हैं कि क्या सिंधिया आने वाले चुनाव में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की चुनावी नैया को सफलतापूर्वक पार लगा सकेंगे? ■

भाजपा और सपा दोनों ही दलों के नेता अपनी–अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. दोनों को ही लगता है कि परिक्रमा प्रकरण से नुकसान कम, फायदा ज्यादा होगा. भाजपा को मुस्लिम वोट हासिल करने से अधिक इस बात की चिंता है कि अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के पाले में न जाए. अगर अल्पसंख्यक कांग्रेस के पाले में गए तो भाजपा का खेल बिगड़ सकता है. भाजपा की सारी लड़ाई कांग्रेस से है, न कि सपा से, क्योंकि अंततः केंद्र में भाजपा–कांग्रेस ही मुख्य खिलाड़ी हैं.

लौटकर भाजपा मंदिर पर आई

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धारा पूरे देश से इतर चल रही है. यहां तक की उत्तर प्रदेश से अधिक पिछड़े कहे जाने वाले बिहार में भी अब विकास की बात होने लगी है, लेकिन लगता है कि देश के सबसे बड़े सूबे का रुतबा रखने वाला यूपी न बदला है, न बदलेगा. राजनीतिक गलियारे में जाति और संप्रदायवाद का जहर बोने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है.

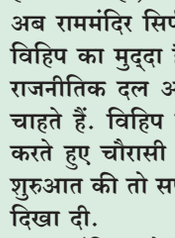

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सहयोगी अमित शाह को गुजरात से बुलाकर भाजपा ने विकास की राजनीति का जो ढिंढोरा पीटा था, विश्व हिंदू परिषद की चौरासी कोसी परिक्रमा के प्रस्ताव और उसपर हुई नौटंकी के बाद वह हवा हो गया है. अंततः इस सूबे की राजनीति उसी राममंदिर पर आकर टिक गई है, जो भाजपा को दो दशकों से खाद–पानी देता रहा है. हालांकि, अयोध्या में राममंदिर को लेकर भाजपा ने कभी चुनावी बढ़त भले ही हासिल की हो, लेकिन जनता अब हकीकत समझ चुकी है. अब राममंदिर सिर्फ भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विहिप का मुद्दा है. वह जनता का मुद्दा नहीं है. लेकिन राजनीतिक दल अभी भी राममंदिर का ही ढिंढोरा पीटना चाहते हैं. विहिप ने नई परंपरा की शुरुआत की कोशिश करते हुए चौरासी कोसी परिक्रमा प्रस्तावित करके इसकी शुरुआत की तो सपा और भाजपा ने मिलकर इसे हरी झंडी दिखा दी.

हालांकि, जो अयोध्या की पारंपरिक चौरासी कोसी परिक्रमा है, वह वैशाख में होती है, जो कि मई–जून में संपन्न हो चुकी है. बावजूद इसके विहिप ने यह परिक्रमा आयोजित की. इस मुद्दे पर पहले सपा के आलाकमान ने उनसे मुलाकात की और बाद में नाटकीय तरीके से उसपर प्रतिबंध लगा दिया और विहिप ने उसे मुद्दा बना लिया. विहिप ने तय समय पर परिक्रमा की शुरुआत करने की कोशिश की जिसे सपा सरकार ने भारी संख्या में गिरफ्तारियों के साथ विफल कर दिया. गनीमत रही कि विहिप की इस दिखावटी शहादत में जनता उसके साथ नहीं आई. पूरे नाटक की पटकथा सपा और विहिप ने मिलकर लिखी और विहिप कैडर तथा सरकारी मशीनरी ने उसे अंजाम दिया.

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धारा पूरे देश से इतर चल रही है. यहां तक की उत्तर प्रदेश से अधिक पिछड़े कहे जाने वाले बिहार में भी अब विकास की बात होने लगी है, लेकिन लगता है कि देश के सबसे बड़े सूबे का रुतबा रखने वाला यूपी न बदला है, न बदलेगा. राजनीतिक गलियारे में जाति और संप्रदायवाद का जहर बोने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है. धर्म यहां विकास में बाधा खड़ा करने का औजार भर है, जिसे हर राजनीतिक दल भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है. राजनीति के बाजार में जाति, धर्म और अपराध सब बिकाऊ हैं और समय देखकर इनकी बोली लगा दी जाती है. यहां एक बेतुके परिक्रमा के आयोजन, सांप्रदायिकता, अनर्गल बयानों, आतंकवाद आदि वोट बटोरू मुद्दों को लेकर ही नेताओं के बीच तलवारें खिंचती हैं और मीडिया भी इन मसलों को खूब हवा देता है. परंतु किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, बिजली–पानी–सड़क, भुखमरी, नारी उत्पीड़न, बलात्कार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर किसी भी मंच पर कभी गंभीर बहस देखने को नहीं मिलती. मीडिया भी कभी इन मुद्दों पर सरकार या नेताओं को असहज करने वाले रुख में नहीं दिखता.

वोट बैंक की राजनीति इस कदर हावी है कि वोट बटोरने के फेर में समाज में अस्थिरता फैलाने से भी किसी को गुरेज नहीं है. पक्ष–विपक्ष दोनों मिलकर वोट बैंक साधने की कोशिश में लगे हैं. नेताओं के बयानों में मौजूद विरोधाभास इसका पुख्ता प्रमाण है. विहिप की चौरासी कोसी परिक्रमा को ही लिया जाए. एक तरफ तो सपा सरकार कह रही थी कि विहिप की परिक्रमा धार्मिक नहीं राजनीतिक है. इससे प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता है तो दूसरी तरफ सपा नेता मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बयान दे रहे थे कि विहिप की इस यात्रा को किसी का भी समर्थन नहीं मिल रहा. सवाल यह है कि अगर विहिप की यात्रा फ्लाप थी तो इस पर रोक लगाकर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया गया. कई मौकों पर ऐसा लगा कि अखिलेश सरकार कह कुछ और रही थी, लेकिन उसे करना कुछ और था. परिक्रमा के पहले नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, उस दौरान विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया अयोध्या में थे. वे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगी. क्या सरकार का खुफिया तंत्र नाकारा है या फिर इसके पीछे की कोई सियासत थी.

मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कठघरे में सपा

सपा ने जिस मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए इस ड्रामे में सहभागिता की, उसी समुदाय के बुद्धिजीवी तबके ने इस पर सवाल खडा कर दिया. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़ी संस्था 'फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस' की बैठक में समाजवादी सरकार और इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव की नीयत पर संदेह व्यक्त किया गया. फोरम से जुड़े प्रोफेसर रजाउल्लाह खान ने यह कह कर चौंका दिया कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने विहिप की चौरासी कोसी परिक्रमा पर रोक लगाकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है. विहिप को अपनी यात्रा सुनियोजित तरीके से निकालने की इजाजत मिलनी चाहिए. सपा नेता और मंत्री आजम खान को प्रोफेसर साहब की बात शायद ही समझ आए, लेकिन रजाउल्लाह खान तो यही कहते हैं कि 200 साधुओं को परिक्रमा यात्रा में शामिल होना था, लेकिन सपा सरकार ने प्रतिबंध लगाकर पूरे देश का माहौल विहिपमय कर दिया. फोरम के सचिव जसीम मोहम्मद ने भी शक जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ मुलायम सिंह विहिप नेताओं से बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इसकी यात्रा पर पाबंदी लगाते हैं. यह नूराकुश्ती अब उजागर हो चुकी है. एक और प्रोफेसर हुमायूं मुराद का बयान भी अहम है. उनका साफ कहना था हिंदू समाज शांतिपूर्वक रहता है. अगर सपा सरकार पाबंदी नहीं लगाती तो परिक्रमा के लिए लोग मिलने मुश्किल हो जाते. वहीं प्रोफेसर शाहबुद्दीन ईराकी का कहना था धार्मिक अनुष्ठान मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है. इसलिए इस पर पाबंदी लगाने की बजाय सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए. कुछ ऐसे ही विचार प्रो मोहम्मद शाहिद और डॉ. फातिमा जोहरा के थे.

हिंदू–मुस्लिम वोटों का है पूरा गणित

उत्तर प्रदेश चौरासी कोसी परिक्रमा के आगे निकल चुका है. भाजपा और सपा दोनों ही दलों के नेता अपनी–अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. दोनों को ही लगता है कि इससे नुकसान कम फायदा ज्यादा होगा. क्योंकि इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा को मुस्लिम वोट हासिल करने से अधिक इस बात की चिंता है कि अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पाले में न जाए. अगर मुस्लिम कांग्रेस के पाले में गए तो भाजपा का खेल बिगड़ सकता है. भाजपा की सारी लड़ाई कांग्रेस से है, न कि सपा से, क्योंकि अंततः केंद्र में भाजपा–कांग्रेस ही मुख्य खिलाड़ी हैं. सपा–भाजपा दोनों का ही वजूद एक–दूसरे की मजबूती पर टिका है. इसीलिए दोनों दल एक–दूसरे को कोसते भी हैं और एक–दूसरे के लिए खाद–पानी का इंतजाम भी करते हैं. इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस, उसके साथ खड़ी रालोद और बसपा के पास हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था. इसलिए इनकी तरफ से अयोध्या का मैच फिक्स था जैसे बयान दिए जा रहे हैं. परंतु अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा की जगह कांग्रेस, बसपा, रालोद आदि होते तो क्या वे भी यही नहीं करते? मायावती ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की तो कांग्रेस परिक्रमा प्रकरण को सपा–भाजपा के बीच फिक्स मैच करार दिया. अच्छा होता कि कांग्रेस और बसपा प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूत आवाज उठातीं. विहिप और बजंरग दल के साथ भाजपा ऐसे मुद्दे उठा रही है, जिससे सामाजिक तानाबाना टूटे और अशांति पैदा हो. हम सभी को अयोध्या की जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने सांप्रदायिक तत्वों को पनाह नहीं दी और उनका सहयोग भी नहीं किया. उम्मीद की जा सकती है कि जब जनता की बारी आएगी तो वह सभी से हिसाब जरूर लेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मायावती ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की तो कांग्रेस परिक्रमा प्रकरण को सपा-भाजपा के बीच फिक्स मैच करार दिया. अच्छा होता कि कांग्रेस और बसपा प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूत आवाज उठातीं. विहिप और बजंरग दल के साथ भाजपा ऐसे मुद्दे उठा रही है, जिससे सामाजिक तानाबाना टूटे और अशांति पैदा हो.

विहिप आंदोलन से परेशान अयोध्यावासी

विहिप की चौरासी कोसी परिक्रमा आंदोलन से सपा और भाजपा भले ही राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में हों, परंतु यहां के कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचा है. बाहर से आने वाले पर्यटक व तीर्थयात्रियों का आवागमन बंद हो जाने से धर्मनगरी के सभी लोगों पर असर पड़ा है. ऐसी किसी स्थिति में पंडा-पुरोहितों को भी मिलने वाली धनराशि बंद हो जाती है, जिससे उन्हें अपना परिवार चलाना कठिन हो जाता है. हनुमानगढ़ी पर प्रसाद की दुकान करने वाले रामबाबू गुप्त कहते हैं कि आए दिन बंदिशों की मार झेल रहे अयोध्यावासियों का जीना दूभर हो गया है, अयोध्या सिर्फ राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बनकर रह गया है. अयोध्या का फायदा राजनीतिक दल तो उठा रहे हैं और स्थानीय बाशिंदों का रोजगार चौपट हो रहा है. यह सब कब तक चलता रहेगा, समझ में नहीं आता. ■

> शर्म की बात तो यह है कि सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो उनके लिए मूल शिक्षा की व्यवस्था उनकी मातृभाषा यानी उर्दू में करनी होगी, लेकिन यूपीए सरकार ने न तो उर्दू माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कहीं खोले हैं और न ही देश के उन प्राइवेट स्कूलों को तरजीही बुनियाद पर कोई विशेष सुविधाएं दी हैं, जहां पर उर्दू माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था है.

सच्चर रिपोर्ट का सच

मुसलमानों को धोख़ा दे रही है कांग्रेस

2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के सत्ता में आते ही रंगनाथ मिश्रा आयोग और अगले साल सच्चर कमेटी का गठन हुआ तो आशा जगी थी कि मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर कर उन्हें अन्य समुदायों के साथ विकास की दौड़ में शामिल किया जाएगा. मगर, यूपीए अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है, बावजूद इसके अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिमों की स्थिति आज भी बदतर हालत में है. रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट चौथी दुनिया के माध्यम से संसद में चर्चा का विषय बनी, इसके बावजूद सरकार इसे दबाए बैठी है. दूसरी ओर सच्चर रिपोर्ट क्रियान्वयन की जटिलताओं में गुम है. आखिर इन रिपोर्टों का क्रियान्वयन कौन करेगा. चौथी दुनिया पहली बार सच्चर रिपोर्ट की 76 अनुशंसाओं की विस्तृत समीक्षा आरंभ कर रहा है, जिससे मुस्लिमों की वास्तविक स्थिति और सरकार के झूठे दावों को समझने में मदद मिलेगी. चौथी दुनिया सच्चर कमेटी रिपोर्ट की वास्तविकता का क्रमवार विश्लेषण कर रहा है. इसी कड़ी में प्रस्तुत है पहला अंक...

डॉक्टर क़मर तबरेज़

भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का देश है. इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी भारत में बसती है. 2001 की मतगणना के अनुसार, यह देश की कुल आबादी का 13.10 प्रतिशत है. इनकी सामूहिक स्थिति बेहद ख़राब है और ये विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक पिछड़े हैं. स्वतंत्रता के बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइज़ेशन (एनएसएस–ओ) और गोपाल सिंह हाई पॉवर माइनॉरिटी पैनल व अन्य कुछ ग़ैर सरकारी रिपोर्टों से यह संकेत तो मिलता था, लेकिन इस संबंध में किसी आधिकारिक रिपोर्ट की कमी महसूस होती थी. लिहाज़ा 2004 में सत्ता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश में आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को जानने के लिए 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट मनमोहन सरकार को 17 नवंबर, 2006 को सौंप भी दी. हालांकि 2004 के अंत में भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस स्वर्गीय रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमिशन फॉर रिलिजियस एंड लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज) गठित किया गया, जिसने 21 मई, 2007 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सुपुर्द की. सच्चर रिपोर्ट को तो संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन मिश्रा आयोग रिपोर्ट सरकार की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि यह इधर–इधर उपलब्ध थी. यही कारण है कि चौथी दुनिया ने जब इसे प्रकाशित किया तो यह संसद में चर्चा का विषय बनी, लेकिन अफसोस की बात है कि यह आज भी ठंडे बस्ते में है. दूसरी ओर सच्चर कमेटी रिपोर्ट का हाल भी अच्छा नहीं है. अब जबकि यूपीए सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के पूरे होने में कुछ महीने ही शेष हैं, ऐसे में न तो सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को लागू किया है और न ही ऐसा कोई बड़ा काम किया है, जिससे यह साबित होता हो कि मुसलमानों के पिछड़ेपन को कम करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

शर्म की बात तो यह है कि जिस सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो इनके लिए मूल शिक्षा की व्यवस्था उनकी मातृभाषा यानी उर्दू में करनी होगी, लेकिन यूपीए सरकार ने न तो उर्दू माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कहीं खोले हैं और न ही देश के उन प्राइवेट स्कूलों को तरजीही बुनियाद पर कोई विशेष सुविधाएं दी हैं, जहां पर उर्दू माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था है. उल्लेखनीय है कि स्वयं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उर्दू अनुवाद अब तक सार्वजनिक नहीं हो सका है. हालांकि यह रिपोर्ट अंग्रेज़ी और हिन्दी में पहले से ही उपलब्ध है. चौथी दुनिया ने जब पड़ताल की तो पता चला कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उर्दू अनुवाद एनसीपीयूल (नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज) के द्वारा कराया जा चुका है और यह उर्दू अनुवाद सरकार के पास पहुंच चुका है, लेकिन उर्दू में यह रिपोर्ट न तो एनसीपीयूएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है और न ही अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर और न ही यूपीए सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट को प्रकाशित कराने का कोई प्रयास किया गया है. साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रमहान ख़ां और पूर्व मंत्री व वर्तमान विदेश मंत्री सलमान ख़ुर्शीद देश के विभिन्न सेमिनारों और पब्लिक प्लेटफॉर्मों पर यह कहते फिरते हैं कि सच्चर कमेटी की सभी या अधिकतर अनुशंसाओं को लागू किया जा चुका है. मुसलमानों को जब यह मालूम ही नहीं है कि उनके पिछड़ेपन के असल कारण क्या हैं, ऐसे में वह यह कैसे पता लगा सकते हैं कि मुसलमानों के विकास व कल्याण से संबंधित सरकार के दावे कितने सच्चे हैं. अंततः भारतीय मुसलमानों को अंधेरे में रखकर एक बार फिर कांग्रेस सरकार 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें मूर्ख बनाकर उनके वोट हथियाना चाहती है. केन्द्र सरकार के इस रवैये से तंग आकर ही केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इसे अपने यहां लागू करने की घोषणा की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ.

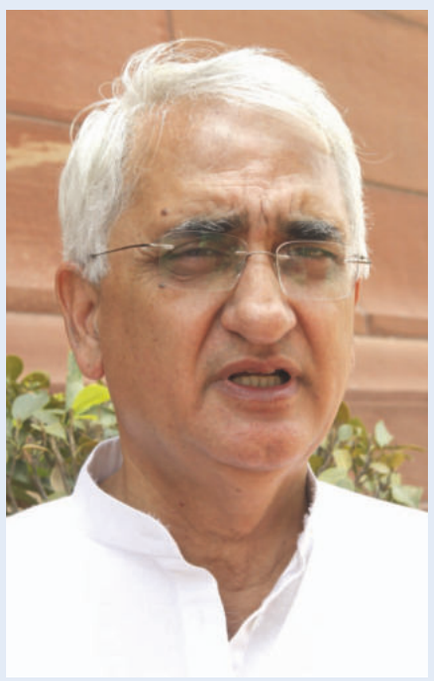

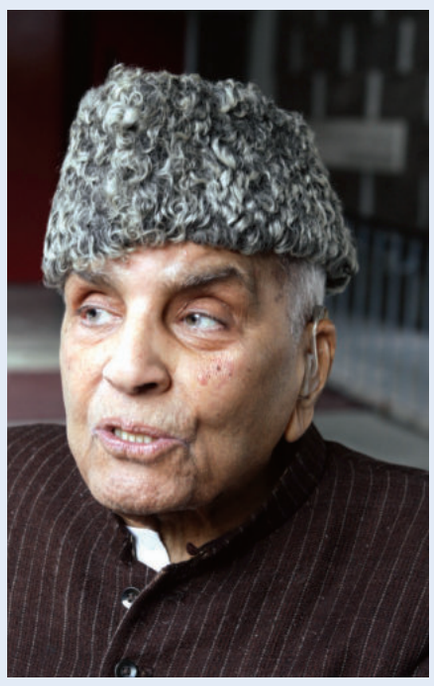

आइए देखते हैं कि सच्चर कमेटी की अनुशंसाएं क्या–क्या हैं और सरकार ने उन पर कितना अमल किया है, ताकि यह बात आम हो सके कि केन्द्र की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कितनी गंभीर है और वह कितना सच बोल रही है और कितना झूठ. यूपीए सरकार के दावों की समीक्षा करते समय यह बात याद रहनी चाहिए कि सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन को लेकर उसने जो भी कार्रवाई की है, वह 31 मार्च, 2013 तक की कार्रवाई है. मार्च से लेकर सितंबर 2013 तक उनमें काफ़ी प्रगति हुई है, जिन्हें नीचे चिन्हित किया गया है.

अनुशंसा : 1

देश में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नीतियां बनाते समय समावेशी विकास और उक्त समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि मुसलमानों के विकास को सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए और यह विकास देश में सभी स्थानों पर दिखाई भी देता हो.

यूपीए सरकार का दावा

पहली अनुशंसा पर अमल को लेकर यूपीए सरकार का दावा है कि उसने शिक्षा, रोज़गार और हाउसिंग के क्षेत्रों में होने वाली प्रगति और ख़ामियों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच व निगरानी के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2008 में सरकार को सौंपी थी, लेकिन बाद में इस काम को समान अवसर आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया.

चौथी दुनिया का रुख़

सच्चर कमेटी ने पहली अनुशंसा को लेकर इस पर विशेष बल दिया है कि इन नीतियों के लागू होने से मुस्लिम समुदाय में यह मानसिकता ख़त्म हो जानी चाहिए कि उनके साथ भेदभाव या पक्षपात से काम लिया जा रहा है और यह तभी संभव है, जब मुसलमानों को भी भारत के प्रगतिशील सामाजिक ढांचे का एक अटूट हिस्सा समझा जाए और उन्हें भी दूसरे समुदायों की तरह महत्व दिया जाए. यह सबको पता है कि भारतीय मुसलमानों के बीच यह धारणा है कि दूसरे समुदायों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है. फिलहाल उनकी इस सोच को बल मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, देश की इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से उन्हें देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के प्रयास किया जा रहे हैं.

दूसरी ओर इस पहली अनुशंसा के अमल का हाल यह है कि सरकार ने समान अवसर आयोग स्थापित करने में आनेवाली समस्याओं का बहाना बनाकर अपनी नाकामी ज़ाहिर कर दी है, यानी अब यह आयोग कभी स्थापित नहीं हो पाएगा. अब देखा जाए तो यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और आख़िरकार इसे ख़ारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लीडर, चाहे वह सलमान ख़ुर्शीद हों या फिर वर्तमान अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री के रहमान, अब तक मुसलमानों से यही झूठ बोलते आ रहे हैं कि उनकी सरकार ने सभी अनुशंसाओं या अधिकतर अनुशंसाओं को लागू कर दिया है.

अनुशंसा : 2

एक नेशनल डाटा बैंक (एनडीबी) तैयार किया जाए, जिसमें विभिन्न सामाजिक व धार्मिक समुदायों या एसआरसी (सोशियो रिलिजियस कैटगरी) से संबंधित पारदर्शिता, निगरानी और सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाया जाए. ऐसे सभी आंकड़ों को कम्प्यूटराइज़्ड किया जाए और फिर उन्हें इंटरनेट पर डाला जाए.

यूपीए सरकार का दावा

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की वेबसाइट पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मज़दूरी और रोज़गार से संबंधित एसआरसी के आंकड़ों पर आधारित 97 सूचियां अपलोड की जा चुकी हैं.

चौथी दुनिया का रुख़ :

यूपीए सरकार की ओर से बोला गया यह पहला झूठ है, क्योंकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की अपनी अलग कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि इसने सभी सूचियां सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर नेशनल डाटा बैंक नाम के पेज पर अपलोड की हैं. इन सूचियों में जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें देखकर यह पता नहीं चलता कि मुसलमानों का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है और इन क्षेत्रों में उनके पिछड़ेपन को किस हद तक दूर किया जा सका है.

दूसरी बात यह है कि सच्चर कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सबसे अधिक परेशानियों का सामना आंकड़े न होने के कारण करना पड़ा था, क्योंकि देश में ऐसी संस्था नहीं थी, जहां से सच्चर कमेटी को मुसलमानों के पिछड़ेपन से संबंधित उचित व विश्वसनीय आंकड़े मिल सकें. इसके लिए देश के सभी राजनीतिक दल तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक केन्द्र में अधिकतर सरकारें इसी पार्टी की रही हैं. कांग्रेस ने जान–बूझकर मुसलमानों को अंधेरे में रखा, क्योंकि इसे डर था कि अगर देश के मुसलमानों को अपने पिछड़ेपन की सही जानकारी का पता चल गया तो वह कांग्रेस को वोट कभी नहीं देंगे. हम सभी यह भी जानते हैं कि सच्चर कमेटी ने भारतीय शसस्त्र सेनाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर आंकड़े तलब किए थे, तो इसे क्या जवाब सुनने को मिला. ■

अगले अंक में जारी...

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री को पारदर्शी होने की ज़रूरत है

देश के लिए यह काफी सुखद है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी. ससंद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी. वह बहुत ही विनम्र, गंभीर और सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने तर्कों से विपक्ष को लाजवाब करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी बात रखने के लिए इसी तरह से सामने आएं.

देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. और यह संकट कई रूपों में है. इस संकट से उबरने के लिए सरकार की कोशिशें बहुत ही धीमी हैं और देर से हो रही हैं. हालांकि वित्तमंत्री ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. साथ ही विदेश पैसा भेजने पर भी कुछ पाबंदियां लगा दी है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है. जरूरत है कि आयात में कमी लाई जाए और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं. साथ ही कुछ समय के लिए या यूं कहें कि 31 मार्च, 2014 तक सोने के आयात पर पूरी तरह बाबंदी लगा देनी चाहिए. इसके अलावा गैरजरूरी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जैसे मोबाइल फोन, जिनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, के आयात पर भी 31 मार्च, 2014 तक पाबंदी लगा दी जानी चाहिए. यदि मार्च तक ये कदम उठाए जाते हैं, तब चालू वित्तीय घाटा भी नियंत्रण में आ जाएगा. साथ ही रुपये के कमजोर होने की वजह से बाजार में जो भय और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, वह भी नियंत्रण में आ जाएगा.

निःसंदेह इन कदमों का विरोध विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में होगा, लेकिन मेरा मानना है कि यदि कोई देश संकट का सामना कर रहा हो, तब परिस्थितियों को और गंभीर बनाने से बेहतर है कि उस देश को कुछ छूट दी जानी चाहिए. मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री के सलाहकार कौन लोग हैं. वित्त मंत्री स्वयं भी नव उदारवादी विचारधारा के साथ चलते हैं. वह खुद की स्थिति की गंभीरता को समझते हैं. फिर ऐसे में भला आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कैसे होने दे सकते हैं. मैं आशा करता हूं कि इस मसले पर वह जल्द ही तेजी के साथ कुछ आवश्यक कदम उठाएंगे. दूसरी तरफ, अंततः संसद सुचारु ढंग से चलने लगी, यह एक अच्छी खबर रही. संसद में खाद्य सुरक्षा बिल पास हो गया. निश्चित तौर पर सरकार के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी का विषय है, जिसका वायदा उन्होंने देश की 67 प्रतिशत जनता से किया है कि वे उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि खाद्यान्न के लिए पैसा कहां से आएगा. उसका वितरण और भंडारण कैसे होगा?

इस योजना में खर्च होने वाले धन की अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपये के बीच आएगी. हालांकि सब बातें कुछ वर्षों के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन सरकार जो कुछ भी करने जा रही है, उसके लिए गंभीरता से निरीक्षण करने की जरूरत है कि यह क्रियान्वित कैसे होगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पहले से ही कई राज्यों में सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है. यद्यपि तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खाद्य सुरक्षा बिल में प्रदान की गई खाद्य सुरक्षा से बेहतर खाद्य सुरक्षा योजनाएं लागू हैं. इस बिल को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार को एक ऐसी मशीनरी बनानी होगी, जो इसकी निगरानी गंभीरता से करे और इसे सही ढंग से लागू करने के लिए काम करे.

हमेशा की तरह इस बार भी खाद्य सुरक्षा बिल के संसद में प्रस्तुत होने से पहले गतिरोध बना हुआ था और इस बार मसला था कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों का मंत्रालय से गायब हो जाना. यह बड़ी ही बेवकूफी भरी सफाई है कि फाइलें मंत्रालय से गायब हो गईं. वास्तव में फाइलें सोच-समझ कर गायब की गईं. सभी को यह मालूम है कि कोल ब्लॉक का आबंटन बिना किसी कार्यवाही के, बिना टेंडर निकाले और बिना किसी मानक के आधार पर कर दिया गया था. इसलिए अगर फाइलें मिल जाती हैं तो ऐसे कई मंत्री, पूर्व मंत्री और पूंजीपति कठघरे में खड़े होंगे, जिन्होंने कोल ब्लॉक आबंटन में होने वाली अनियमितता का फायदा उठाया है.

इस आबंटन में एक कंपनी ऐसी भी है, जो कभी भी कोयले के व्यापार में नहीं थी, लेकिन उस कंपनी के नाम पर भी कोयले की खदान आबंटित की गई. और इस आबंटन के लिए कंपनी ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से हजारों करोड़ रुपये उधार भी लिए. अब, जब इस पूरे प्रकरण में होने वाली अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है तो भला बैंक कैसे अपना पैसा वापस हासिल कर पाएगा? चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायलय और सीबीआई के पास है, इसलिए फाइलों को अन्य विभागों में उपलब्ध सभी दस्तावेजों के आधार पर पुनः बनाने की कोशिश करना आवश्यक है. सीएजी का कहना है कि उनके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में उनसे जानकारी नहीं ली है.

एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री से केवल निवेदन ही कर सकता हूं, वह भी इसलिए, क्योंकि उस दौरान कोयला मंत्रालय उनके पास था. हालांकि प्रधानमंत्री हर एक फाइल को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्हें सच के साथ सामने आना चाहिए. उस समय जो कोई भी उनके कार्यालय का राज्यमंत्री अथवा सचिव रहा हो, जिन्होंने इस तरह नियम के विरुद्ध काम करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप लाखों करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ, यह लाखों करोड़ रुपया सरकार के खाते में वापस आना चाहिए.

देश के लिए यह काफी सुखद है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी. ससंद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी. वह बहुत ही विनम्र, गंभीर और सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने तर्कों से विपक्ष को लाजवाब करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी बात रखने के लिए इसी तरह से सामने आएं. मुझे लगता है कि ज्यादा पारदर्शिता बरतने से कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री, दोनों को मदद मिलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

तानाशाही के अनुभव

ठाकुर दास बंग

हाईकोर्टों के उन जजों का सजा के तौर पर दुरस्थ जगहों में तुरंत तबादला हुआ, जिनके स्वतंत्र निर्णय सरकार के खिलाफ गए. स्वतंत्र संचार साधन और निष्पक्ष न्याय-व्यवस्था लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं और आपातकाल में उनकी ही स्वतंत्रता समाप्त हो गई. व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया. इन अनुच्छेदों में मनुष्य का जीवित रहने का अधिकार भी शामिल था. उस समय के सरकारी महाधिवक्ता स्वर्गीय नीरेन डे ने एक बन्दी-प्रत्यक्षीकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह बहस की कि चूंकि मौलिक अधिकार निरस्त हो चुके थे, इसलिए नागरिकों का जीने का अधिकार भी समाप्त हो गया था. ऐसी स्थिति में यदि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा गैरकानूनी या विद्वेष वृत्ति से भी कत्ल करवा दिया जाता तो किसी को अदालत में जाने या हर्जाने की मांग करने अधिकार नहीं था. सबसे गजब की बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया. 42 वां संशोधन इस प्रकिया का चरम बिन्दु था. इसने संविधान को इस तरह संशोधित किया कि ऊपर से देखने में तो इसका लोकतांत्रिक स्वरूप बनाए रखा गया, लेकिन वास्तव में देश पर तानाशाही लाद दी गई. उस समय संविधान के दूसरे संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को कानून के ऊपर रखने की कोशिश की, ताकि उनके खिलाफ कोई भी दीवानी या फौजी कार्रवाई ना हो सके.

यानी यदि ये लोग किसी की हत्या भी कर देते या किसी की सम्पत्ति छीन लेते तो भी उनके खिलाफ कुछ भी न होता. यह याद रखना चाहिए कि आज दुनिया में ऐसे बीसों तानाशाह हैं, जिन्होंने अपने को कानून के ऊपर रखा है और सैकड़ों या हजारों खून के इल्जाम भी उनके सिर पर हैं. यह तो एक संयोग था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह संशोधन स्वीकार नहीं किया और राज्यसभा से पास होने के बाद भी यह निकाल दिया गया. सौभाग्य से मार्च 1977 में इस आशा से चुनाव की घोषणा की गई कि विरोधी नेताओं के अभी-अभी जेल से बाहर आने व जे. पी. के रोग-शय्या पर पड़े रहने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत एकदम आसान हो जाएगी. उन्हें चुनाव कराने की सख्त जरूरत थी, ताकि पश्चिमी देशों से मांग कर रुपये की नितांत कमी की शीघ्रपूर्ति के लिए वह उनकी नजरों में अपने प्रशासन का औचित्य सिद्ध कर सकतीं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी चालों को व्यर्थ कर दिया और जनता शासन को सत्ता में आने का मौका दिया. अपनी तमाम कमियों के बावजूद यह शासन इतिहास में इस घृणित 42 वें संशोधन को समाप्त करने और लोकतंत्र को फिर से अपनी राह पर लाने के लिए याद किया जाएगा, लेकिन जनता शासन अपने नेताओं के आपसी झगड़े के कारण टूट गया और इन बातों से ऊबी जनता ने अपने मतदान से इंदिरा कांग्रेस को फिर सत्ता में बिठा दिया. काफी लोगों ने यह उम्मीद की थी कि तानाशाही शासन के अनुभव, विशेषतः लोगों की, उसके प्रति तीव्र प्रतिक्रिया से श्रीमती गांधी में गंभीरता आएगी और वे आगे लोकतंत्र और आजादी में दस्तंदाजी करने में सावधानी बरतेंगी. उन्होंने उस अनुभव से पाठ जरूर सीखा है, लेकिन दूसरी ही किस्म का. उनकी आंखे अभी भी किसी-न-किसी तानाशाही पर ही लगी हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई नाटकीय कदम न उठाने की बात सीखी है. 1975 की आपातस्थिति उस चक्रवात की तरह थी, जो कुछ ही मिनटों में हर चीज को बेढ़ंगा कर देता है, हजारों को मृत और घायल कर देता है और तुरंत सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लेता है. दूसरी ओर सूखा दबे पांव आता है, धीरे-धीरे चुपचाप. लोग बराबर यह आशा लगाए रहते हैं कि यदि कल नहीं तो अगले सप्ताह वर्षा जरूर होगी और जब एक दिन उनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, वे अपने को भूखमरी और मृत्यु के किनारे पाते हैं. सूखे का समाचार दुनिया के समाचार-पत्रों में मोटी सुर्खियों में नहीं छपता, हालांकि इसके द्वारा मरे लोगों की संख्या चक्रवात से मरे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है. तानाशाही अब सूखे की तरह ही लाई जा रही है, चुपचाप, एक-एक कदम, बिना किसी नाटकीय हलचल के. हममें से ज्यादातर लोग जितना समझते हैं, उससे यह कहीं ज्यादा निकट आ चुकी है. यह करीब-करीब हमारे सिर पर आ चुकी है. आइए हम इसकी पदचाप सुनें. मिसा (आन्तरिक सुरक्षा कानून) को जनता सरकार ने रद्द कर दिया था. उसी की प्रतिकृति अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में मिलेगी, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जीवन भर के लिए जेल में बन्द हो सकता है. सिवाय इसके कि जेल से छूटने और उसमें दुबारा डाल दिए जाने के बीच उसे कुछ आजादी महसूस हो जाए. ऐसा ही घिनौना दूसरा कानून है, आवश्यक सेवा सुरक्षा कानून. यह कानून किसी भी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हड़ताल पर रोक लगाने में प्रयुक्त हो सकता है. इसके अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं की विस्तृत परिभाषा है. इसका वास्तविक इस्तेमाल होटलों में हड़ताल रोकने मे किया गया है. ऐसा नहीं है कि इस कानून के लागू होने के पहले देश में अस्पताल, पानी व बिजली आपूर्ति तथा ऐसी ही अन्य चीजों में रुकावट डालने के विरुद्ध कोई सुरक्षा कानून नहीं था. काफी कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह नया कानून सारे श्रमिक आन्दोलन को पंगु बनाने के लिए एक हथियार के तौर पर निकाला गया है. किसी भी धंधे को आवश्यक सेवा घोषित किया जा सकता है और हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है. हड़ताल में शामिल होने वाले, उनको मदद करने या सहायक होने वोलों पर संक्षिप्त अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता और उन्हें लंबी सजाओं और जुर्माने का भागीदार बनाया जा सकता है. ■

सबसे गजब की बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया. 42 वां संशोधन इस प्रकिया का चरम बिन्दु था. इसने संविधान को इस तरह संशोधित किया कि ऊपर से देखने में तो इसका लोकतांत्रिक स्वरूप बनाए रखा गया, लेकिन वास्तव में देश पर तानाशाही लाद दी गई. उस समय संविधान के दूसरे संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को कानून के ऊपर रखने की कोशिश की, ताकि उनके खिलाफ कोई भी दीवानी या फौजी कार्रवाई ना हो सके.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

वोट सिक्योरिटी बिल पास

यूपीए सरकार का वोट सिक्योरिटी बिल लोकसभा में आखिर पारित हो ही गया. सरकार को गिरते रुपये से ज्यादा चिंता केवल खाद्य सुरक्षा सिक्योरिटी बिल की थी. उसे देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है. वह तो केवल वोट के लिए कुछ भी करेंगे, के फार्मूले पर काम कर कर रही है. यूपीए सरकार को न तो जनता की चिंता है और न तो रुपये की. वह तो केवल अपने खजाने को भरने में लगी है. यह सरकार दिशाहीन हो गई है, इसका पता इसी बात से लगता है कि वित्त मंत्री चिदंबरम ने अपने एक बयान में कहा है कि 2009 से 2011 के बीच लिए गए कुछ गलत फैसलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के ये हालात बने हैं. वह अपनी सरकार द्वारा ही लिए गए फैसलों को अब गलत बता रहे हैं. जब सरकार के नुमाइंदे ही ऐसी बात करेंगे तो जनता और निवेशकों का विश्वास तो डगमाएगा ही. सच पूछा जाए तो यूपीए सरकार को केंद्र में बने रहने का अब कोई हक नहीं है. उसे जल्द से जल्द लोकसभा भंग करके चुनाव मैदान में उतरना चाहिए.

-अवधेश कुमार, सहरसा

गिरता मानवीय स्तर

आधुनिकता के ज्ञान विस्फोट में समाज को क्या मिला. धन का लोभ, संस्कारों का पतन, व्यभिचार, लूट, अश्लीलता जैसे अनेक तत्व मानवीय स्तर को पतित कर रहे हैं. ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति अपने रूप में की थी, ताकि मानव अपने अस्तित्व को समझे और पाश्विक विचारों से परे रहे. मानवीय समाज एवं संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकारों ने कई कानून बनाए, लेकिन सरकार के सभी विभागों में जमकर धज्जियास्क्षड़ाई गईं. सारे विधि-विधान ताक पर रखकर मानव रक्त का प्यासा बन गया. ऐसी स्थिति में देर-सबेर सबको एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता की शरण लेनी पड़ती है, जो हर पल हमारे कर्मों को चिन्हित कर रही है. यह सत्ता उन कर्मों का फलाफल भी देगी. यदि इस ईश्वरीय शक्ति की सत्ता की अवधारणा प्रत्येक बच्चों के मन-मस्तिष्क में बैठाई जाए, तो उन अवस्थाओं पर अंकुश स्वतः लग जाएगा. भगवान महावीर का दिव्य संदेश जीयो और जीने दो, भी यही बात बतलाता है. सही मायने में देखा जाए तो धर्म या धार्मिक ग्रन्थों का स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में होना राष्ट्रहित तथा समाज के हित में है. मध्य प्रदेश सरकार ने भगवद्गीता को पाठयक्रम में शामिल कर एक सकारात्मक पहल की है, जो एक सार्थक कदम है, बशर्ते की इसमें राजनीति न हो.

-विकास कुमार पाटनी, झुमरी तलैया

जिम्मेदार कौन

मानसून सत्र में संसद में केवल कुछ ही दिन काम हुए और बाकी दिन संसद का कामकाज हुड़दंग के कारण बर्बाद हो गया. कभी तेलंगाना के मुद्दे पर तो कभी किसी और मुद्दे पर संसद नहीं चल सका. संसद न चलने के लिए सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है. दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि संसद न चलने के लिए जिम्मेदार कौन है? बार-बार संसद का न चलना, न तो देश हित में है और न ही सरकार के हित में. संसद चलने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है. विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सरकार का काम है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे. इस बार खुद सरकार विपक्ष के सवालों से भागती नजर आई. सरकार के मंत्री लोकसभा में ऐसे बयान देते हैं, जिसके वजह से खुद सरकार की किरकिरी होती है और विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है. विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ता. इस बार विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के मंत्री और उसके नेता खुद संसद में हुड़दंग मचाने वालों में शामिल थे. सरकार हो या विपक्ष, दोनों संसद न चलने के लिए जिम्मेदार हैं. एक-दूसरे पर आरोप लगाकर ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. सरकार हो या विपक्ष, जब स्वार्थ की बात आती है तो वह एक हो जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेताओं के जेल से चुनाव लड़ने संबंधी रोक लगाए जाने पर सारे सांसद एक हो गए. सरकार और विपक्ष बाकी कामकाज छोड़कर जेल से चुनाव लड़ने संबधी बिल पारित करते हैं और जब जनता के हित से जुड़े विधयकों को पारित करना होता है तो हुड़दंग मचाते हैं. जनता सब जानती है. सरकार हो या विपक्ष, वह दोनों से चुनाव में हिसाब लेगी.

-राजेश, समस्तीपुर

हर मोर्चे पर विफल सरकार

कांग्रेस नीत यूपीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. चाहे वह देश का कोई भी मुद्दा हो. सरकार के नौ साल विफलताओं से ही भरे हैं. इसने महंगाई से लेकर घोटालों तक में कीर्तिमान स्थापित किया है. इसे न देश की चिंता है, न अर्थव्यस्था की. इसे तो केवल चिंता हैं अपनी झोली भरने की. देखा जाए तो इस सरकार ने घोटालों के क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ है. डरपोक सरकार की विदेश नीति का आलम यह है कि अभी तक पाकिस्तान और चीन ही घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन अब ठिगना कद का म्यांमार भी भारत में घुसपैठ करने लगा है. धन्य है ऐसी सरकार और सरकार को चलाने वाले बाबा घंटाल. देखा जाए तो सरकार की वजह से पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हुई है. इसके विवेकहीन नीतियों के कारण ही देश आर्थिक खाई में गिरता जा रहा है. सरकार पहले कह रही थी की अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुनामी कहां से आ रही है. यूपीए सरकार ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है.

-संजीव, जहानाबाद

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार का इक़बाल ख़त्म हो चला है

जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है और प्रशासन की साख खत्म हो जाती है, तब ऐसी घटनाओं की भरमार हो जाती है, जिन्हें नहीं होना चाहिए. दिल्ली में एक चलती बस में एक नालाबिग और चार बालिग लड़कों ने एक लड़की का अमानवीय बलात्कार किया, जिसके खिलाफ पूरी दिल्ली खड़ी हो गई. उस गुस्से को देखकर ऐसा लगता था कि शायद अब बलात्कार नहीं होंगे. और अगर होंगे, तो लोगों का गुस्सा या तो बलात्कारियों को सीधे दंडित करेगा या सरकार दंडित करेगी, लेकिन सरकार का सारा रवैया लोगों के इस गुस्से को लेकर अमानवीय भी रहा और असंवेदनशील भी, जिसकी वजह से जहां सामान्य जन में सरकार के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई, वहीं इसने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपराध करने के प्रति उकसाया भी. अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लगा कि सरकार लोगों के रोष के खिलाफ खड़ी है, यानी उनके साथ खड़ी है. दूसरी बात उनके मन में यह भी आई कि अगर हम ऐसी ही अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते रहे, तो सरकार हमारा कर क्या लेगी? हम सरकारी मशीनरी को प्रभावित कर आसानी से छूट जाएंगे. इस संदेश ने देश में बलात्कार की बाढ़-सी ला दी. देश के हर हिस्से में क्या नाबालिग, क्या बच्चे, क्या जवान और क्या अधेड़ महिलाएं कोई भी उम्र, बलात्कारियों से बच नहीं पा रही है. परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि लोगों में हताशा भी पैदा हो रही है और निराशा भी. अब बलात्कार की घटनाओं को लेकर कहीं पर भी गुस्से का इजहार नहीं हो रहा है.

वर्षों से बुंदेलखंड में एक कथन प्रचलित है कि अगर किसी की हत्या करनी है तो उससे पहले 11 बीघे गन्ना उपजाओ और फिर गन्ना बेचकर जितना पैसा आए, उसे पुलिस और अदालत पर खर्च कर दो तो हत्या करके आसानी से बच सकते हो. यह पैसा पुलिस और अदालत के कर्मचारियों में बांटने के लिए रिजर्व रखा जाता है. इसी तरह अब बलात्कार के लिए पहले शिकार तलाशा जाता है और उसका सामूहिक बलात्कार होता है और फिर लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसियों में पैसा पहुंचा दिया जाता है. इसका पहला परिणाम यह होता है कि थाने में पीड़ित महिला की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती. मैंने कई ऐसी रिपोर्टिंग की है, जिनमें बलात्कार पीड़ित महिला थाने में शिकायत लेकर गई तो उसकी शिकायत तो दर्ज नहीं ही हुई, बल्कि उसे थाने में तीन-चार दिन जबरन रोका गया और पुलिस द्वारा ही पीड़िता का बलात्कार किया गया. ऐसी खबरें कभी-कभी अखबारों में भी आईं, लेकिन उन्हें अधिकारियों ने या तो अनदेखा किया या फिर प्रकरण को दबा दिया.

अब तो अपराध करने वाले इतने निश्चिंत हो गए हैं कि वे पुलिस और प्रशासन तथा राजनेताओं को अपराध क्षेत्र में अपना सहभागी मानने लगे हैं. और क्यों न मानें! जब सत्ता चलाने वाले मंत्रियों के कमरे में टहलते हुए जाया जा सकता है और जैसी मर्जी हो, वैसी फाइल उठाकर कोई भी बाहर चला जाता है और फिर सर्वशक्तिमान सरकार के अपराध पकड़ने वाले तंत्र ऐसी घटनाओं का पता ही नहीं लगा पाते, तब कैसे इन छोटे अपराधियों के मन में डर बैठाया जा सकता है.

इसी को इकबाल खत्म होना कहते हैं. हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जब वित्तमंत्री थे, तो उनके कमरे में जासूसी यंत्र पाए गए थे. तीन दिन के बाद सरकार ने कहा कि वह यंत्र नहीं थे, च्विंगम था. सरकार अपनी बेइज्जती छिपाना चाहती थी और शायद अपनी नाकामी भी. इस घटना के पीछे कौन है, इसका पता नहीं चला. हालांकि वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण कमरों के बाहर और भीतर सेंसर लगे हुए हैं. इन कमरों में कौन जाता है, यह वहां छिपे हुए कैमरे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन न तो कैमरों में रिकॉर्ड छवि को देश के सामने रखा गया और न ही यह बताया गया कि जब-जब ऐसी घटनाएं हुईं, तब सेंसर काम कर रहा था या नहीं.

प्रधानमंत्री से जुड़े कोयले के दस्तावेज वाली फाइलें इसी अंदाज में गायब हुईं, जिनका पता न कैमरे लगा पा रहे हैं, न सेंसर लगा पा रहा है. ऐसी अभेद्य सुरक्षा बनाई गई है, जिसमें जब चाहे, तब सेंध मारी जा सकती है. और सरकार मुस्कराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये कपोल-कल्पानाएं हैं. सरकार की इन हरकतों ने खुद सरकार की और प्रशासन की साख खत्म कर दी है.

दरअसल, सरकार का सारा ध्यान उन्हें चेतावनी देने वाले या उन्हें सार्थक सलाह देने वाले की जुबान कैसे बंद हो, इस पर रहता है. रिजर्व बैंक के ट्रेजरी पर जांच एजेंसियों का छापा पड़ता है और वहां बड़ी मात्रा में नकली नोट पाए जाते हैं. जब यह रिपोर्ट प्रामाणिकता के साथ छापी जाती है कि नकली नोटों की सप्लाई रिजर्व बैंकों के जरिये भी हो रही है तथा इसके पीछे कौन-सी देशी-विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, तो सरकार इस पूरे किस्से को दबाने की कोशिश करती है और यहां पर भी जो लोग ऐसी खबरों का खुलासा करते हैं, सरकार उन्हें प्रताड़ित करने में लग जाती है.

जहां सरकार अपना इकबाल खुद खत्म कर रही है, वहीं वह आर्थिक अपराध करने वालों को न केवल प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि छोटे अपराधियों के लिए अभयदान जैसा माहौल बना रही है. न सरकार सख्त है, न प्रशासन सख्त है. कोई भी केस वर्कआउट नहीं हो रहा. सरकार शायद यह सोचकर बैठी है कि किसके पास वक्त है, जो रोज प्रदर्शन में जाए. सरकार का सोचना सही है, क्योंकि जनता इन सारी स्थितियों से निराश हो चुकी है, लेकिन जब जनता में निराशा ज्यादा बढ़ जाती है तो वह निराशा एक बड़े तूफान की भूमिका भी बना जाती है. अब ये सरकार और राजनीतिक तंत्र के सोचने की बात है कि वे जनता को किस हद तक अनदेखा करेंगे और किस हद तक उसे चिढ़ाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप जनता कहीं कानून हाथ में न लेने लगे. ■

जब जनता में निराशा ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह निराशा एक बड़े तूफान की भूमिका भी बना जाती है. अब यह सरकार और राजनीतिक तंत्र के सोचने की बात है कि वह जनता को किस हद तक अनदेखा करेंगे और किस हद तक उसे चिढ़ाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप जनता कहीं कानून हाथ में न लेने लगे.

editor@chauthiduniya.com

यह घाव कांग्रेस ने खुद तैयार किया है

मेघनाद देसाई

भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी को एक बड़े नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी, तब कांग्रेस को खुश होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के पास एक टेलर मेड मुद्दा मिल गया था, जिसमें पार्टी आराम से बीजेपी को संप्रदायवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी कहकर खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूत कर लेती. निश्चित रूप से यह ऐसा मैच होता, जो कांग्रेस के लिए फिक्स था. लेकिन अब जो चुनावी सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें दोनों ही भाजपा के मुकाबले घटने वाली हैं.

लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई प्रेत छाया पड़ गई है. दरअसल, यह प्रेत छाया नरेंद्र मोदी की है. कांग्रेस के सभी वरिष्ठ प्रवक्ता और पार्टी के दूसरे बड़े नेता मीडिया के माध्यम से बस नरेंद्र मोदी को ही कोसने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके उलट कांग्रेस जितना ही नरेंद्र मोदी की भर्त्सना कर रही है, मोदी जनता की नजरों में कमजोर पड़ने के बजाए उतने ही बड़े होते जा रहे हैं. इस स्थिति को लेकर कांग्रेस पसोपेश में पड़ गई है कि क्या वह मोदी को एक प्रांतीय नेता मानकर अनदेखी करे. उनकी राहुल गांधी से तुलना न करे या फिर अपने प्रवक्ताओं से कहे कि वह मोदी को फांसीवादी बताते हुए उनके खिलाफ और उग्र रूप धारण कर लें.

भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी को एक बड़े नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी, तब कांग्रेस को खुश होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के पास एक टेलर मेड मुद्दा मिल गया था, जिसमें पार्टी आराम से बीजेपी को संप्रदायवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी कहकर खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूत कर लेती. निश्चित रूप से यह ऐसा मैच होता, जो कांग्रेस के लिए फिक्स था.

लेकिन अब जो चुनावी सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें दोनों ही भाजपा के मुकाबले घटने वाली हैं. राहुल की लोकप्रियता मोदी की तुलना में कम हो रही है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. जो मतदाता इस बलिदानी परिवार में अपनी आस्था रखे हुए हैं, उनके मत-परिवर्तन की वजह क्या है.

इस सवाल का जवाब है देश की चरमराती अर्थव्यवस्था. देश की अर्थव्यवस्था तेजी से गर्त में जा रही है. मुद्रास्फीति की दर पिछले चार वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है. चालू वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है और बजट घाटा तकरीबन 5 प्रतिशत तक पहुंच गया है. रुपये की गिरती कीमत बता रही कि हमारी अर्थव्यवस्था बीमार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है. रघुरामन राजन और घुवुरी सुब्बाराव जैसे अर्थशास्त्री तकरीबन मार्च 2012 से ही यह अंदेशा जता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 जैसे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है. मौजूदा हालात में मुद्रास्फीति ही मतदाताओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर रही है. रुपया जितना ही गिरता जाएगा, मुद्रास्फीति उतनी ही बढ़ेगी और हालात उतने ही खराब होंगे.

यह घाव पार्टी ने खुद अपने लिए तैयार किया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र ही जिम्मेदार है. पार्टी की जो उदार अर्थशास्त्रियों की फौज है, वह चाहती है कि देश में विकास हो. राजकोष अनुशासित हो. मुद्रास्फीति की दर कम हो, जबकि पार्टी की समाजवादी विंग चाहती है कि पुनर्वितरण हो. यह घटक मानता है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के पुनर्वितरण को संभाला जा सकता है, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत. योजनाओं के वितरण के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है. आश्चर्य की बात है कि देश में एक साथ इतने अर्थशास्त्री निर्णायक पदों पर आसीन हैं. समाजवादी शाखा इस मुगालते में है कि वे देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और वे इस बात की जल्दी में भी दिख रहे हैं.

पार्टी का यही घटक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मनमोहन सिंह का दौर अब खत्म हो रहा है और युवराज यानी राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है. हालांकि इस सरकार ने जो फैसले किए, उसके दुष्परिणाम यूपीए-2 की शुरुआत से ही दिख रहे हैं.

अब उन गलत फैसलों के दुष्परिणाम खुलकर सामने आ रहे हैं. आज देश अपनी चमक खो चुका है और इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी अब बैकफुट पर है. हमारा सौभाग्य ही है कि रेटिंग एजसियों ने अभी हमें बख्शा हुआ है और हम रेटिंग में बहुत नीचे नहीं पहुंचे हैं.

लेकिन विडंबना तो यह है कि कोई भी अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है. समाजवादी घड़ा अब फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है. और वे इसे विश्व की सबसे महान योजना बताने पर तुले हुए हैं, जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह योजना पहले से चली आ रही कई अन्न योजनाओं में की एक कड़ी भर है. फिर इस योजना पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में इस योजना से बेहतर योजनाएं पहले से ही चल रही हैं.

अगर सरकार इस योजना को अपने वोट बैंक के तौर पर देख रही है तो इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. अर्थव्यवस्था नकारात्मक दिख रही है. और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने इतनी खर्चीली योजना शुरू की है, जो आने वाले दिनों में उसके लिए ही घातक साबित हो सकती है. यह मुश्किलें, जितनी कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद समाजवादी विचारधारा वालों के कारण पैदा हुई हैं, उतनी ही बाहर मौजूद वामपंथियों के द्वारा भी. पूंजी पर हमारा नियंत्रण खत्म हो चुका है. आयात महंगा हो रहा है और सोने के प्रति हमारी लालसा बनी हुई है. कुल मिलाकर हम सेकुलर समाजवादी स्थिरता के दौर में पहुंच चुके हैं. ■

आश्चर्य की बात है कि देश में एक साथ इतने अर्थशास्त्री निर्णायक पदों पर आसीन हैं. समाजवादी शाखा इस मुगा-लते में है कि वे देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और वे इस बात की जल्दी में भी दिख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

पंचायत के ख़र्च का हिसाब मांगें

सूचना के अधिकार क़ानून के आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता. बशर्ते, आप सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए सलाना लाखों रुपये आते हैं. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं भी आती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

गांधी जी का सपना था कि देश का विकास पंचायती राज संस्था के ज़रिये हो. पंचायती राज को इतना मज़बूत बनाया जाए कि लोग ख़ुद अपना विकास कर सकें. आगे चल कर स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के नाम पर त्री–स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू भी की गई. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद. खंड स्तर पर एक इकाई और सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत की

अवधारणा लागू हो गई. इसके साथ ग्राम सभा नाम की भी एक संस्था बनाई गई. ग्राम सभा एक स्थायी संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें पंचायत के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं. ग्राम सभा की संकल्पना इसलिए की गई थी, ताकि पंचायत के किसी भी विकास कार्य में गांव के लोगों की सीधी भागीदारी हो. उनकी सहमति से विकास कार्य की कोई भी रूपरेखा बने, लेकिन

हुआ ठीक इसका उल्टा. आज देश की किसी भी पंचायत में ग्राम सभा की हालत ठीक नहीं है. ग्राम सभा की बैठक महज़ खानापूर्ति के लिए की जाती है. किसी भी विकास योजना में ग्रामीणों से न तो कोई सलाह ली जाती है और न ही ग्राम सभा की बैठक में उस पर चर्चा की जाती है. पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है, लेकिन सूचना के अधिकार क़ानून के आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता. बशर्ते, आप सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये सलाना आते हैं. इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं. ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपको लगता है कि सरपंच और अन्य अधिकारी मिल कर इन रुपयों और योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं तो बस आप सूचना का अधिकार क़ानून के तहत एक आवेदन डाल दें. आप अपने आवेदन में किसी एक ख़ास वर्ष में आपकी पंचायत के लिए कितने रुपये आवंटित हुए. किस कार्य के लिए आबंटन हुआ? वह कार्य किस एजेंसी के द्वारा करवाया गया? कितना भुगतान हुआ? भुगतान की रसीद इत्यादि की भी मांग कर सकते हैं. इसके अलावा, आप कराए गए कार्यों का निरीक्षण करने की भी मांग कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं. मसलन, इंदिरा आवास योजना के तहत आपके गांव में किन–किन लोगों को आवास आवंटित हुए. ज़ाहिर है, जब आप ये सवाल पूछेंगे, तो भ्रष्ट सरपंचों और अधिकारियों पर एक तरह का दबाव बनेगा. और यह काम आप चाहें तो कई लोगों के साथ मिल कर भी कर सकते हैं. जैसे अलग–अलग मामलों पर या एक ही किसी मामले में कई लोग मिल कर आवेदन डालें. इसका असर यह होता है कि चाह कर भी कोई दबंग सरपंच या अधिकारी आप पर दबाव नहीं डाल पाएगा या आपको धमकी नहीं दे पाएगा. तो, हम उम्मीद करते हैं कि इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आपकी पंचायत में यदि भ्रष्टाचार है तो उसे ख़त्म किया जा सके, उसे करारा जवाब दिया जा सके. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ग्राम पंचायत के ख़र्चे का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
.....ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

1. वर्ष.....के मध्य.....ग्राम पंचायत को किन-किन मदों/योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? आबंटन का वर्षवार ब्योरा दें.
2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान करवाए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:

1. कार्य का नाम
2. कार्य का संक्षिप्त विवरण
3. कार्य केलिए स्वीकृत राशि
4. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
5. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
6. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
7. कार्य शुरू होने की तिथि
8. कार्य समाप्त होने की तिथि
9. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
10. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
11. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
12. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.
13. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिहोंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी.
14. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष.....के दौरान कार्यो/योजनाओं पर होने वाले खर्चो की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:

क. कार्य का नाम जिसके लिए ख़र्च किया गया
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ड. कार्य शुरू होने की तिथि
च. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
छ. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रुपये अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम केप्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

इस सप्ताह कानूनी दस्तावेज को जांच-परख कर हस्ताक्षर करें. कोई विदेशी संपर्क वाला व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है. शारीरिक कष्ट थोड़ा बढ़ेगा और आप थोड़ा ढीला महसूस करेंगे. माता-पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा. अचानक यात्रा से कुछ फायदे का योग है. पारिवारिक और मांगलिक कार्य में कुछ खर्चे की सम्भावना बनती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

इस सप्ताह विलासिता से संबंधित खर्च हो सकती है. इस सप्ताह क्रय-विक्रय करते वक़्त ध्यान रखें, क्योंकि धोखा हो सकता है. पूर्व से चला आ रहा रोग परेशान कर सकता है. वाहन को सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट लग सकती है. क्रोध और संयम खोने से बचें. शत्रुओं पर नज़र रखें. थोड़ी दौड़-भाग भी बढ़ेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

इस सप्ताह आप धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे और किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे. इस सप्ताह किसी नाउम्मीद जगह से आपको अच्छी खबर मिलेगी. निवेश सोच-समझ कर करें. सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. व्यापारी वर्ग काफी खुश रहेंगे और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा करेंगे. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

इस सप्ताह आप विनम्र होकर चलें. किसी से रुष्ट होकर कोई कार्य न करें. अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग काफी अच्छा करेंगे. व्यापारी वर्ग नये कार्य की तलाश करेंगे और सफल रहेंगे. निवेश की सम्भावना है और आप उससे काफी प्रसन्न रहेंगे. आपके नये-नये मित्र बनेंगे, जो लम्बे समय में आपके लिए मददगार साबित होंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

इस सप्ताह आपके खर्चे आपकी परेशानी का कारण बनेंगे. घर की समस्या को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी. अपने कार्य स्थल पर साथ के लोगों से सामंजस्य बना कर चलें. विद्यार्थी वर्ग अच्छा करेंगे. आपके कार्य करने की शैली ज्यादा व्यावसायिक रहेगी. व्यापारी वर्ग अपने अन्दर मजबूती महसूस करेंगे. स्वास्थ्य थोड़ी बहुत समस्या के साथ ठीक चलेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

इस सप्ताह आपका घरेलू प्रबंधन बहुत ही अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश थोड़े मंथन के बाद करें. कोई भी निर्णय उत्तेजना में न लें. मानसिक परेशानी को अपने ऊपर हावी न होने दें. यात्रा की योजना बनेगी और आप लाभान्वित रहेंगे. आपका पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी बढ़ेगा. परिवारिक बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

इस सप्ताह अपने मन की सोची हुई रणनीति को किसी से उजागर न करें. अपना कार्य करते चलें, फल अवश्य मिलेगा. शुभ कार्य में थोड़ा विलम्ब होगा. सामाजिक रूप से आपका उत्तरदायित्व बढ़ेगा. व्यापारी और नौकरीपेशा, दोनों वर्ग अच्छा प्रदर्शन करेगे. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खासकर उदर और नसों से संबंधित समस्या का ध्यान रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

इस सप्ताह आपकी प्रगति के राह खुले रहेंगे. आपका धनोपार्जन अच्छा होगा. धन के आगमन के वजह से आप पारिवारिक लोगों का भी खास ध्यान रख पाएंगे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे. इस बिच अपने घमंडी स्वभाव से बचें. स्वास्थ्य हलके उतार-चढ़ाव के साथ ठीक रहेगा. कोई पुराना मित्र आपके लिए सहयोगी बनकर खड़ा रहेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

इस सप्ताह आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी. आपके दोस्तों और मित्रों का दायरा बढेगा. अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आपका मंथन चलेगा और इस विचार को लेकर आप व्यस्त भी रहेंगे. इस सप्ताह आप बहुत ही समझदारी का परिचय देंगे. आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव आएगा, विचलित न हों. स्वास्थ्य औसतन ठीक रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

इस सप्ताह आपके पारिवारिक सदस्यों और मित्र-बंधुओं के बीच सम्बन्ध में सुधार आएगा. कोई भी जमीन-जायदाद और नई संपत्ति की खरीद में कानूनी दस्तावेज को जांच-परख कर खरीदें. आपका विनम्र स्वभाव पराये को भी अपना बनाएगा. सत्ता से सम्बंधित लोग भी मददगार साबित होंगे. स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

इस सप्ताह आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है. आपके विरोधी थोड़े सक्रिय होंगे, लेकिन आप उन्हें परास्त करने में सफल होंगे. दांपत्य जीवन में कोई खटास न आने दें. अपने व्यावसायिक पार्टनर पर खास ध्यान रखें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

इस सप्ताह आपको जोखिम उठाने की इच्छा होगी, लेकिन आप इससे बचें. यह आपका व्यय बढ़ने का समय है. सोच-समझकर खर्च करें. वाणी पर संयम रखें और कटुता न आने दें. दांपत्य जीवन में कोई दरार न आने दें. अपने परिवार के वरिष्ट सदस्यों का आशीर्वाद लेकर कोई नये कार्य करें.

ज़रा हट के

मेंढक की निकली बारात

आज तक हमने इंसानों की बारात देखी और सुनी है, लेकिन अगर आपको पशु–पक्षियों की बारात के बारे में सुनने को मिले तो पहली बार तो आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन यह सोलह आने सत्य है कि एक जगह लोगों ने मिलकर मेढक की बारात निकाली. सोनभद्र जिले में आदिवासियों ने बारिश के लिए मेढ़क और मेढ़की की शादी कराई. धूमधाम से मेढक की बारात निकाली गई और बैंड–बाजे पर जमकर नाच–गाना हुआ.

बारिश नहीं होने और जिले को सूखे से बचाने के लिए आदिवासियों ने लिलासी गांव में मेढक और मेढकी का ब्याह कराने का फैसला किया. वर पक्ष के मुखिया शिव प्रसाद बने तो वधू पक्ष के मुखिया की जिम्मेदारी विश्वनाथ ने संभाली. नये कपड़े पहने शिव प्रसाद गांव के करीब पचास लोगों के साथ मेढक की बारात लेकर टेम्पो से पड़ोस के मुरता गांव पहुंचे, जहां एक मंदिर के परिसर में बारात के ठहरने और विवाह के आयोजन की व्यवस्था की गई थी. स्वागत–सत्कार के बाद दूल्हा बने मेढक की अगवानी हुई. बैंड–बाजों की धुन पर बारातियों ने जमकर ठुमके लगाए. दोनों गांवों के लोगों द्वारा विधि–विधान से शादी की रस्म पूरी कराई गई. ऐसी मान्यता है कि मेढक और मेढकी की शादी कराने से बारिश होती है. बारात विदाई के बाद वर–वधू को लिलासी में देवस्थल चौरा पर देवी को प्रणाम कराकर गांव के एक पोखर में जीवन–यापन करने के लिए छोड़ दिया गया.■

डॉक्टरों ने जिंदा किया महिला को !

कोई व्यक्ति मर जाए और उसे फिर से जीवित कर लिया जाए, ऐसा संभव है. नहीं न, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने एक ऐसी महिला की जिंदगी बचा ली, जो 42 मिनट पहले मृत घोषित हो चुकी थी. इस महिला को हार्ट अटैक के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां शीघ्र ही उसे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन ऐसी हाईटेक मशीनों के जरिये, जो दिमाग में खून की सप्लाई जारी रखती हैं. मेलबर्न के डॉक्टर महिला की धमनियों में खून का रास्ता खोलने में कामयाब रहे और इससे महिला के दिल की धड़कनें भी लौट आईं.

अस्पताल ने महिला के बचने को हैरानी भरा बताया है. पीड़ित महिला वैनीसा तानासियो 41 साल की हैं और दो बच्चों की मां हैं. तानासियो को पहली बार ये अटैक आया था और उसी ने उन्हें लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया, लेकिन चमत्कारी मशीन और डॉक्टरों की मेहनत और सूझ–बूझ से उनकी जान बच गई. इस वाकये को जिसने सुना आवाक रह गया.

तानासियो ने बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं.■

प्लेन के पहियों के सहारे सफ़र

अगर आपको विमान के बदले उसके पहियों को पकड़कर यात्रा करनी पड़े तो क्या आप यात्रा करेंगे. आपका जवाब होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन विमान के पहियों के बीच छिपकर यात्रा करने वाले एक नाइजीरियाई युवक के बारे में आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे. यह नौजवान सकुशल बच गया. एरिक एयर के प्रवक्ता ओला अदेबानजी ने बताया कि नाइजीरिया का एक नौजवान डेनियल इहेकिना अपने गृहनगर बेनिन के हवाई अड्डे से लागोस जाने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को धता बताते हुए विमान के पहियों के अपनी जगह पर जाने के दौरान ही वहां छिप गया था.

बाद में विमान के यात्रियों की नजर उस पर गई तो उन्होंने विमान के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी. ■

सीरिया में जारी हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद से सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने का आग्रह करने को कहा है. भारत सीरियाई लोगों के हित में विचार-विमर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सभी मुद्दों का समाधान करने के पक्ष में है.

गृहयुद्ध की आग में झुलसता सीरिया

राजीव रंजन

सीरिया में पिछले दो वर्षों से हिंसा, रक्तपात और अराजकता का माहौल है. सेना और विद्रोहियों के इस संघर्ष में अब तक लगभग एक लाख लोग अपनी जान गवां चुके हैं. इसमें कोई दो राय नहीं कि असद शासन इस संघर्ष को रोकने और देश में स्थायित्व लाने में नाकाम रहा है. रासायनिक हथियारों के बहाने अमेरिका और पश्चिमी देश सीरिया पर हमले को लेकर उतावले हैं. रिपोर्टों पर विश्वास करें तो सीरिया को चौतरफा घेर लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि सीरिया पर हमला किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, बल्कि इससे क्षेत्र में नई समस्याएं ही पैदा होंगी. यह सही है कि असद सेना और विपक्ष दोनों ने युद्ध अपराध किए हैं, लेकिन इस आग को पश्चिमी देश नहीं बुझा सकते. कहीं न कहीं पश्चिमी देशों का इस देश पर हमले की योजना अपने हितों को साधने जैसा है.

सीरिया में पिछले दो वर्षों से हिंसा और रक्तपात जारी है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे ही सबसे ज्यादा मारे गए हैं. फिलहाल इस देश के 68 लाख लोगों को तत्काल सहायता की जरूरत है. हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बावजूद इसके पश्चिमी देश सीरिया पर हमले को लेकर अपनी आस्तीनें चढ़ाए हुए हैं. जिस तरह से इस देश को लेकर पूरा विश्व दो फाड़ में बंट गया है, उससे एक और विश्व युद्ध के हालात नजर आ रहे हैं. जरूरत है सभी देशों को मिल-बैठ कर सर्वमान्य हल निकालने का, क्योंकि हमला या युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न ही यह किसी के हित में है.

हमला समस्या का हल नहीं

किसी भी देश पर हमला, वहां की समस्या का हल नहीं हो सकता है? पश्चिमी देश जिस तरह से सीरिया पर हमले को लेकर उतावले हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का इस हमले के पीछे अपना निहित स्वार्थ है. वास्तव में देखा जाए तो दमिश्क के बाहरी इलाके में कथित रासायनिक हमले के बाद सीरिया पर हमले की योजना तैयार की गई है. सूत्र बताते हैं कि रासायनिक हथियारों के हमले में लगभग 1400 लोगों के मारे जाने की आशंका है और पश्चिमी देशों को इन रासायनिक हमलों से भविष्य में डर है, लेकिन सवाल है कि जिस कथित रासायनिक हमले की दुहाई देकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सीरिया पर हमले करने की सोच रहे हैं, वह रासायनिक हमला हुआ भी है कि नहीं, यह अभी साफ नहीं हो सका है. खबर लिखे जाने तक रासायनिक हथियारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी. संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट अभी दे या फिर देने में कितना भी समय लगे, लेकिन कोई भी रिपोर्ट हमले का आधार नहीं बन सकती.

पश्चिमी देशों की तानाशाही

पश्चिमी देशों के नागरिक भी सीरिया पर हमला और खून-खराबे के पक्ष में नहीं हैं. ब्रिटिश संसद में सीरिया पर सैन्य हमले के विरोध में मतदान भी हो चुका है. अमेरिकी संसद में भी सीरिया पर हमले को लेकर एक मत नहीं है. बावजूद इसके, ये देश तानाशाही रवैया अपना रहे हैं. यह बात खुले तौर पर कही जा सकती है कि सीरिया पर हमला होना या न होना अमेरिकी हितों पर निर्भर करता है. सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने आरोप लगाया है कि विद्रोही सरकार को दोषी ठहराने के लिए रासायनिक हथियारों के तिकड़मों का सहारा लिया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पहले सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के लिए उतारू अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के उतावलेपन को दुनिया देख रही है. विश्व समुदाय यह भी नहीं भूला है कि रासायनिक हथियारों की आड़ में अमेरिका ने इराक में क्या खेल खेला. सच मायने में देखा जाए तो सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों के अपने हित हैं, जो किसी बहाने उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहते हैं. अपने पैंतरेबाजी के तहत सीरिया के मौजूदा आंतरिक हालात के लिए उन्होंने टर्की, इजराइल और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकमत नहीं

सीरिया पर हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी एकमत नहीं है. सीरिया के प्रबल समर्थक देश रूस और ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के इस आक्रामक रुख पर गंभीर चिंता जताई है. रूस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करके उन्हें पुरानी ग़लती फिर से नहीं दोहरानी चाहिए. रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश में बाहर से सैन्य हस्तक्षेप करके सुरक्षा नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके विपरीत उस इलाके में अस्थिरता ही पैदा हुई है. चीन भी सीरिया पर हमले के खिलाफ है. ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर सीरिया पर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे.

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता

संयुक्त राष्ट्र संघ अब तक सही मायनों में एक वैश्विक संस्था बन ही नहीं पाई है. सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य जब तक एकमत नहीं होते, तब तक संयुक्त राष्ट्र कुछ कर ही नहीं सकता. इसका मतलब यह है कि सुरक्षा-परिषद स्थाई सदस्यों का बंधक है. यही कारण है कि अमेरिका हमेशा ही इसे आखें दिखाता रहा है और अपनी दादागिरी करता रहा है. परिणामतः दुनिया प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वाली खतरनाक स्थितियों से घिरती जा रही है.

भारत के आर्थिक हित होंगे प्रभावित

सीरिया को भारत चाय, मशाला और बासमती और अन्य प्रकार के चावल को भारत बड़े पैमाने पर सीरिया को निर्यात करता है. ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया के अनुसार सीरिया के चावल आयातक इस समय भुगतान समस्या से गजर रहे हैं, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है. सीरिया पर हमले की स्थिति में भारत का चालू खाता घाटा प्रभावित होगा. चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही गर्त में जा रही है, इसलिए यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि हमले की स्थिति में कच्चे तेल की कीमत वर्तमान के 109 डॉलर प्रति बैरल से 117 से 120 डॉलर प्रति बैरल हो जाएगी. विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से हमारे यहां तेल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी और तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, जिससे रोजमर्रा के उपयोग की लगभग सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी.

संकट का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी : भारत

भारत शांतिप्रिय देश है. सीरिया में जारी हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद से सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने का आग्रह करने को कहा है. भारत ने सीरिया के लोगों की उचित आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सभी मुद्दों का समाधान करने के पक्ष में है.

सर्वमान्य हल

संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के ताकतवर देश सीरिया और विपक्ष को विश्वास में लेकर ईमानदारी से बातचीत का प्रयास करें तो स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मौजूदा समय में दोनों पक्षों में इसका अभाव दिख रहा है. जिस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक और लीबिया के साथ किया, अगर वही कदम सीरिया को तबाह करने में ये देश उठाते हैं और यदि अपनी मनमानी करने में ये देश सफल हो भी हो जाते हैं तो पश्चिम एशिया के इस देश का स्वरूप एक अराजक एवं अस्थिर देश का होगा. अस्थिर और अराजक सीरिया समूचे पश्चिम एशिया एवं विश्व बिरादरी के लिए समस्याएं खड़ी करेगा. इसलिए जरूरी है कि ओबामा और पश्चिमी देश आगे बढ़ने से पहले अपने इस कदम पर एक बार फिर विचार कर लें.■

सीरिया

सीरिया दक्षिण-पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है. यह इजराइल तथा इराक के बीच स्थित है. मध्य-पूर्व के देशों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है. इसकी राजधानी दमिश्क है. 1963 से यहां आपातकाल लागू है, जिसके कारण 1970 के बाद से यहां के शासक असद परिवार के लोग होते हैं. यहां के राष्ट्रपति बशर अल-असाद और प्रधानमंत्री मोहम्मद नाजी अल-ओतारी हैं. सीरिया की 90 फीसद आबादी मुस्लिम है और 10 फीसद ईसाई. सुन्नी मुस्लिम कुल जनसंख्या के 74 फीसद हैं, जबकि शिया करीब 13 फीसद. यहां यहूदी भी कुछ संख्या में रहते हैं. यहां की अधिकारिक भाषा अरबी है. इसके अतिरिक्त कुर्द, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं भी यहां बोली जाती हैं. सीरिया की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि, पेट्रालियम, उद्योग और पर्यटन पर टिकी हुई है. ■

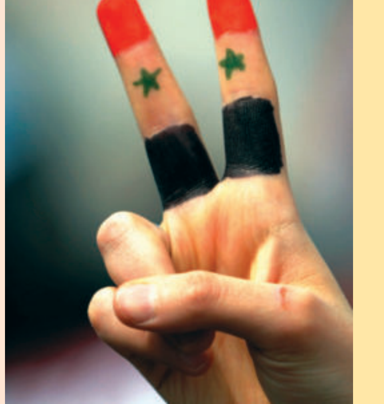

कौन हैं बशर अल असद

बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं. 11 सितंबर, 1965 को उनका जन्म हुआ था. असद अपने पिता के दूसरे बेटे हैं. उन्होंने दमिश्क विश्वविद्यालय से नेत्र संबंधी अध्ययन में डिग्री हासिल की है और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे. बड़े भाई की मौत के बाद बशर अल असद को राजनीतिक रूप से तैयार होना पड़ा. वर्ष 2000 में अपने पिता हाफेज अल असद की मौत के बाद उन्होंने सीरिया में सत्ता की बागडोर संभाली. ■

कैसे भड़की यह आग

मार्च 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति असद को पद से हटाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण व्यापक प्रदर्शन हुए. सरकार को यह प्रदर्शन नागवार गुजरा. इसलिए उसने प्रदर्शनकारियों का दमन करने का प्रयास किया. इसके बाद असद विरोधी आंदोलन हिंसक हो गया और विद्रोहियों ने सीरिया की सेना के साथ संघर्ष शुरू कर दिया. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक दोनों पक्षों के 100,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं. इन संघर्षों के कारण सीरिया में गंभीर आर्थिक संकट भी पैदा हो चुका है. ■

जानलेवा हैं रासायनिक एवं जैविक हथियार

रासायनिक हथियार के रूप में क्लोरीन गैस का दुरुपयोग जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रभावी रूप से किया था. यह गैस फेफड़े के ऊतकों को जलाकर नष्ट कर देती है, जो जानलेवा है. आज-कल वैज्ञानिकों का ध्यान कीटनाशक दवाओं में पाए जाने वाले विषैले रसायनों को और भी प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर है, जो किसी की जान लेने के लिए काफी है. मस्टर्ड एवं लेविसाइट जैसी गैसों का दुष्प्रभाव त्वचा पर छाले एवं फेफड़े के ऊतकों के विनाश के रूप में देखा जा सकता है. मस्टर्ड गैस की दस मिली ग्राम की मात्रा ही मृत्यु के लिए पर्याप्त है.

जैविक हथियार

अधिकांश बीमारियों की जड़ में जीवाणु होते हैं. उनके विरुद्ध सामान्य एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाते हैं. ऐसे जैविक हथियारों को छोटे-मोटे जानवरों, पक्षियों, हवा, पानी, मनुष्य आदि किसी भी साधन द्वारा फैलाया जा सकता है. ऐन्थ्रैक्स, वैरियोला वाइरस, इबोला वाइरस, बॉट्युलिन बैक्टीरिया, जानवरों में खुरपका बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया, प्लेग वाइरस, ये ऐसे वाइरस हैं, जिसका प्रयोग आतंकवादी या अपराधिक तत्व जैविक हथियार के रूप में कर मनुष्य जगत को मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं.

बचाव के उपाय

इससे बचने के कोई ठोस एवं कारगर उपाय नहीं है. युद्ध क्षेत्र में सैनिक गैस मास्क एवं त्वचा को पूरी तरह ढकने वाले सूट पहन कर अपना बचाव कुछ सीमा तक कर पाएँगे. उपरोक्त परिधान के अतिरिक्त नाना प्रकार के वैक्सिन तथा विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स की भारी खुराक जैविक हथियारों के आक्रमण भी से बचाव में सभंवत: सहायक सिद्ध हो सकती है. रसायनों के नए प्रकार एवं जीवाणुओं की नई जेनेटिकली परिमार्जित किस्म बड़ी आसानी से उपरोक्त सुरक्षा उपायों को भेद सकती है. और यही कारण है उन रासायनिक एवं जैविक हथियारों से डरने का. ■

साई

मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथो में मिलता है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. यहां भगवान के दर्शन के लिए विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है. इसी पर्ची के माध्यम से आप यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं.

आस्था

सबका मालिक एक है

चौथी दुनिया ब्यूरो

आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां के लोग श्री शिरडी के साई बाबा के नाम से परिचित न हों. वह भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के आध्यात्मिक विभूति थे. मानयता है कि उनका जन्म लगभग 1838 ई. में महाराष्ट्र के पथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ वर्ष तक एक मुस्लिम फकीर परिवार ने पाला था. उसके बाद साई शेलू गांव के एक ब्राह्मण संत गुरु वेंकुशा के आश्रम में 12 वर्ष तक रहे थे. 1854 में साई अपने गुरु के आदेश और आशीर्वाद से शिरडी गांव में चले गए थे. वहां लगभग दो माह तक एक युवक संत के रूप में रहने के बाद साई अचानक वहां से चले गए थे. तीन वर्ष बीतने के बाद 1858 में एक बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आए थे और फिर वहीं बस गए थे. वहां साई ने एक त्यागी हुई पुरानी वीरान पड़ी हुई मस्जिद को अपना स्थान बनाया और जो द्वारिका माई के नाम से प्रसिद्ध है. यह नाम साई के द्वारा ही दिया गया है. साई 60 वर्षों तक उसी मस्जिद में रहे थे और 80 वर्ष के आयु में साई ने शिरडी में ही अपना प्राण त्यागा था. साई ने किसी को भी अपने परिवार, जाति धर्म के बारे में नहीं बताया था, लेकिन कुछ प्रमाणों से माना जाता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे. वे शिरडी में फकीर का एक सीधा–सादा जीवन व्यतीत करते थे. वे हमेशा अल्लाह मालिक है, कहते रहते थे. साई मानवों व पशु–पक्षियों सभी को अपना प्रेम और सद्भाव देते थे. उनके पास संस्कृत, उर्दू, अरबी, मराठी, हिंदी, और तमिल भाषाओं की जानकारी थी. साई शिरडी गांव में केवल पांच परिवारों से ही रोज दिन में दो बार भिक्षा मांग कर लाते थे. जो भी भिक्षा में मिल जाता, उसे द्वारिका माई में लाते थे और सभी को मिट्टी के बर्तन (परात) में सभी को मिलाकर रख देते थे. कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया आकर उनका एक अंश आकर खा जाते थे, तब उसके बाद बचे भिक्षा को भक्तों के साथ मिल–बांट कर खाते थे. साई के द्वारा द्वारिका माई में स्थापित की गई धुनी आज भी लगातार प्रज्ज्वलित हो रही है. साई अपने भक्तों कों और वहां वाले आंगतुकों को धुनी की भस्म(ऊदी) को आशीर्वाद के साथ दिया करते थे और उनके सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते थे और वे त्रिकालदर्शी थे. लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते थे, पशु–पक्षियों और अन्य प्राणियों के पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी होती थी. साई ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, वह हमेशा ही प्रसन्न होकर रहता था. साई ने कई अत्यंत रोमांचकारी चमत्कार किए थे. उन्होंने केवल स्वाभाविक रूप से करुणावश चमत्कार किया था. दिखाने के लिए नहीं, जैसा कि आजकल कई संत करते हैं. साई के चमत्कारों तथा भक्तों पर अनुग्रह की ख्याति धीरे–धीरे भारत समेत पूरे विश्व में फैल गई. उन्हें विश्व गुरु स्वीकार किया गया है. साई के शिरडी में रहते समय साठ वर्षों के दौरान हजारों दुखी भक्त और याचक उनकी कृपा पाने के लिए आए थे और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी. महाराष्ट्र के एक महान भक्त श्री दामोलक हेमाडयंत ने साई से प्राथना की थी कि वे उनके दिव्य जीवन, चमत्कारों और उपदेशों पर एक ग्रंथ लिखने की अनुमति दे दें. साई ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा था श्री साई सत् चरित्र लेखक के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा. उसकी भक्ति में दिनों–दिन वृद्धि होगी. जो मेरे चरित्र और कार्यो का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा. साई कहते हैं, जो भक्त उनको हृदय और प्राणों से चाहेगा, उससे वे सदैव प्रसन्न रहेंगे. साई की लीलाओं का जो कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर–संतोष की प्राप्ति हो जाएगी. साई कहते हैं यह मेरा वैशिष्ठय है कि जो कोई अनन्य भाव से ही मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा निरन्तर पूजन, स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. साई कहते हैं कि मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो. सुख और शांति प्राप्ति का सरल मार्ग यही है. केवल साई के उच्चारण मात्र से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे. ■

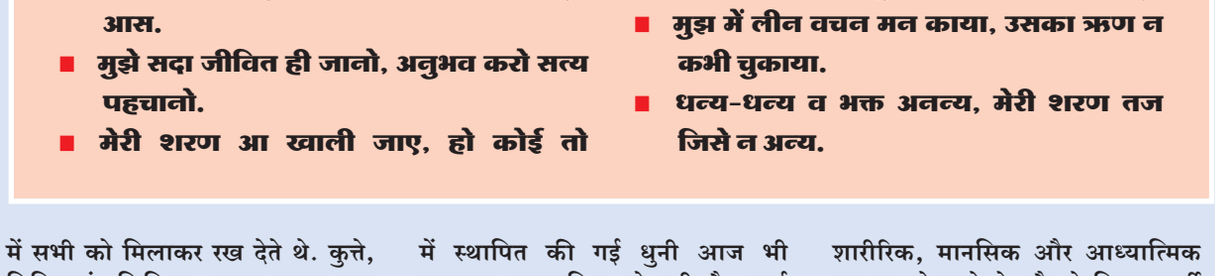

साई के ग्यारह वचन

- जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
- चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
- त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
- मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
- मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
- मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
- जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसै रूप हैं मेरे मन का.
- भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
- आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
- मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
- धन्य–धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, सांई से आप कब और कैसे जुड़े. सांई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. सांई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

भगवान वेंकटेश्वर

चौथी दुनिया ब्यूरो

तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिन्दू मंदिर है. यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है. श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र और प्राचीन मंदिर वेंकटाद्रि नामक पर्वत की सातवीं चोटी पर स्थित है, इसी कारण यहां बाला जी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है. यह मंदिर सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला रहता है. श्रोतों के अनुसार, कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से मुक्ति संभव है. इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50 हजार से भी अधिक लोग दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है और यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है. मंदिर परिसर में अनेक खूबसूरत द्वार, मंडप, छोटे मंदिर और अन्य दर्शनीय स्थल हैं. इस मंदिर और भगवान वेंकटेश्वर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथो में मिलता है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. यहां भगवान के दर्शन के लिए विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है. इसी पर्ची के माध्यम से आप यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं. यहां निःशुल्क दर्शन की भी व्यवस्था है. इस मंदिर में विकलांग लोगों के लिए महाद्वारम नामक मुख्य द्वार से दर्शन की व्यवस्था है, इस द्वार पर उनकी सहायता के लिए सहायक उपलब्ध होते हैं.

पौराणिक कथा

प्रसिद्ध पौराणिक सागर–मंथन की गाथा के अनुसार, जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा चौदह रत्न निकले थे. इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थीं. लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण रूप के कारण देवता, दैत्य, और मनुष्य सभी उनसे विवाह करने के लिए लालायित थे, लेकिन देवी लक्ष्मी को उनमें कोई न कोई कमी लगी. लक्ष्मी ने समीप में खड़े भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी. विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया. यह रहस्य है कि विष्णु जी ने लक्ष्मीजी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया? भगवान विष्णु के हृदय में संसार के पालन के लिए उत्तरदायित्व छिपा था. उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी का निवास वक्षस्थल बना. एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया. तब एक समस्या सामने आई कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए. इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया. भृगु ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा, और शिव जी को यज्ञ के फल हेतु अनुपयुक्त पाया. अंत में भृगु विष्णुलोक पहुंचे. उस समय विष्णुजी शेष शय्या पर लेटे हुए थे और वह को नहीं देख पाए. भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी. अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने विनम्र भाव से उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से बोले. हे ऋषिवर आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न होकर भृगु ने यज्ञ फल के लिए विष्णुजी को उपयुक्त घोषित किया. उस घटना की साक्षी लक्ष्मी जी बेहद क्रुद्ध हो गईं कि विष्णु जी का वक्ष उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर मारने का अधिकार किसने दिया? लक्ष्मीजी को विष्णुजी पर क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने के बजाय उनसे क्षमा क्यों मांगी? परिणामस्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु का त्याग कर चली गई. विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिलीं. विष्णु जी ने लक्ष्मीजी को ढूंढ़ते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के रूप में धरती पर जन्म लिया. संयोगवश लक्ष्मी जी और विष्णुजी का विवाह हुआ, जिसमें सभी देवी–देवताओं ने भाग लिया. भृगु ऋषि ने लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और उन दोनों को आशीर्वाद दिया. लक्ष्मीजी ने भृगु को क्षमा कर दिया. विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मीजी को भेंट करने के लिए विष्णुजी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के अंत तक ब्याज सहित चुकाने का वादा किया. मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में जो भक्त दान करता है, वह हमेशा धन–धान्य से परिपूर्ण रहता है. तिरुपति में केशदान भी किया जाता है. मान्यता है कि केश दान यहां सबसे बड़ा दान है.

तिरुपति बाला जी भारत का एक सुप्रिद्ध तीर्थस्थल है. भगवान वेंकटेश्वर विष्णु जी के रूप हैं. भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से उनके भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. यहां स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति सोना, हीरे और जवाहरात से सुसज्जित है.

श्री पद्मावती मंदिर

तिरुचनूर तिरुपति से पांच किमी दूर है. यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी पद्मावती को समर्पित है. कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक पद्मावती जी के दर्शन नहीं किए जाएं. माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार थे पद्मावती स्वयं लक्ष्मी की अवतार थीं. तिरुमला में सुबह 10.30 से 12.30 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है. यहां दर्शन सुबह 6.30 बजे शुरू हो जाते हैं. तिरुपति से तिरुचनूर के बीच दिन भर बसें चलती हैं.

आकाशगंगा

आकाशगंगा जलप्रपात तिरुमाल मंदिर से तीन किमी दूर उत्तर में स्थित है. इसकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण यह है कि इसी के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है. पहाड़ी से निकलता पानी तेजी से नीचे घाटी में गिरता है. बारिश के दिनों में यहां का दृश्य बहुत मनमोहक हो जाता है.

प्रसाद

यहां प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही–चावल प्रसाद तार्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है.लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहां प्रभु को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं. इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है.

कहां ठहरें

ठहरने के लिए तिरुमाला मंदिर के आस पास रहने के लिए विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशालाएं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. यहां खाने–पीन के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट है, जहां आप दक्षिण भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं.

कैसे पहुंचें

यहां आप ट्रेन, बस और हवाई मार्ग से जा सकते हैं. निकटतम रेलवे स्टेशन तिरुपति जंक्शन है. देश के सभी प्रमुख शहरों से यहां नियमित रूप से ट्रेन आती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

जासूस की चतुराई

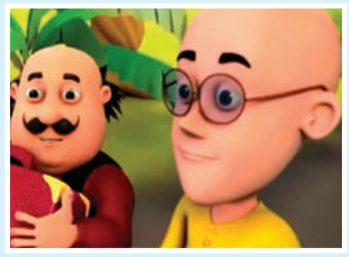

एक बार एक देश के सिपाहियों ने शत्रु देश का एक जासूस पकड़ लिया. जासूस के पास यूं तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, मगर उसके पास स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे मिठाइयों का एक डब्बा जरूर मिला.

सिपाहियों को मिठाइयों को देख लालच आया, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं यह जासूस उसमें जहर मिलाकर तो नहीं लाया है. इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने पहले जासूस को मिठाई खिलाई और जब जासूस ने प्रेमपूर्वक थोड़ी सी मिठाई खा ली तो सिपाहियों ने मिल कर मिठाई का पूरा डब्बा हजम कर लिया और उस जासूस को जेल में डालने के लिए पकड़ कर ले जाने लगे.

इतने में उस जासूस को चक्कर आने लगा और वो उबकाइयां लेने लगा. उसकी इस स्थिति को देख कर सिपाहियों के होश उड़ गए. वह जासूस बोला– लगता है मिठाइयों में धीमा जहर मिला हुआ था. खाने के कुछ देर बाद इसका असर होना चालू होता है. और ऐसा कहते कहते वह जासूस जमीन पर ढेर हो गया. वह बेहोश हो गया था.

सिपाहियों की तो हवा निकल गई. वे जासूस को वहीं छोड़ कर चिकित्सक की तलाश में भाग निकले. इधर जब सभी सिपाही भाग निकले तो जासूस उठ खड़ा हुआ और इस तरह अपने भाग निकलने के मीठे तरीके पर विजयी मुस्कान मारता हुआ वहां से छूमंतर हो गया.

शिक्षा : साहस से काम लें.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

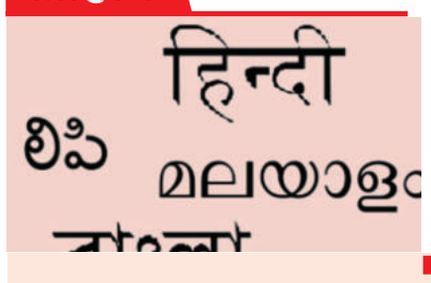

> वैश्विक स्तर पर देखें तो वहां भी अंग्रेजी के वर्चस्व के आगे सैकड़ों भाषाओं पर अस्तित्व का संकट है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2009 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, सबसे खराब हालत भारत में है, जहां 196 भाषाएं मिटने की कगार पर हैं.

कविता

राह से भटकी अकादमियां

बिहार भोजपुरी अकादमी ने मशहूर लोकगायिका मालिनी अवस्थी को अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत बनाने का ऐलान किया तो भोजपुरी भाषा और उसकी राजनीति करने वालों ने खासा बवाल मचाया. गायक मनोज तिवारी ने अकादमी के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया. मालिनी ने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से खत लिखकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मामले का अंत हो गया, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं.

अनंत विजय

हिंदी साहित्य जगत में मासिक पत्रिका हंस के कार्यक्रम के कथिक क्रांतिकारी लेखकद्वय के बहिष्कार के बीच मचे कोलाहल को परिधि पर धकेलकर कुछ दिनों के लिए भोजपुरी साहित्य चर्चा के केंद्र में आ गया था. बिहार की लगभग मृतप्राय भोजपुरी अकादमी को लगा कि वो विवादों के ऑक्सीजन से अकादमी में जान फूंक सकती है. बिहार भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष ने मशहूर लोकगायिका मालिनी अवस्थी को अकादमी का अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत बनाने का ऐलान कर दिया. इस ऐलान के बाद भोजपुरी भाषा और उसकी राजनीति करने वालों ने खासा बवाल मचाया. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके गायक कलाकार मनोज तिवारी ने विरोध को वाणी देते हुए बिहार भोजपुरी अकादमी के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया. भोजपुरी गायक, अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी ने आनन-फानन में भोजपुरी अकादमी के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार का सम्मान लौटाने की भी धमकी दी. इस प्रसंग में मनोज तिवारी और भोजपुरी अकादमी के बीच जमकर बयानों के तीर चले. इस विवाद का अंत किया मालिनी अवस्थी ने. मालिनी ने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से खत लिखकर भोजपुरी अकादमी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. मालिनी ने भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष को लिखा– मैं पूरब की बेटी हूं और पूरब में ही पली-बढ़ी हूं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी की गंगा बहती है. मुझे गर्व है कि मुझे उन्हीं भोजपुरी संस्कारों ने सींचा और निखारा है और लोकप्रियता दिलाई है. महोदय, आपने भोजपुरी के प्रति मेरा समर्पण और योगदान देखकर मुझे बिहार भोजपुरी अकादमी का अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया था, किंतु कुछ व्यक्तियों ने स्वार्थवश इस नियुक्ति पर अकारण सवाल खड़े किए. इस वजह से मेरा अंतर्मन कहता है कि मैं इसके लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले लूं. मालिनी के इस खत ने विवाद का तो पटाक्षेप कर दिया, लेकिन इस विवाद के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो गए.

सबसे बड़ा और अहम सवाल तो बिहार भोजपुरी अकादमी के कामकाज पर खड़ा हो गया है. बिहार भोजपुरी अकादमी ने भोजपुरी भाषा के विकास के लिए अब तक क्या काम किया है, इस बात की पड़ताल होनी चाहिए और उसको सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए. साहित्य जगत को भोजपुरी अकादमी के कामकाज के बारे में ज्ञात नहीं है. भोजपुरी साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी ने क्या कदम उठाए हैं, वह भी भोजपुरी भाषा भाषियों के अलावा गैर भाषा के लोगों को भी पता चलना चाहिए. क्या सिर्फ किसी मशहूर शख्सियत को अकादमी का सांस्कृतिक दूत बनाकर भोजपुरी साहित्य का भला हो सकता है या फिर भोजपुरी साहित्य को विस्तार और नये आयाम मिल सकते हैं, इस बारे में विचार करना होगा. इस पूरे विवाद पर फिल्म समीक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखक विनोद अनुपम ने बेहद सटीक टिप्पणी की. उनका कहना है कि विश्व की किसी भी भाषा के लिए ब्रांड एंबेसडर की परिकल्पना नहीं गई थी. इसके साथ ही विनोद अनुपम ने सवाल भी उठाया कि क्या किसी भी भाषा का विकास ब्रांड एंबेसडर के सहारे हो सकता है. दरअसल, ब्रांड एंबेसडर की नियुक्ति के पीछे भाषा के विकास से ज्यादा प्रचार की लालसा होती है. और उसी लालसा में मालिनी को सांस्कृतिक राजदूत बनाने का फैसला हुआ.

लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन भाषा अकादमियों के कामकाज पर गंभीरता से विचार हो और उनके कर्ताधर्ताओं की जवाबदेही तय की जाए. ये अकादमियां सरकारी कृपापात्रों के

आरामगाह में तब्दील हो चुकी हैं. आजादी के पहले 1944 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में सैद्धांतिक रूप से साहित्यक सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नेशनल कल्चरल ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. आजादी के बाद भारत सरकार ने इस सैद्धांतिक मंजूरी को अमली जामा पहनाने की दिशा में काम करते हुए साहित्य, कला और नाटक के लिए तीन अलग अलग अकादमियों का गठन किया. संसद के सेंट्रल हॉल में जब 12 मार्च, 1954 को साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी तो अपने भाषण में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अकादमी के उद्देश्यों के बारे में कहा था कि साहित्य का उच्चतम स्तर हासिल करना अकादमी का ध्येय होना चाहिए. उसी मौके पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था साहित्य अकादमी उन लोगों का जमावड़ा है जो मौलिक और आलोचनात्मक लेखन में रुचि रखते हैं. भाषा की अकादमियों का गठन एक बेहद पावन उद्देश्य के लिए किया गया था. बाद में केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी भाषा अकादमियों का गठन हुआ. शुरुआत में तो राज्यों की ये भाषा अकादमियां ठीक से काम काज करती रहीं, लेकिन कालांतर में इनके क्रियाकलापों पर राजनीति की छाप पड़ने लग गई. खासकर इमरजेंसी के बाद से इन अकादमियों का राजनीतिकरण शुरू हो गया.

सीपीआई और उसके पिछलग्गू लेखक संगठन प्रलेस ने इमरजेंसी लगाने के इंदिरा गांधी के फैसले को जायज ठहराया और उसे अनुशासन पर्व तक कहकर इंदिरा गांधी का महिमामंडन किया. पुरस्कारस्वरूप इंदिरा गांधी ने साहित्य संस्कृति की कमान कथित प्रगतिवादियों के हाथों में सौंप दी. यहीं से इन अकादमियों के राजनीतिकरण की शुरुआत हुई. अकादमी के अध्यक्ष और अन्य पदों पर इन्हीं प्रगतिवादियों का बोलबाला हो गया. तमाम तरह के पुरस्कार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत लाल झंडा उठाने वाले लेखकों को विदेश यात्रा पर भेजा जाने लगा. अस्सी के दशक में तो दिल्ली स्थित साहित्य अकादमी के प्रांगण में दूसरी विचारधारा के लोगों को तो अस्पृश्य माना जाता था. सालों तक साहित्य अकादमी के पुरस्कार विचारधारा विशेष के लेखकों को दिए गए, चाहे वे किसी भी भाषा के क्यों न हों. केंद्र की अकादमियों में व्याप्त विचारधारावाद का असर राज्य की अकादमियों पर भी हुआ और वहां भी राजनीति शुरू हो गई.

नब्बे के दशक में लालू यादव के शासनकाल में बिहार में साहित्य-संस्कृति नेपथ्य में चले गए. साहित्यक संस्थाओं पर ताले लगने शुरू हो गए. पटना के साहित्य सम्मेलन जैसे साहित्यक केंद्रों पर अपराधियों का कब्जा हो गया. तकरीबन डेढ़ दशक के बाद जब नीतीश कुमार ने सूबे की कमान संभाली तो इन अकादमियों में जान तो वापस लौटी लेकिन अब भी सारी संस्थाएं आईसीयू में वेंटिलेटर पर ही हैं. सुखदा पांडे के संस्कृति मंत्री रहते हुए इस दिशा में कुछ उम्मीद जगी थी, सूबे में सांस्कृतिक हलचलें शुरू हो गई थीं. लेकिन राजनीतिक वजहों से बीजेपी और नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा. इस अलगाव के बाद बिहार में कला और संस्कृति मंत्री का जिम्मा नीतीश कुमार के पास ही है. मशहूर लेखक पवन वर्मा के बिहार के मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं. उनकी नियुक्ति को भी लंबा अरसा हो गया है. पवन वर्मा का ध्यान भी इन मृतप्राय अकादमियों की तरफ नहीं जा पाया है. दरअसल, अगर हम इन भाषा अकादमियों के गठन से लेकर बाद के दो तीन दशक तक देखें तो पाते हैं कि उस दौर के राजनेताओं की भी साहित्य और संस्कृति में रुचि थी. वे खुद भी रचते थे. विमर्श करते थे. लेकिन अब के नेताओं में यह रचने की प्रवृत्ति नहीं बची, जिसकी वजह से उनकी प्राथमिकताओं में अकादमियां रही ही नहीं. अगर कोई शख्स जुगाड़ लगा पाने में कामयाब हो गया तो वह अकादमी का अध्यक्ष तो बन जाता है, लेकिन सरकार से उसे काम करने में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है. सरकारों को साहित्य के प्रति संवेदनशील बनाने का जिम्मा लेखकों को उठाना होगा और लेखक संघों की राजनीति से परे संगठित होना होगा. अगर ऐसा हो पाता है तो साहित्य का भला होगा, नहीं तो इसी तरह से कोई किसी को भी ब्रांड एबेंसडर बनाकर विवाद उठते रहेंगे और अकादमियों की छीछालेदार होती रहेगी. यह स्थिति किसी भी भाषा के लिए अप्रिय होगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

कुछ ऐसा लिख

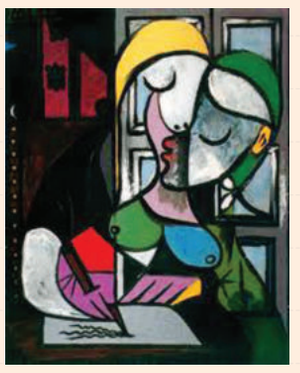

डॉ. सुनीता

समय जब लिख रहा हो
बंटवारे की चिट्ठी
उससे कह देना
करुणा के बजाय कहन का ख्याल रखे

कुछ ऐसा लिखे
दुनिया बदल जाए
लादी धोती स्त्री
बर्तन मांजती मंझवारिन
चक्करघिन्नी सी घूमती धरती
धीरज धरे मगर यातना के विरुद्ध
विद्रोह करने की गुंजाइश रहे

धर्म के नाम पर पाखंडी आवरण ओढ़ती दिन-रातें
उजाले में काजल से काले मन को
बदल सकने के सारे उपक्रम देना
तृप्त करे अतृप्त आत्माओं के अबूझ महल
मर्ज कोई भी हो हल तुम देना

समय की नब्ज अपने हाथ लेना
कोई कुछ भी बोले कुछ न सुनना
बल्कि
मन बहलावे के भड़ुवे से बच के रहना
और बस जीने के हुनर देना

बाकी सब अपने हिस्से रख लेना
यह गुजारिश गरीबों की ही नहीं
डरे-सहमे, स्वर्ग-नर्क की उम्मीद में पले हर किसी की

लघुकथा

औलाद का सुख

तबस्सुम जहां

मैं ने उसकी आंखों को गौर से देखा. आंसू के साथ उसकी पलक का एक बाल भी आंख के कोने में उलझ कर उसकी गर्भ में हो रही पीड़ा में हिलमिल गया था. लगा जैसे उसका अपना अंश ही उसका बैरी हो और वह जल्द से जल्द उसको निकालकर बाहर फेंकना चाहती हो! वह अपनी पीड़ा को दबाते हुए बोली- निगार, असमा के अब्बू ने सख्ती से कहा है कि ऑपरेशन नहीं कराना है... सख्त गुनाह है! आखिर एक यही दौलत तो बख्शी है हमें खुदा ने, आठवां हुआ तो क्या हुआ. जैसे सब पल रहे हैं, वैसे ये भी पल जाएगा...!

हां! पल जाएगा. दस सालों में अब ये आठवां भी... मैंने चिढ़ते हुए कहा- न तन पर पूरे कपड़े, न पेट भर खाना, बच्चे नंगे बदन सर्दी में ठिठुरते रहें या गर्मी में फोड़े फुंसी से सड़ते रहें, आखिर तुम्हारी नज़र में पालने से ज़्यादा ज़रूरी काम पैदा करना है, सही कहा न निगार?

वैसे हैं कहां पर सब बच्चे! क्या स्कूल गए हैं या मदरसे?

निगार कुछ देर के लिए मानो अपना दर्द बिसूर गई और शान से बताने लगी-आतिफ और असलम चाउमीन की रेहड़ी पर हैं. दोनों मिलकर पचास रुपये कमा लेते हैं. और सबा, गुल पड़ोस के घर में रिपिट काटना सीख रही हैं. पांच-पांच रुपये उनको भी शुरुआत में मिलने लगे हैं. फईम, नईम अभी थोड़े छोटे हैं. अक्ल कम है, इसलिए सबा के अब्बू उनको छुन्नू चाय वाले के यहां बर्तन धोने के काम पर लगा आए हैं. अल्लाह का बहुत करम है. सबा के अब्बू को कुछ तो औलाद का सुख मिला! उफ़! मैंने निगार की झुग्गी पर निगाह डाली. तस्त के एक कोने में कुछ बोतलें लुढ़की पड़ी थीं और जिनसे दो साल का भिनकता हुआ सा बच्चा खेल रहा था, जिनकी गंध गटर की बदबू को भी मात कर रही थी. पास ही बड़े मियां भी तहमद ओढ़े उसी गटर में लथपथ औलाद का सुख भोग रहे थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाषाओं पर संकट

आधी सदी में विलुप्त हुईं 250 भाषाएं

कृष्णकांत

कहा जाता है कि यदि किसी सभ्यता अथवा संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दीजिए. भाषा किसी समुदाय विशेष की प्रमुख पहचान होती है, जो कि तेजी से नष्ट हो रही है. वैश्वीकरण ने दुनिया को एक गांव में तब्दील करके हमें सिर्फ फायदे पहुंचाए हों, ऐसा नहीं है. इसने हमसे बहुत कुछ छीना है. छोटी-छोटी संस्कृतियां वैश्वीकरण की धारा में तिनके की तरह बह रही हैं. उनकी बोली-भाषा, उनकी सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान आदि पर गंभीर संकट है. हाल ही में एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले 50 सालों में भारत में 250 भाषाएं नष्ट हो गईं. सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि भाषाएं अलग-अलग वजहों से बड़ी तेजी से मर रही हैं.

भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर नामक संस्था की ओर से भारतीय भाषाओं के लोक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1961 में भारत में 1100 भाषाएं बोली जाती थीं. पिछले 50 सालों के दौरान इनमें से 250 भाषाएं लुप्त हो गई हैं और फिलहाल 850 भाषाएं जीवित हैं. यदि भाषाएं किसी संस्कृति की पहचान से जुड़ी हैं तो यह पहचान तेजी से नष्ट हो रही है.

इससे पहले इस तरह का कोई सर्वेक्षण ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की अगुआई में 1894-1928 के बीच इस तरह का भाषाई सर्वे हुआ था. उसके करीब सौ साल बाद भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर नामक संस्था की ओर से भारतीय भाषाओं का लोक सर्वेक्षण (पीएलएसआइ) किया गया. करीब सदी भर बाद अपने तरह का यह पहला सर्वे है. इसमें कहा गया है कि 1961 में भारत में 1100 भाषाएं बोली जाती थीं. पिछले 50 सालों के दौरान इनमें से 250 भाषाएं लुप्त हो गई हैं और फिलहाल 850 भाषाएं जीवित हैं. वड़ोदरा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके भाषाविद गणेश देवी इस सर्वे के अध्यक्ष हैं. गणेश देवी ने बताया कि हम करीब 780 भाषाओं का अध्ययन कर सके. फिलहाल भारत में करीब 850 भाषाएं जीवित हैं. यदि 1961 की जनगणना को आधार माना जाए तो इन पचास सालों में 250 भाषाएं नष्ट हो चुकी हैं. सर्वेक्षण की प्रासंगिकता के सवाल पर उन्होंने कहा, हर शब्द एक अलग विश्व-दृष्टि पेश करता है. मिसाल के तौर पर हम कितने लाख बार रोए होंगे तो एक शब्द पैदा हुआ होगा आंसू. यह शब्द गया तो हमारी विश्व-दृष्टि भी गई.

हालांकि, इस सर्वे में बोली और भाषा में वर्गीकरण नहीं किया गया है. इस विषय पर गणेश देवी का कहना है कि यह विवाद ही फिजूल है. भाषा सिर्फ भाषा होती है. हम इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं कि जिस भाषा की लिपि नहीं है वह बोली है. विश्व की ज्यादातर भाषाओं के पास लिपि नहीं है. विश्व में कुल छह हजार भाषाएं हैं और 300 से ज्यादा के पास अपनी कोई लिपि नहीं है, लेकिन वे बहुत

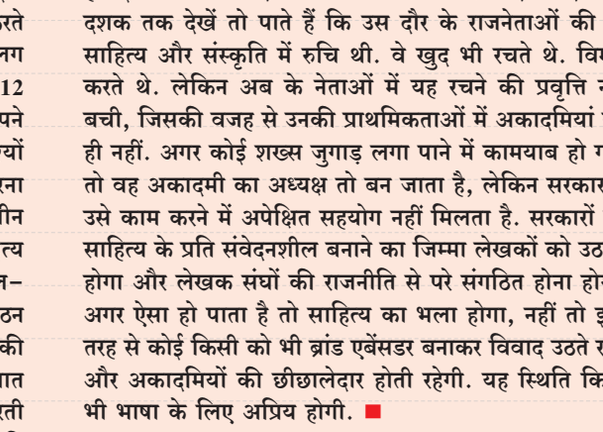

मशहूर भाषाएं हैं. यहां तक कि अंग्रेजी की भी अपनी लिपि नहीं है. वह भी उधार की लिपि यानी रोमन में लिखी जाती है. हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है. देवनागरी में ही संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भी लिखी जाती हैं. यानी भाषा की अपनी लिपि होनी जरूरी नहीं है. कुछ विद्वान इसकी परिभाषा देते हैं कि जो भाष कराए, वही भाषा है. उसका लिखा जाना जरूरी नहीं है. वेदों के बारे में भी कहा जाता है कि वह बोला हुआ ज्ञान है. श्रुति है. वह पढ़ा अथवा लिखा हुआ ज्ञान बाद में बना. गणेश देवी का कहना है कि इन सैकड़ों भाषाओं के करोड़ों शब्दों की विश्व दृष्टि को अगली पीढ़ी को सौंपने के उद्देश्य से हमने यह सर्वे किया. इसमें सरकार की कोई मदद नहीं ली गई. करीब तीन हजार स्वयंसेवियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, लेखकों, किसानों, बनजारों आदि की सहायता से यह सर्वेक्षण पूरा किया गया. इसे शिक्षक दिवस के रोज 68 खंडों में करीब 35 हजार पन्नों की रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा.

सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब चार सौ भाषाएं ऐसी हैं, जो घुमंतू, आदिवासी और गैर-अधिसूचित जातियां द्वारा बोली जाती हैं. सर्वेक्षण में जिन 780 भाषाओं का अध्ययन किया गया, उनमें से 400 भाषाओं का व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किया गया है. गणेश देवी का कहना है कि यह सर्वेक्षण किसी भाषा के नष्ट होने का रोना रोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विविधता का उत्सव मनाने के लिए किया गया है. अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. अरुणाचल में 90 भाषाएं बोली जाती हैं. दादर और नागर हवेली में गोरपा नाम की एक भाषा मिली, जिसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है. हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग चालीस करोड़ है, जबकि सिक्किम में माझी बोलने वालों की संख्या सिर्फ चार है. इस सर्वेक्षण में उन भाषाओं को भी शामिल किया गया, जिन्हें बोलने वालों की संख्या दस हजार से कम है. सर्वेक्षण में इन भाषाओं को शामिल करने करने के पीछे देवी ने तर्क दिया कि बांग्लादेश युद्ध के बाद भाषाई संघर्ष की संभावनाओं को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत उन भाषाओं को जनगणना में शामिल करना बंद कर दिया गया, जिन्हें बोलने वालों की संख्या दस हजार से कम हो. यही वजह है कि 1961 की जनगणना में 1652 भाषाओं का जिक्र है, जबकि 1971 में यह घटकर 182 हो गई और 2001 में 122 रह गई. सर्वेक्षण में ऐसा माना गया कि 1961 की जनगणना में जिन 1652 भाषाओं को जिक्र है, उनमें से अनुमानतः 11 सौ को भाषा का दर्जा दिया जा सकता है. भारत सरकार की तरफ से 2006-07 में भारतीय भाषाओं पर सर्वेक्षण कराए जाने की पहल हुई थी, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी.

वैश्विक स्तर पर देखें तो वहां भी अंग्रेजी के वर्चस्व के आगे सैकड़ों भाषाओं पर अस्तित्व का संकट है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2009 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, सबसे खराब हालत भारत में है जहां 196 भाषाएं मिटने की कगार पर हैं, इसके बाद अमेरिका का स्थान है, जहां 192 भाषाएं विलुप्तप्राय हैं. इंडोनेशिया में भी 147 भाषाएं मिटने वाली हैं. दुनिया में 199 भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या दस से भी कम है. 178 भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें बोलने वालों की संख्या 150 लोगों से भी कम है. एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में 6900 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 2500 भाषाओं की स्थिति चिंताजनक है. यदि भाषा संस्कृति का आधार है तो इन भाषाओं के नष्ट होने के साथ ये संस्कृतियां भी नष्ट हो जाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

दुनिया भर में करोड़ों लोग एसएमएस की जगह व्हाट्स ऐप का इस्तेमाल एक-दूसरे को संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं. इसके अलावा, एमएमएस, ऑडियो संदेश आदि भी इसके जरिये काफी तेज गति से भेज सकते हैं.

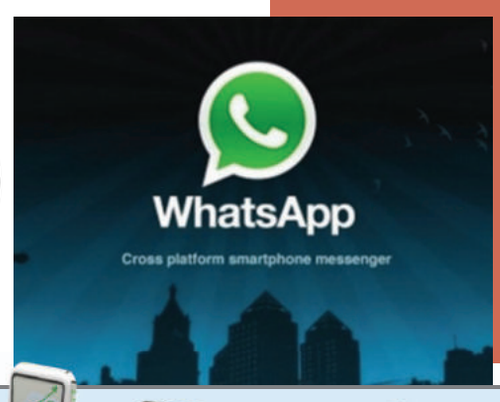

मोबाइल ऐप्स से बनाइए लाइफ आसान

मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि ऐप्लिकेशंस के कारण यह अब आपके लिए कई तरह से सुविधाजनक हो गया है. दुनिया भर में मौजूद स्मार्टफोन्स के करोड़ों यूजर्स के बीच एप्लिकेशंस काफी लोकप्रिय हैं. इन्हें आप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं. इन ऐप्लिकेशन में गेम्स से लेकर आपके फाइनांशियल, हेल्थ और पर्सनल प्लानर तक शामिल हैं. ऐप्लिकेशंस को सबसे पहले एपल ने आईफोन में पेश किया था. फिलहाल एपल के एप स्टोर में करीब सवा दो लाख ऐप्लिकेशंस मौजूद हैं. अब तक पांच अरब से ज्यादा ऐप्लिकेशंस डाउनलोड हो चुके हैं. दूसरे नंबर पर गूगल का एंड्रॉयड ऐप स्टोर है, जहां करीब 70 हजार एप्स हैं. इनके अलावा, नोकिया का सिंबियन, विंडोज, ब्लैकबेरी ओएस में भी ढेरों सारे ऐप्लिकेशंस मौजूद हैं. ■

गूगल मैप्स

Google maps

गूगल मैप्स दुनियाभर में 55 प्रतिशत से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स की पहली पसंद है. इस ऐप्लिकेशन के जरिए आपको कही जाने के लिए किसी से कुछ पुछने की जरूरत नहीं है, जगह खोजना, डायरेक्शन, ट्रैफिक और सर्च जैसी तमाम जानकारियां इसी में मिल जाएंगी. आपको यह भी पता चल जाएगा कि किसी एक जगह से दूसरी जगह किन साधनों से जाया जा सकता है. रूट क्या है और जाने में कितना समय लगेगा. ■

वीचैट

WeChat

पूरी दुनिया में 27 प्रतिशत यूजर्स वीचैट का इस्तेमाल करते हैं. इसमें ऑडियो वीडियो और ग्रुप चैटिंग किया जा सकता है. इस एप्लिकेशन के जरिए आप लाइव चैट, ग्रुप चैट, पुश टु टॉक सुविधा और वीडियो कॉलिंग सुविधा का फायदा भी उठा सकते हैं. इस एप्लिकेशन का लाभ लगभग सभी तरह के मोबाइल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर उठाया जा सकता है. इस एप्लिकेशन में एक शेक फीचर भी होता है, जिसकी मदद से आप नए दोस्त बना सकते हैं. ■

हाइक

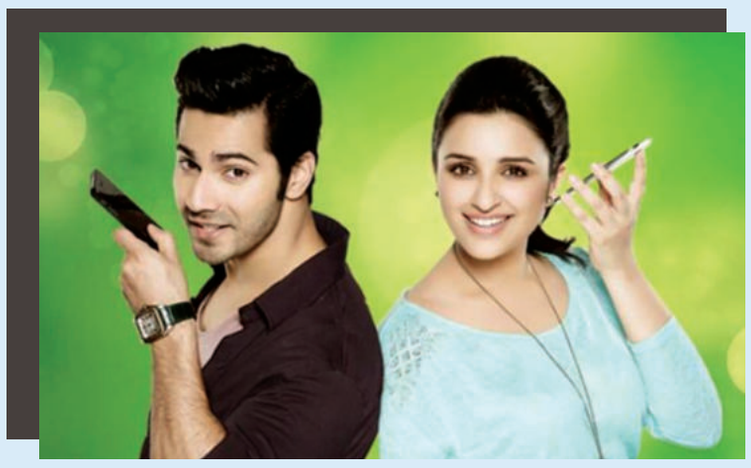

hike

इसके फीचर्स व्हाट्स एप्प जैसे ही हैं. इसकी खासियत यह है कि जो लोग हाइक से नहीं जुड़े हैं, उनको भी इसके जरिये एसएमएस भेजा जा सकता है. इसमें वॉकी-टॉकी की भी सुविधा दी गई है. ■

व्हाट्स ऐप

व्हाट्स ऐप की लोकप्रियता हाल के दिनों में काफी तेजी से बढ़ी है. अब दुनिया भर में करोड़ों लोग एसएमएस की जगह इसका इस्तेमाल एक-दूसरे को संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं. इसके अलावा, एमएमएस, ऑडियो संदेश आदि भी काफी तेज गति से भेज सकते हैं. व्हाट्स एप्प की सुविधा ब्लैकबेरी, नोकिया, विंडोज फोन और आईफोन के साथ ही सभी एंड्रॉयड फोन्स पर दिए जा रहे हैं. ■

स्नैपटू

यह ऐप्लिकेशन आपको हर जगह फेसबुक, ट्विटर, मौसम का हाल, टॉप न्यूज से लेकर जीमेल तक ढेरों फीचर देता है. इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें अपनी जरूरत के टूल जोड़ सकते हैं. ■

लुकआउट

यह ऐप्लिकेशन आपके मोबाइल के लिए एंटी-वायरस और डेटा बैकअप के अलावा फोन खो जाने पर ढूंढने का काम भी करता है. फोन खो जाए तो आप लुकआउट की साइट पर जाकर उसे लोकेट कर सकते हैं, लेकिन फोन ऑफ होने पर यह काम नहीं करता. ■

ड्राइव सेफ्टी

ड्राइविंग के दौरान यह ऐप आपके फोन पर आने वाले हर एसएमएस और ई-मेल को जोर से पढ़कर सुनाता है. इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सेटिंग करनी होगी कि किस तरह की आवाज में आप सुनना चाहते हैं, आवाज कितनी तेज रखनी है, बोलने की स्पीड कैसी हो और क्या-क्या पढ़कर सुनाया जाए. इसकी सबसे बड़ी खासियत टेक्स्ट पढ़ने की क्लियरिटी है, यानी आप जब ड्राइव कर रहे हैं और इसे ऑन कर दें तो मेसेज या ई-मेल पढ़ने के लिए फोन छूने की जरूरत भी नहीं.

ब्लैकट्रैक

यह ऐप्लिकेशन आपकी प्रोडक्टिविटी सुधारने के लिए है. यह आपकी फोन और ई-मेल एक्टिविटी का सारा लॉग आपको मुहैया कराता है, यानी इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि किस काम में आपका कितना टाइम लग रहा है. जब आप काम कर रहे होते हैं तो यह किसी तरह के पॉप-अप या टैग से आपको डिस्टर्ब नहीं करता. साइलेंटली यह यह आपके काम की रिपोर्ट बनाता है और डेली व वीकली आपको मेल कर देता है. यह पूरी तरह सिक्योर है, क्योंकि इसमें कोई वेबसाइट या सर्वर यूज नहीं होता.

स्काइप

ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के लिए यह स्काइप एक बेहद लोकप्रिय एप्लिकेशन है. इसके जरिये दुनिया भर में बातचीत किया सकता है. इस एप्प के जरिए ऑडियो-वीडियो चैट के साथ ही टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं. इसके द्वारा आप कॉन्फ्रेंस कॉल, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. इसकी ऑडियो-वीडियो, मैसेज चैटिंग सेवा तो मुफ्त है, लेकिन किसी लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर पर फोन करने के लिए शुल्क देना पड़ता है. स्काइप का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड, विंडोज, ब्लैकबेरी, आईओएस फोन या विंडोज और मैक आधारित कंप्यूटर, लैपटॉप पर भी कर सकते हैं. ■

skype™

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मिरर इन योर पॉकेट

यह ऐप्लिकेशन आपके फोन को आइने में बदल देता है. कभी जब आप बाहर हों और आइने की जरूरत पड़ जाए तो, इस ऐप को ऑन कर स्क्रीन को मिमर के तौर पर इश्तेमाल कर सकते हैं. ■

रन कीपर

जॉगिंग पर जाते समय इसे ऑन कर दीजिए. जीपीएस डेटा की मदद से यह पता लगाएगा कि आपने कितनी दूरी कवर की, आपकी स्पीड क्या रही और आपने इस दौरान कितनी कैलरी बर्न की. इसके अलावा, मैप पर यह आपका रूट भी आपको दिखा देगा. ■

टैंगो

इस एप्लिकेशन में पुश टु टॉक फीचर होता है, जिसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन को वॉकी-टॉकी में बदल सकते हैं. यह सुविधा आपको एंड्रॉयड आधारित फोन, विंडोज फोन और आईओएस आधारित फोन पर मिल सकती है. ■

निम्बज

इसकी सहायता से मुफ्त कॉल कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं. स्काइप की तरह इसमें दुनिया भर के लैंडलाइन और अन्य मोबाइल नंबर पर भी कॉल करने की सुविधा होती है, जिसे निम्बज आउट सर्विस कहते हैं. ■

गूगल हैंगआउट

इस पर भी मुफ्त में वीडियो कॉल या चैटिंग की सुविधा है, जिसे गूगल प्लस हैंगआउट कहते हैं. इसकी सहायता से किसी एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या चाहें तो ग्रुप चैट भी कर सकते हैं. ग्रुप चैट में अधिकतम 10 लोगों को शामिल किया जा सकता है. यह ऐप एंड्रॉयड 2.3 या उससे ऊंचे वर्जन को ओएस का इस्तेमाल करने वाले सभी फोन पर चलता है. ■

वाइबर

इसके जरिये मुफ्त कॉल के साथ टेक्स्ट भेज सकते हैं. इसमें अलग से यूजरनेम बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ही आपके आईडी का काम करता है. इंस्टॉल करने के बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिंक करके स्वत: ही यह बता देता है कि और कौन-कौन से लोग वाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं. वाइबर का फायदा एंड्रॉयड, आईओएस आधारित फोन, नोकिया, ब्लैकबेरी फोन, विंडोज फोन और मैक या विंडोज आधारित कंप्यूटर व लैपटॉप पर किया जा सकता है. ■

Viber

फ्रिंग -

इससे फ्री कॉल कर सकते हैं. इसमें भी ग्रुप कॉल की सुविधा होती है, जिसमें एक साथ चार लोगों को शामिल किया जा सकता है. स्काइप की तरह की फ्रिंग में लैंडलाइन या मोबाइल नंबरों पर भी कॉल करने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए शुल्क देना पड़ता है. इस ऐप्लिकेशन का फायदा एंड्रॉयड, आईओएस आधारित फोन या नोकिया के स्मार्टफोन पर लिया जा सकता है. ■

इंस्टाग्राम -

इंस्टाग्राम फेसबुक के तहत काम करने वाला पिक्चर एप्लीकेशन है. इस ऐप्लिकेशन का प्रयोग दुनिया भर में किया जाता है. ■

डाउनलोड कैसे करें -

हर स्मार्टफोन में उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े ऐप्लिकेशन स्टोर का लिंक होता है. इसे आप वाई-फाई, जीपीआरएस या एज से कनेक्ट कर सकते हैं. ऐप्लिकेशन भले ही फ्री हैं, लेकिन इसमें डाउनलोड करने पर डेटा यूसेज का खर्च आपको चुकाना पड़ सकता है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> भारत एक विकासशील देश है. साथ ही यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. इसलिए खेलों के विकास के लिए जब तक देश में कोई ठोस खेल नीति नहीं बनेगी, कोई रोडमैप नहीं बनेगा, तब तक खेल और खिलाड़ी बदहाल ही रहेंगे. वर्ष 2007 में तत्कालीन खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हम जल्दी ही एक समग्र खेल नीति का मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश कर रहे हैं.

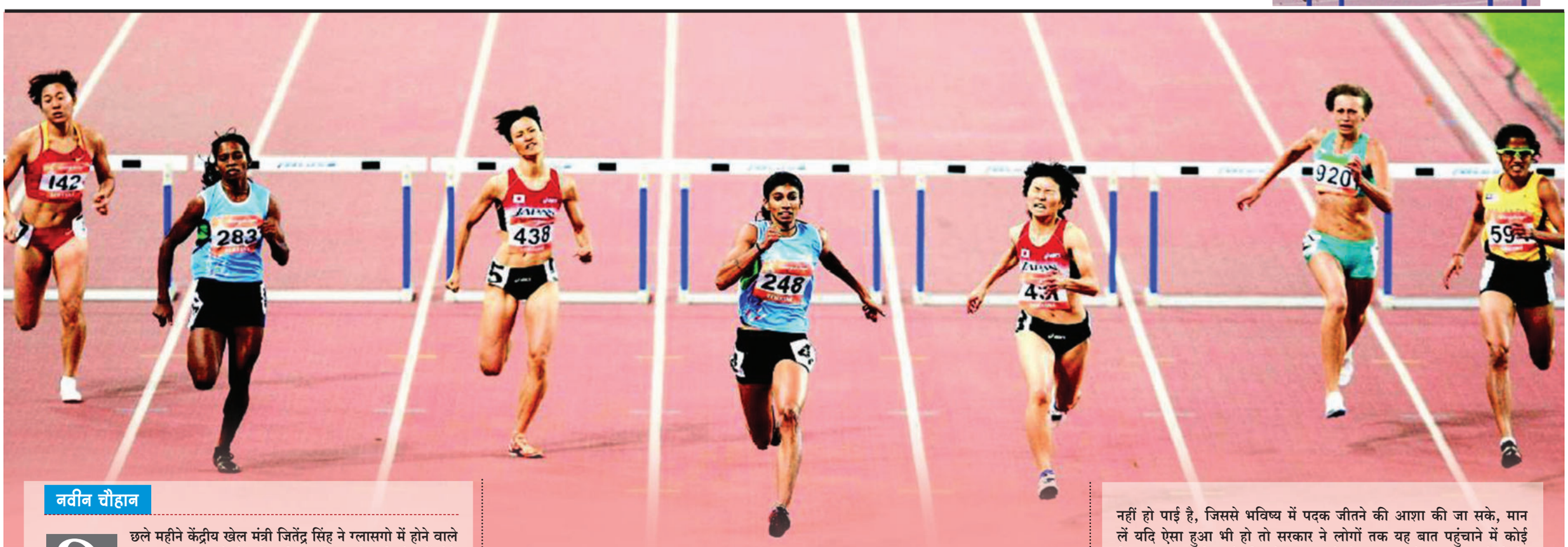

खेलों का बंटाधार

नवीन चौहान

पिछले महीने केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्लासगो में होने वाले 2014 राष्ट्रमंडल खेलों और दक्षिण कोरिया के इंचियोन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए हो रही तैयारियों से नाखुशी जाहिर की थी. उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि महज कुछ खेल महासंघों ने ही इन खेलों की तैयारियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा दिया है. मंत्रालय ने खेल महासंघों से संभावित पदक विजेताओं की सूची भी बनाने को कहा था, लेकिन इस दिशा में भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है. देश के खेल मंत्री द्वारा खेल की तैयारियों को लेकर इस तरह नाराज़गी जताने का यह कोई पहला वाकया नहीं है. इस तरह के खेलों को लेकर तैयारियों का अब तक आलम कुछ ऐसा ही रहा है. केंद्र सरकार के पास खेलों के विकास को लेकर न तो कोई व्यापक नीति है, न ही कोई ऐसा रोडमैप, जिस पर खेल मंत्रालय काम कर रहा हो. खेलों के क्षेत्र में तो भारत सरकार को आग लगने पर कुंआ खोदने की याद आती है. राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के आयोजन में महज एक साल का वक्त बचा है. ऊपर से देश में आम चुनाव सिर पर है. देश के अधिकांश खेल महासंघों के मुखिया संसद में बैठे लोग ही हैं, जिन्हें खिलाड़ियों के पदक जीतने से ज्यादा अपनी सीट बचाने की चिंता है. खेल महासंघों के लोग संभावित पदक विजेता खिलाड़ियों से ज्यादा विजयी हो सकने वाले लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर स्वयं को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं. ऐसे में उन्हें देश के गौरव, खेलों और खिलाड़ियों की सुध कैसे रहेगी.

वैसे भी भारत आईओए (अंतराष्ट्रीय ओलंपिक संघ) के निलंबन का सामना कर रहा है. हाल ही में चीन में संपन्न हुए दूसरे युवा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी स्वतंत्र ओलंपिक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए, जिसमें भारोत्तोलन टीम में शामिल आठ खिलाड़ी निर्धारित उम्र से अधिक के निकले. इससे देश में खेल महासंघों के काम करने के तरीके का खुलासा हो जाता है, जिन्हें न तो खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता है, न ही निलंबन की. इसी तरह हॉकी इंडिया ने हाल ही में हुए एशिया कप में भाग लेने के लिए जो टीम भेजी, उस टीम के साथ कोई डॉक्टर नहीं गया था. प्रतियोगिता के पहले मैच से पहले कप्तान सरदार सिंह को बुखार आ गया. ऐसे में टीम के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जिससे की सरदार जल्दी ठीक होकर टीम की कमान संभाल पाते. देश में जितने भी खेल महासंघ हैं, उनमें से अधिकाश में नेताओं की तानाशाही चल रही है. वो उसे बपौती मानकर अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं. जो वित्तीय सहायता खेल प्राधिकरणों को मिलती है, उसका उपयोग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से ज्यादा मैनेजमेंट के खर्च में व्यय होता है. इस वजह से खिलाड़ी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

भारत एक विकासशील देश है. साथ ही यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. इसलिए खेलों के विकास के लिए जब तक देश में कोई ठोस खेल नीति नहीं बनेगी, कोई रोडमैप नहीं बनेगा, तब तक खेल और खिलाड़ी बदहाल ही रहेंगे. वर्ष 2007 में तत्कालीन खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हम जल्दी ही एक समग्र खेल नीति का मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश कर रहे हैं. इस नई खेल नीति में ग्रामीण इलाकों के युवाओं को अधिक संख्या में शामिल करने और उन्हें कई तरह के खेलों के लिए तैयार करने पर बल दिया जाएगा. मौजूदा समय में युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र सरकार का कार्य केवल बड़ी खेल स्पर्धाओं के आयोजन तक सीमित है. ग्रामीण इलाकों में युवाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है. शहरी इलाकों में रहने वाले पांच करोड़ युवाओं को ही केवल खेल सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, जबकि 72 करोड़ युवा इन सुविधाओं से वंचित हैं. इस असंतुलन को सुधारना होगा. अब तक शहरों से ही खिलाड़ी निकल कर आते रहें हैं, लेकिन गांवों में भी प्रतिभा छिपी हुई है और हम चाहते हैं कि वे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें.

केंद्र की यूपीए सरकार ने पंचायत के अंतर्गत ग्रामों में खेलों के विकास के लिए अप्रैल 2008 में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान की शुरुआत की. इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के निर्माण के लिए एक मुश्त 1 लाख रुपये, और ब्लॉक पंचायत के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया. इस योजना के अंतर्गत हर साल देश के 10 प्रतिशत ग्रामों में इस योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य भी रखा गया. केंद्र सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. कई राज्यों में मैदान के निर्माण की योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से भी जोड़ा गया. योजनानुसार पिछले चार वर्षों में हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अब तक देश के 40 से 45 प्रतिशत गांवों में, मतलब लगभग 3 लाख गावों में मैदानों का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर है. विडंबना तो यह है कि ग्रामाणों को इस योजना के बारे में जानकारी भी नहीं है. इसके अलावा इस योजना में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के उद्देश्य से हर वर्ष पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने करने की बात भी अभियान में शामिल की गई थी, लेकिन योजना के लागू होने के चार साल गुजर जाने के बाद भी इस रास्ते से होकर गुजरे किसी भी प्रतिभावान खिलाड़ी की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे भविष्य में पदक जीतने की आशा की जा सके, मान लें यदि ऐसा हुआ भी हो तो सरकार ने लोगों तक यह बात पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. पिछले दस सालों से हर साल केंद्र सरकार खेलों के विकास के लिए औसतन 1336 करोड़ रुपये मुहैया करा रही है. यूपीए-1 सरकार ने वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक हर वर्ष औसतन लगभग 605 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि यूपीए-2 के दौरान औसतन 2066 करोड़ रुपये खर्च किए गए. यूपीए 2 के कार्यकाल में कुल 10331 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें से अधिकांश फंड की दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर बंदरबांट हो गई. कॉमनवेल्थ खेलों का बजट भी कई गुना ज्यादा हो गया. कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से चंद घंटों पहले तक तैयारियां पूरी नहीं की जा सकी थीं. जैसे-तैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कॉमनवेल्थ खेलों का सफल आयोजन कर लिया, लेकिन इसके राष्ट्रमंडल खेल घोटाले का खुलासा हुआ और जो बदनामी विश्व भर में हुई, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी. इसके बाद खेल मंत्री के रूप में अजय माकन ने खेलों में सुधार लाने के अथक प्रयास किए, लेकिन स्पोर्ट्स कोड को लेकर खेल प्राधिकरणों और खेल मंत्रालय के बीच में विवाद बना रहा. कैबिनेट ने माकन के स्पोर्ट्स बिल को खेल मंत्रालय के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया. इसके बाद सरकार ने अफरातफरी में स्पोर्ट्स कोड 2011 लागू कर दिए और सभी खेल संस्थानों को इनका पालन करने के लिए बाधित किया. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इसे ओलंपिक चार्टर के अनुसार सरकारी दखल माना और इंडियन ओलंपिक ऐसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी. सरकार यहां भी बचाव नहीं कर पाई.

कुल मिलाकर केंद्र सरकार और खेल प्राधिकरणों के बीच पैसे के लेन-देन का खेल चल रहा है. हर साल खेल मंत्रालय केंद्र सरकार से मान्यताप्राप्त खेल प्राधिकरणों को खेलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. केंद्र सरकार ने 53 राष्ट्रीय खेल प्राधिकरणों (नेशनस स्पोर्ट्स फेडरेशंस) को मान्यता दी है. खेल मंत्रालय इन सभी फेडरेशंस को हर साल औसतन लगभग 100 करोड़ रुपये मुहैया कराता है. इन्हीं सौ करोड़ रुपये की मारामारी में खेलों का वजूद राजनीति और राजनीतिज्ञों के पैरों तले कुचला जाता है. ऐसे तो औसतन प्रत्येक स्पोर्ट्स फेडरेशन को लगभग 2 करोड़ रुपये सलाना मिलते हैं, यह राशि देश की बड़ी जनसंख्या के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह भी जरूरतमंद खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाता है. अफ्रीकी देश नाइजीरिया की सरकार ने वर्ष 2008 में बीजिंग में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों के बाद वर्ष 2009 में उनके यहां खेलों को बढ़ावा देने और विश्वपटल पर सफल होने के उद्देश्य से विजन 2020 नाम से एक खेल नीति बनाई. इस खेल नीति में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए निकट और दूरगामी लक्ष्यों को जोड़ा गया है. साथ ही नाइजीरिया में खेलों के विकास और लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश की जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है. जमैका जैसा छोटा सा कैरेबियाई देश हर बार भारत जैसे विशाल देश से ज्यादा पदक ओलंपिक और अन्य स्पर्धाओं में जीत लेता है. आर्थिक मामले में वह हमसे बहुत पीछे है. शायद हमारी सरकारों ने इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया. भारत में पहली खेल नीति 1984 में लागू की गई थी, उसी दौरान चीन ने भी खेलों में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर एक योजना के तहत कार्य करना शुरू किया. आज चीन खेलों के मामले में कहां है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है. देश की पहली खेल नीति लागू होने के 29 साल बाद भी हम खेलों में सफलता की राह में चंद कदम ही चल पाए हैं. इसका एक ही कारण है भारत में खेलों को लेकर कोई विजन, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिस पर गंभीरता से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और खेल प्राधिकरण मिलकर काम कर रहे हों. खेलों को हमारे समाज और सरकार दोंनों ने ही गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज हम एक ओलंपिक पदक के लिए भी मोहताज हैं. ये बात और है कि हम लंदन ओलंपिक में छह पदक जीतने में कामयाब हुए हों. यदि हमने मिल-जुलकर और भविष्य को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य निर्धारित करके कार्य नहीं शुरू किया तो हमें अर्श से फर्श पर आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी. इसके बाद हम लकीर ही पीटते रह जाएंगे.■

navinchauhan@chauthiduniya.com

खेलों के मायने बदल रहे हैं. खेल अब महज मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि, स्वस्थ और समृद्ध देश का प्रतीक भी बन गया है. खेलों को अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता है. इसलिए अगर खेल के साथ खिलवाड़ होता है तो यह खेल की आत्मा को तो प्रभावित करता ही है, देश की साख पर भी चोट पहुंचाता है.

खेलों के विकास के लिए बज़ट में किए गए प्रावधान

वर्ष	बजट	राष्ट्रीय खेल प्रधिकरणों को वित्तीय सहायता	पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान	अरबन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम	स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया	नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड (सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)
2008-09	890	092				
2009-10	3670.13	135	15			
2010-11	3315.67	112	350	150	1175.54	8.12
2011-12	1121	100	165	35	236	0.00
2012-13	1152	110	235	14.5	256	5.00
2013-14	1219	160	180	45	326	5.00

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
09 सितंबर–15 सितंबर 2013

फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख नॉर्थ इंडियन के किरदार में थे. वहीं दीपिका साउथ इंडियन लड़की की भूमिका में थीं. वह पूरी तरह साउथ गर्ल की गेटअप में नज़र आईं. सिर्फ़ भाषा ही नहीं बल्कि, उन्होंने पूरी फिल्म में कपड़े भी वहीं के पहने हैं.

उत्तर की फिल्मों में दक्षिण का मसाला

मुंबइया फिल्में देख-देख कर ऊब चुके दर्शकों को साउथ की संस्कृति, रहन-सहन और नाच-गाना काफ़ी भा रहा है. फिल्मकारों को भी वहां के खूबसूरत लोकेशन में आसानी से शूटिंग करने की अनुमति मिल जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड में इन दिनों साउथ का प्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़ रहा है.

प्रियंका तिवारी

कुछ सालों से हिंदी फिल्मों में साउथ के स्पाइस का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है. आजकल साउथ की फिल्मों की रीमेक से लेकर पूरी की पूरी फिल्म ही साउथ में बनाई जाने लगी है. साउथ और नॉर्थ दोनों ही कल्चर को मिक्स करके फिल्में बन रही हैं. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रांझना में सोनम कपूर बनारस की एक मुस्लिम लड़की के किरदार में दिखीं, तो वहीं साउथ के स्टार धनूष एक साउथ इंडियन बनारसी के किरदार में दिखे. हालांकि पहले की फिल्मों को देखें तो कॉमिक रिलीज के लिए साइड हिरो का किरदार साउथ का पात्र चुना जाता था, लेकिन अब कि फिल्मों में फिल्म के लीड हीरो या हिरोइन को ही साउथ के कैरेक्टर के रूप में पेश किया जाने लगा है. साउथ का रहन-सहन और खान-पान पहले भी दर्शकों को आकर्षित करता रहा है. इसीलिए फिल्मकार फिल्मों में दक्षिण का तड़का डालते रहे हैं. दरअसल, साउथ का नाच गाना, कल्चर, ऐक्शन, ओवर ऑल मसाला मेलोड्रमा दर्शकों को इन दिनों खूब भा रहा है. 90 के दशक के बाद ऐक्शन फिल्मों का दौर लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन अब साउथ की फिल्मों की रीमेक या पटकथा पर आधारित फिल्मों के ज़रिए एक बार फिर से ऐक्शन फिल्मों का दौर भी लौट आया है, जो दर्शकों को खुब पसंद आ रहा है. इसकी शुरुआत आमिर की फिल्म गजनी और सलमान की वॉन्टेड से हुई, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया.

हाल ही में रिलीज हुए फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख नॉर्थ इंडियन किरदार में थे. वहीं दीपिका साउथ इंडियन लड़की की भूमिका में थी. वह पूरी तरह साउथ गर्ल की गेटअप में नज़र आईं. सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी फिल्म में कपड़े भी वहीं के पहने हैं. हालांकि शाहरुख पहले भी साडथ इंडियन किरदार में नज़र आ चुके हैं. शाहरुख फिल्म रावन में साउथ के विडियो गेम डिजाइनर शेखर सुब्रमण्यम के किरदार में दिखे. वहीं अपनी फिल्म ओम शांति ओम में वह साउथ के फिल्मस्टार्स की मिमिक्री करते नज़र आए थे. बालीवुड में ऐसे कई स्टार हैं, जिन्होंने साउथ इंडियन किरदार निभाएं. जिन्हें जहां मौक़ा मिला, वहीं उसने दक्षिण भारतीय किरदार अपना लिया. अमिताभ, मिथुन से लेकर महमूद तक सबने साउथ का रोल किया. महमूद के लिए तो साउथ इंडियन किरदार उनकी पहचान ही बन गई. 1965 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म गुमनाम में साउथ इंडियन के रोल में महमूद कॉमेडी करते नज़र आए. गुमनाम के बाद पड़ोसन में भी महमूद एक साउथ इंडियन डांस टीचर के किरदार में नज़र आए. एक और फिल्म दो फूल में भी वह साउथ इंडियन किरदार में काफ़ी हिट रहे. साउथ के ये रोल फिल्मों में इतने कामयाब रहे कि फिल्मकारों को मजबूर होना पड़ा बार-बार महमूद को साउथ इंडियन के रोल में कास्ट करने के लिए. 1982 में आई फिल्म देशप्रेमी में अमिताभ डबल रोल में नज़र आए. इस फिल्म में कोई साउथ इंडियन किरदार तो नहीं था, लेकिन फिल्म में अमिताभ उनकी पत्नी बनी हेमा मालिनी के सामने साउथ इंडियन के रोल में आते हैं और गाना भी गाते हैं. 1990 आई फिल्म अग्निपथ में मिथुन चक्रवर्ती कृष्णा अय्यर एमए की भूमिका में नज़र आए. यह किरदार काफ़ी हिट हुआ था. बड़े से लेकर छोटे स्टार तक सभी ने साउथ इंडियन किरदार निभाए हैं, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी नहीं होती थी, ये सिर्फ़ एक कॉमिक रिलीज के लिए इश्तेमाल होते थे, जिससे फिल्म को एक अलग रंग दिया जा सके.

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में एक्टर-एक्ट्रेस और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर्स का हमेशा से आदान प्रदान होता रहा है, लेकिन एक वक्त आया जब साउथ के फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने विरासत, डोली सजा के रखना, सात रंग के सपने जैसी फिल्मों को हिंदी में रीमेक किया. उस वक्त इन फिल्मों को ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2002 में एक मलयालम फिल्म रामजी राव स्पिकिंग को हिंदी में हेराफेरी के नाम से

90 के दशक के बाद बॉलीवुड में ऐक्शन फिल्मों का दौर लगभग ख़त्म सा हो गया था, लेकिन अब साउथ की फिल्मों की रीमेक या पटकथा पर आधारित फिल्मों के ज़रिए एक बार फिर से ऐक्शन फिल्मों का दौर लौट आया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इसकी शुरुआत आमिर की गजनी और सलमान की वॉन्टेड से हुई.

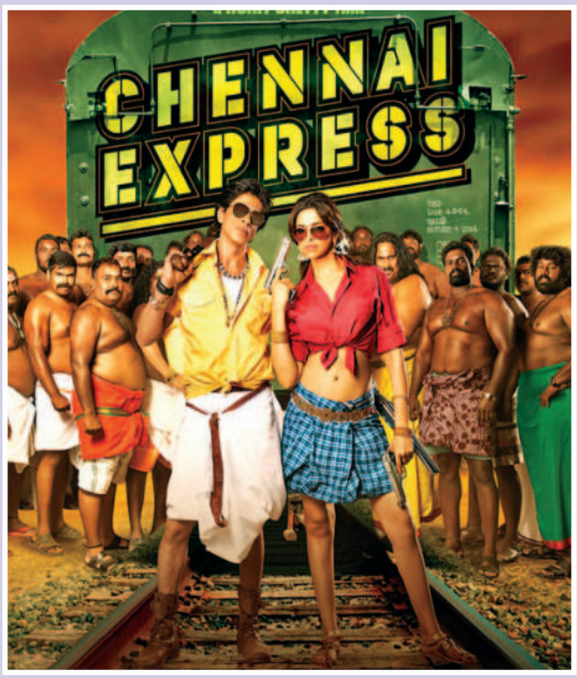

बनाया गया तो यह फिल्म न सिर्फ सुपरहिट हुई, बल्कि अक्षय कुमार को सुपरस्टार का दर्जा भी मिला. तुषार कपूर का डेब्यू भी साउथ की रीमेक मुझे कुछ कहना है से हुआ था. यह फिल्म भी सुपरहिट रही. डायरेक्टर सतीश कौशिक ने साउथ की रीमेक बनाई तेरे नाम, यह फिल्म भी हिट रही. 2005 में एक और फिल्म आई नो एंट्री, यह भी रीमेक थी, यह फिल्म भी हिट रही. अक्षय की फिल्म भूल भूलैया भी पहले तमिल और मलयालम में बनाया जा चुका था. आमिर की फिल्म गजनी भी साउथ की रीमेक थी. इस डायरेक्ट किया था एआर मुरूगादास ने. गजनी की सफलता के बाद साउथ इंडियन फिल्मों को और विस्तार मिला, जब 2009 में वॉन्टेड आई. इस फिल्म ने सलमान के करियर को एक बार फिर से पुर्नजीवित किया. यह फिल्म साउथ के फिल्म निर्देशक महेश बाबू की पोकिरी की रीमेक थी. उसके बाद तो सलमान ने कई और साउथ की रीमेक फिल्मों में काम किया. अक्षय कुमार, अजय देवगन से लेकर कई और बड़े छोटे स्टार्स ने साउथ की रीमेक फिल्मों में काम किया. अगले साल की शुरुआत में सलमान की फिल्म किक रिलीज होने वाली है, यह फिल्म भी रवि तेजा और इलियाना स्टारर एक फिल्म की रीमेक है. वहीं हाउसफुल कमल हसन की फिल्म कताला कताला से प्रेरित बताया जाता है. साल 2011 में रेड्डी, बॉडीगार्ड सिंघम जैसी तीन फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई और ये तीनों ही रीमेक थी. 2012 में राउडी राठौर भी सुपरहिट हुई, जो पहले तमिल और तेलगु में बनाई जा चुकी थी. अजय की सन ऑफ सरदार भी तेलगु फिल्म मर्यादा रमन्ना की रीमेक थी. आने वाले दिनों में भी अक्षय सलमान, शाहिद, अजय हर किसी ने कोई न कोई साउथ फिल्म की रीमेक साइन कर रखी है. किसी भी तेलगु, तमिल या मलयाली फिल्म को उठा कर उसके पटकथा के साथ थोड़ी बहुत बदलाव कर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के साथ मेल कर फिल्म बना दी जाती है.

सच तो यह है कि एक ही तरह की फिल्में देख-देख कर बोर हो चुके दर्शक अब कुछ नया चाहते हैं. साउथ के खूबसूरत लोकेशन और फिल्मों के लिए वहां उचित माहौल मिलने के कारण फिल्मकार साउथ की तरफ़ मुव कर रहे हैं. साउथ और बॉलीवुड के एक्टर-एक्ट्रेस और डाइरेक्टर-प्रोड्यूसर्स अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. साथ ही वह आइडियाज का भी आदान प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह दर्शकों को बेहतर मनोरंजन दिया जा सके. इसके अलावा, विदेशों के महंगे लोकेशन फिल्मकारों को ज़रूर भाते हैं, लेकिन वहां फिल्मों की शूटिंग कर पाना इतना आसान भी नहीं है. उन्हें वहां के सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, इसके लिए उन्हें काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है और ढ़ेर सारे पेपरवर्क्स भी करने पड़ते हैं. वहीं साउथ में फिल्मकारों को फिल्म शूटिंग के लिए पूरा माहौल मिलता है, उन्हें परमिशन के लिए थकाऊ प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. यही हाल नॉर्थ का भी है. यहां फिल्मकारों को फिल्म की शूटिंग के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं. इसके अलावा, नॉर्थ की तुलना में साउथ में फिल्मों की शूटिंग लोकेशन काफ़ी सस्ते भी हैं.

एक सच यह भी है कि दर्शक फिल्मों में नॉर्थ इंडिया, मुंबई और कोलकाता को काफ़ी देख चुके हैं. सिनेमा अब ग्लोबल हो गया है, ऐसे में अब भाषा भी कोई समस्या नहीं रह गई है. लोग अब एक ही जगह सीमित होकर नहीं रहते, बल्कि वे हर कल्चर के साथ मिक्सअप हो रहे हैं. ऐसे में फिल्मकार देश के विभिन्न हिस्सों में फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ कर दर्शकों को कुछ नया दे रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्कूल गर्ल्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए : नीतू चंद्रा

अभिनेत्री नीतू चंद्रा चाहती हैं कि स्कूलों में लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए बक़ायदा उन्होंने एक ऑनलाइन पिटिशन दाख़िल कर सरकार से इसकी मांग भी की है. वह कहती हैं कि इससे लड़किया आत्मनिर्भर बनेंगी और उनके साथ होने वाले हादसों से काफ़ी हद तक वे अपनी रक्षा कर सकेंगी. हाल ही में शक्ति मिल कंपाउंड में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंग रेप हादसे ने दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी महिलाओं के सिक्यॉरिटी पर सवाल उठा दिया है. इस घटना से व्यथित नीतू चंद्रा ने महिलाओं के सुरक्षा को लेकर पहल करते हुए भारत सरकार के लिए एक ऑनलाइन पिटिशन दाख़िल की. इसके तहत, चौथी से बारहवीं क्लास में पढ़ रही लड़कियों के लिए स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करने की मांग की गई है. वैसे, नीतू ख़ुद ताइक्वॉन्डो में ब्लैक बेल्ट हैं और इस क्षेत्र में एशिया लेवल पर दो बार इंडिया को रिप्रजेंट भी कर चुकी हैं. लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के कोशिश में लगी नीतू, एक एनजीओ के साथ अपने इस सपने को साकार करने में भी लगी हैं. उनका मानना है कि लड़कियों में आत्मविश्वास के साथ-साथ सुरक्षा का भाव पैदा कर अन्याय से लड़ने का जज्बा पैदा किया जाए, न कि बंदूकों और चाकू की नोंक पर उनसे मनमानी की जाए. नीतू ने पिटिशन में लिखा है कि हम यह नहीं कहते कि लड़कियों को बंदूक चलाने या अपने पर्स में किसी धारदार हथियार को ले जाने की इजाजत दी जाए. हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि लड़कियों को अत्याचारियों का मुक़ाबला करने के साथ-साथ उनके ख़िलाफ़ चिल्लाने और एक क़रारा मुक्का मारने की ताक़त मिले. इसके अलावा, नीतू का यह भी कहना है कि अब वक्त आ गया है, जब हमें एकता का परिचय देना होगा और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा. ■

ग्रैंड मस्ती

डाइरेक्टर	:	इंद्र कुमार
प्रोड्यूसर	:	अशोक ठाकरिया, इंद्र कुमार
लेखक	:	मिलाप जावेरी, तुषार हिरनंदानी
स्टार कास्ट	:	विवेक ओबराय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी, सोनाली कुलकर्णी, ब्रुना अब्दुल्लाह, करिश्मा ताना, कायनात आरोड़ा, मरियम जाकरिया, मंजरी फड़नीश
म्यूजिक	:	आनंद राज आनंद, संजीव दर्शन
सिनेमेटोग्राफी	:	रितुराज नारायण
बजट	:	20 करोड़
रिलीज डेट	:	13 सितंबर, 2013

यह फिल्म तीन शादी शुदा दोस्तों पर आधारित हैं. विवेक ओबेरॉय के किरदार का नाम इसमें मीत है, वहीं आफताब शिवदसानी प्रेम के किरदार हैं, जबकि रितेश देशमुख अमर की भूमिका में हैं. रितेश देशमुख इस फिल्म में डॉक्टर और विवेक एक बिजनेसमैन की भूमिका में हैं. ग्रैंड मस्ती 2004 में आई फिल्म मस्ती का सिक्वल है. यह एक एडल्ट कॉमेडी है. फिल्म मस्ती आपको याद होगी, जिसमें तीन दोस्त बिरयानी के चक्कर में अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित फिल्म मस्ती की कामयाबी के बाद अब इसका सिक्वल आ रहा है. इसमें काफ़ी द्विअर्थी संवाद हैं. कहा जा रहा है कि यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म अमेरिकन पाई से प्रेरित है.

इससे पहले भी बॉलीवुड में सेक्स कॉमेडी पर आधारित फिल्में बन चुकी हैं. बीआर चोपड़ा की संजीव कुमार अभिनीत फिल्म पति पत्नी और वो बॉलीवुड की वास्तविक सेक्स कॉमेडी फिल्म मानी जाती है. इसके बाद लंबे समय तक कोई सेक्स कॉमेडी फिल्म नहीं बनी. कोई पंद्रह साल बाद हंसल मेहता की सेक्स कॉमेडी फिल्म यह क्या हो रहा है रिलीज हुई. एक और सेक्स कॉमेडी फिल्म बनी थी ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बड़ा सुख. इस फिल्म में छोटे शहर के दो युवा रॉबी घोष और विजय अरोड़ा सेक्स का अनुभव लेने के लिए शहर आते हैं. तब ऋषि दा की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी. बासु चटर्जी ने भी 1981 में इसी विषय पर आधारित एक फिल्म बनाई थी शौकीन. फिल्म में तीन बुड्ढे अशोक कुमार, उत्पल दत्त और एके हंगल फिल्म में मॉडल रति अग्निहोत्री को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं. सेक्सुअल कंटेंट के बावजूद इस फिल्म के संवाद साफ-सुथरे और हंसाने वाले थे. यह फिल्म हॉलीवुड की 1961 में रिलीज फिल्म ब्वॉयज नाइट आउट का रीमेक थी. शौकीन की सफलता के बावजूद बॉलीवुड में सेक्स कॉमेडी को सफलता नहीं मिली. शायद तब दर्शकों को ऐसा हास्य रास नहीं आ रहा था, लेकिन अब शायद दर्शकों को सेक्स कॉमेडी पर आधारित फिल्में भाने लगी हैं. ■

चौथी दुनिया

09 सितंबर–15 सितंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार – झारखंड

वामपंथी एकता पर ग्रहण

तमाम वामपंथी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद लंबे समय से बिहार में चल रही है. प्रमुख वामपंथी नेताओं में प्रकाश करात हों या एबी वर्धन या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, सभी इस ओर प्रयास भी करते दिख रहे हैं. कई बार विभिन्न आयोजनों में ये नेता यह कह चुके हैं कि बिहार में अगर वाम को मजबूत होना है, तो अपने खोये जनाधार को पाना ही होगा. उन्हें एक मंच पर आना होगा, लेकिन भाजपा व जदयू गठबंधन में टूट के बाद बिहार के बदलते समीकरण से एक बार फिर इस संभावना पर ग्रहण लगता दिख रहा है.

शशि सागर

सीपीआई का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले साल पटना में हुआ था. इस दौरान सीपीआई ने खुले सत्र में सभी वामपंथी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था. सभी ने वाम एकता की बात को एक सुर में ज़रूरी बताया था. हालांकि इस दौरान भी सीपीआई के एबी वर्धन ने नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्ष होने को सर्टिफिकेट दे दिया था. इसके बाद सीपीआई एमएल के परिवर्तन रैली के दौरान भी सीपीएम और सीपीआई के राज्य सचिव एक मंच पर दिखे थे और वाम जनवादी मोर्चे की वकालत भी की थी. यही वजह थी कि वामपंथी–जनवादी कार्यकर्ता यह मुगालता भी पालने लगे थे कि अब सभी वाम पार्टियां एक मंच पर आएंगी, लेकिन यह भ्रम भी टूटता ही नज़र आ रहा है.

सभी वाम पार्टियों को एक मंच पर लाने और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष करने की कवायद चल रही थी, तभी जदयू और भाजपा का अलगाव हुआ. इस अलगाव के बाद विश्वास मत के दौरान विधानसभा में सीपीआई ने अपने एक विधायक के साथ नीतीश का समर्थन किया. इसके बाद ही विवादों और बयानों का दौर शुरू हुआ. समर्थन देने को लेकर सीपीआई यह तर्क दे रही है कि जदयू नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा से अलग हुई है और सांप्रदायिक ताक़तों को सत्ता में आने से रोकना है, लेकिन सीपीआई भले ही कोई तर्क गढ़ ले पर नीतीश के प्रति उसका रवैया हमेशा से नरम ही रहा है. अपने 21वें अधिवेशन के दौरान उसने यह संकेत भी दे दिया था. अभी गत माह ही पार्टी के आयोजन के दौरान प्रकाश करात का भी बिहार के बेगूसराय में आना हुआ था, तब उन्होंने भी वाम एकता की वकालत की थी. जानकार बताते हैं कि ऐसी संभावना है कि सीपीआई जदयू के साथ चली जाए. अगर ऐसा हुआ तो माले सीपीआई के साथ नहीं होगी, ऐसा संकेत माले दे चुकी है. लालू के साथ सत्ता सुख भोग चुकी सीपीआई आज पानी पी–पीकर लालू को कोस रही है. पिछले दिनों एक आयोजन में वर्धन पटना आए. विधान परिषद के सभागार में बोलते हुए वर्धन ने कहा कि लालू दग़ाबाज़ हैं और उन्होंने 15 सालों में कम्यूनिस्टों को नुक़सान ही पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि 17 साल के बाद यह गठबंधन टूटा है और यह कम्यूनिस्टों के लिये फ़ायदे की बात है, लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि कम्यूनिस्टों को फ़ायदा हो न हो सीपीआई अपनी राष्ट्रीय मान्यता बचाये रखने के लिये जदयू से फ़ायदा अवश्य ले लेगी. वामपंथी दलों की एकता में श्रेष्ठताबोध भी आड़े आती है. सीपीआई को जहां इस बात का दंभ है कि वह मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं सीपीएम ख़ुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी मानती है. माले को भी इस बात का दंभ है कि वह अकेले सालों भर बिहार में सड़क के विपक्ष की भूमिका में रहती है. वर्धन की बातों से यह दंभ झलकता भी है. इसी अगस्त में जब एक कार्यक्रम के दौरान वर्धन से पूछा गया कि जदयू से गठबंधन की संभावना को लेकर माले नाराज़ दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि सीपीआई कोई भी निर्णय माले महासचिव से पूछ कर नहीं लेगी. दीपांकर और उनकी पार्टी के जन्म से पहले से सीपीआई और सीपीएम का अस्तित्व है.

एक वामपंथी नेता कहते हैं कि बिहार में वाम एकता संभव नहीं है और सीपीआई का तो एकदम साफ स्टैंड है कि किसी तरह राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता कर लोकसभा में पांच सीट लाया जाए. इसके लिये वो बिहार में जदयू के साथ जाएगी, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ है ही और जयललिता और चंद्रबाबू नायडू को भी समर्थन दे ही रही है. माले के सवाल पर वह कहते हैं कि माले को भी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, इसलिये वो पहले से ही घोषणा कर चुकी है कि 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी. कामरेड माले को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि माले यह प्रयास कर रही है कि हम इस बदौलत फिर से उभर सकें, लेकिन आत्मगत प्रयासों की एक सीमा होती है. इसलिये माले को कार्यनीति और रणनीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है. बहरहाल बिहार में वाम एकता के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो यह दिखता है कि संघर्ष के नाम पर तो ये पार्टियां एक मंच पर आती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आती है, उनका गठबंधन टूट जाता है. गत लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी वामपंथी दलों में पूर्ण समझौता नहीं हो पाया था. भाकपा माकपा उम्मीदवारों को कई सीटों पर कड़ी टक्कर मिली थी. जानकार बताते हैं कि बिहार में फिर से भाकपा की स्थिती 1956 वाली हो गई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि माकपा का एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है, लेकिन अपनी इस दुर्गती के बाद भी संसदीय मोह से वाम उबर नहीं पा रही है. सीपीएम और माले साथ होंगे, ऐसी भी संभावना नहीं दिख रही है. कारण यह कि दोनों ही दंभ के शिकार हैं. अबतक तो यही दिखता है कि बिहार की वामपंथी पार्टियां अगर धरना–प्रदर्शन को छोड़ दें तो एक साथ कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है. जिस राष्ट्रीय पहचान को बचाने की संकट से कभी सीपीएम गुजरा था, आज वह संकट सीपीआई के साथ है. यही वजह है कि वह उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ है, जबकि वहां वाम पार्टियां पॉस्को के सवाल पर सरकार का विरोध कर रही है. डॉ. भगवान प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि संघर्ष की एकता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है. आज इन वाम पार्टियों को गांव जाना होगा, पटना में बैठकर धरना–प्रदर्शन कर ये संघर्ष नहीं कर सकते हैं. इन्हें संसदीय राजनीति से दूर जाकर सतत संघर्षशील जनपक्षधरीय विपक्ष तैयार करने की ज़रूरत है. आज इन वाम पार्टियों को अपने ऐतिहासिक भूल से सीख लेने की भी ज़रूरत है. मनमोहन के नव उदारवाद का समर्थन उन्होंने किया ही था, इमरजेंसी में भी वे कांग्रेस के साथ थे. आज भले सीपीआई लालू को कोस रही है और नीतीश का गुणगान कर रही है, लेकिन मंडल कमीशन के नाम पर जातीगत आरक्षण का उन्होंने ही समर्थन किया था. बाद के दिनों में उनका वर्गीय जनाधार वर्णीय जनाधार में बंटता चला गया और सीपीआई–माले से टूट कर लोग लालू के साथ चले गये. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि वाम जनवादी जन आकांक्षाओं के दबाव में ये पार्टियां वाम एकता की बात करती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही जायेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ उनका सम्मानजनक समझौता होने से रहा. अगर ये वाम पार्टियां एक मंच पर आ भी जाये तो राजनीतिक फ़ायदा भले हो जाये, लेकिन चुनाव परिणामों में कोई अंतर नहीं आने वाला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

नकारा बना आयुर्वेदिक औषधालय

परसौनी ग्रामीण क्षेत्र में आम-अवाम को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर सीतामढ़ी ज़िले के परसौनी प्रखंड अंतर्गत स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कुछ वर्षों से नकारा बना हुआ है. वर्ष 1955-56 में स्थापित बरामदा समेत तीन छतदार मकान जर्जर हो चुके है. मकान के कमरे, खिड़कियां और किवाड़ बेकार हो चुके हैं. सरकारी स्तर पर डॉ. चंद्रभूषण निराला के अलावा एक मिश्रक एवं एक आदेशपाल की नियुक्ति भी की गई है. तक़रीबन 15 हज़ार रुपये प्रति वर्ष सरकारी स्तर पर दवा मद में मुहैया भी कराई जाती है, लेकिन आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. पंसस सैरुल हुसैन, मिथिलेश साह, मो. निजामुद्दीन मुखिया, प्रदीप साहनी, हरि शंकर राउत, दिनेश प्रसाद सिंह, राम विनय सिंह एवं सुनील पासवान समेत अन्य ने राज्य सरकार एवं ज़िला पदाधिकारी से शीघ्र समस्या निदान कराने का आग्रह किया है.

– राम नारायण

बोधगया होटल एसोसिएशन ने किया सम्मानित

बोधगया के महामाया पैलेस में आयोजित बिहार प्रदेश भाजपा के दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन बोधगया होटल एसोसिएशन ने भाजपा के वरिष्ट नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय समेत मंच पर बैठे भाजपा के वरीय नेताओं को महाबोध मंदिर का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मान किया. एसोसिएशन ने बोधगया के विकास से संबंधित एक स्मारक पत्र भी भाजपा नेताओं को सौंपा गया. बोधगया होटल एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष काली भगत, महासचिव सुदामा कुमार, यूकी, राजेश कुमार, नंदलाल साव आदि ने मिल कर भाजपा नेताओं का सम्मान किया. एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने बताया कि भाजपा कार्य समिति की बैठक बोधगया में होना गौरव की बात है. इससे न सिर्फ पूरे प्रदेश के लोगों को बोध गया आने का मौक़ा मिला, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी यहां के विकास के प्रति जागृत हुआ है.

– सुनील सौरभ

हाजत में आदिवासी की मौत

चतरा ज़िले के टंडवा थाने की हाजत में माधव उरांव की मौत हो गई. ज़िला परिषद 18 की सदस्य शोभा कुजूर ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने इसे प्रताड़ित किया है और गले में रस्सी लगाकर उसकी हत्या कर दी है. वहीं पुलिस इसे आत्महत्या कह रही है. ज़िले के एसपी अनुप ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक एएसआई बीके मिश्रा और दो चौकीदार मुखलाल पासवान और योगेश्वर यादव को निलंबित कर दिया है. साथ ही थानेदार प्रमोद रंजन लाइन हाजिर कर लिए गए हैं. कुजूर और स्थानीय विधायक जर्नादन पासवान ने थाना प्रभारी पर 302 के तहत मुक़दमा दर्ज करने और मृतक के परिजन को बीस लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है. मृतक को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

– अमरेंद्र सिह

चंपारण

मोतिहारी सेहत महक़मा सुधरने को तैयार नहीं

इंतेजारूल हक़

मोतिहारी सेहत महक़मा अब तक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाक़ाम साबित हुआ है. पूर्वी चंपारण ज़िले का स्वास्थ्य विभाग व सिविल सर्जन कार्यालय इन दिनों अनियमितता का मुख्य केंद्र बना हुआ है और यहां अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी बहती गंगा में हाथ साफ़ कर रहे हैं. मरीजों के इलाज़, चिकित्सीय कर्मचारियों के तबादले, सदर अस्पताल की सफ़ाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और नियम-कानून को यहां ठेंगा दिखाया जाता है. पूर्वी चंपारण ज़िले का स्वास्थ्य विभाग व सिविल सर्जन कार्यालय में लाखों-करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बगैर किसी निविदा के ही मौखिक आदेश पर लाखों की दवा दे दी जाती है और बाद में इसे काग़ज़ी खानापूर्ति कर हजम कर लिया जाता है. बीते दिनों जिलाधिकारी विनय कुमार के निर्देश पर सदर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता द्वारा की गई. अस्पताल परिसर में स्थित नर्स ट्रेनिंग कॉलेज में छापेमारी व बरामद क़रीब 70 लाख रुपये की दवा व मोतिहारी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के बयान पर नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. इस मामले की प्राथमिकी इसका ताजा उदाहरण है. चौंकाने वाले तथ्य तो यह हैं कि जब राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा घोटालों व व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, तो अपनी ग़लतियों को छुपाने के लिए उन पर मुक़दमा कर दिया जाता है. हाल ही में युवा राजद द्वारा सीएस कार्यालय के समक्ष आहूत धरना इसका ज्वलंत प्रमाण है. पहले तो सिविल सर्जन डॉ. सरोज सिंह द्वारा धरना पर बैठे राजद नेताओं को धमकी दी गई और फिर अपने कर्मचारियों से धक्का-मुक्की कराकर अस्पताल की व्यवस्था को और चौपट कराने का प्रयास किया गया और उल्टे नगर थाना में आवेदन देकर मारपीट करने, सरकारी संपत्ति तोड़ फोड़ करने एवं नीजी स्टेटोस्कोप छिनने का मामला दर्ज करा दिया गया. पुलिस मामले को दर्ज कर जांच कर रही है. यहां बताते चलें कि पूर्वी चंपारण के तत्कालीन जिलाधिकारी विनय कुमार अपने पदस्थापना काल से ही सदर अस्पलात को भ्रष्ट व्यवस्था से उबारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. इसके अलावा, यहां जिन निजी नर्सिंग होमों को परिवार नियोजन, बीपीएल परिवारों के इलाज व ऑपरेशन के लिए ठेके दिए गए हैं, उनमें अधिकांश के पास न तो सर्जन हैं और न ही मरीजों के बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था. केवल खानापूर्ति कर सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय कमिटी द्वारा की गई है. जांच प्रतिवेदन भी सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक उन नर्सिंग होमों व उनके संचालकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उस मामले में भी सिविल सर्जन डॉ. सरोज सिंह समान रूप से ज़िम्मेदार रही हैं. राजद नेता व मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजेश गुप्ता उर्फ बब्लू गुप्ता, जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, बजरंगी नारायण ठाकुर, अनिरुद्ध साहनी, नसीमा खातून, डॉ. शमीम अहमद, ज़िला विद्विज्ञ संघ के महासचिव राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू यादव आदि बताते हैं कि सदर अस्पताल में इन दिनों गुंडाराज है. उक्त नेताओं ने झुठे मुक़दमें को वापस लेने व सीएस के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइ करने की मांग की है. ■

फूड इंस्पेक्टर मौन, तो सुनेगा कौन

अवधेश कुमार शर्मा

पश्चिम चंपारण ज़िले में इन दिनों मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री बेरोक-टोक जारी है और उसका सेवन करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं. बिहार की सुशासन सरकार मध्याह्न भोजन योजना में मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन खुले आसमान में बगैर किसी निबंधन के बिक रही मिलावटी खाद्य सामग्रियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. खाद्य पदार्थो में मिलावट राष्ट्र के विकास में बाधक बन रहा है, क्योंकि स्वस्थ नागरिकों से ही देश की प्रगति होती है. अधिकतर व्यवसायिक खाद्य संस्थान (होटलों) प्रतिष्ठान एवं खाद्य पदार्थ निर्माता बिना अनुज्ञप्ति(फूड लाईसेंस) लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए फैक्ट्री चला रहे हैं, ये खाद्य पदार्थ काफ़ी निम्न स्तर के होते हैं, जो बेहद हानिकारक होते हैं. निर्माण क्षेत्र में देखा जाए पर्व त्योहार पर बिकने वाले खाने पीने वाली चीजें जैसे सेवइयां, बिस्कुट, मिठाई, दालमोट, बेसन, लेमनजुस, तेल मासाला आदि बनाने वाले क्षेत्रीय निर्माता बगैर अनुज्ञप्ति के प्रशासन के नाकों तले लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम बेख़ौफ़ कर रहे है. इसके अलावा, ज़िले के विभिन्न होटल और रेलवे स्टेशन पर खुदरा खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी बिना सैनेटरी इंस्पेक्टर के प्रमाणपत्र के धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं. जानकार बताते हैं कि उपर्युक्त स्थानों पर अधिकतर घटिया खाद्य सामग्री को बेचने व बनाने का काम कतिपय कनीय अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है. अधिकारियों मिलीभगत के कारण खाद्य लाइसेंस लेना एवं इसके मापदंड पर खरा उतरना ज़रूरी नहीं होता है. इस प्रकार देखा जाए तो पश्चिम चंपारण के बेतिया, बगहा, नरकटियागंज अनुमंडल व विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों बेसन, सरसों तेल, सत्तु, बासी सब्जी की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है. अद्भूत तौर घटिया सामग्री विभिन्न ब्रांडेड प्रोडॅक्ट के नाम पर बेची जाती है, यहां तक कि पेयजल की सील डुप्लीकेट बोतले भी धड़ल्ले से बेची जा रही है, जबकि दूसरी ओर कई होटलों एवं स्टेशन पर बासी-पुरानी मिठाईयां व एक्सपायरी अन्य खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, लेमनजुस, ब्रेड, दालमोट आदि बेची जा रही है. इन खाद्य पदार्थों की बिक्री से न केवल लोगों में बिमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, बल्कि आमजन बेवक्त मौत के आगोश में भी समा रहे हैं. इस संबंध में जब फूड इंस्पेक्टर से बात की जाती है, तो वे संसाधन एवं कर्मचारियों की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं तथा लोगो को बेमौत मरने के लिए मिलावट करने वालों को खुली छूट देते हैं. यहां ज़िले के खाद्य निरीक्षक से मुलाकात भी कई बार जुते घिसने के बाद ही हो पाती है, पुछने पर वह कहते हैं कि अकेले पूरा ज़िला देखना है. प्रतिदिन कहां-कहां देखा जाए, आप ही बताएं, सभी जगह जाना संभव है? वहीं कुछ व्यापारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि फूड इंस्पेक्टर का आदमी आकर अपनी बंधी बधाई रक़म नियत समय पर ले जाता है, तो फिर डर किस बात का? इस बाबत इंसपेक्टर ने रिश्वतख़ोरी को एक सिरे से नकारते हुए कहा कि सारी बाते व आरोप निराधार है. ■

feedback@chauthiduniya.com

डिहाइड्रेशन से खुद को बचायें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. भरत कुमार
फिज़ीशियन, दरभंगा

तीज-कर्मा के शुभअवसर पर बिहारवासियों को बधाई

बरसात के मौसम में संक्रमण रोग का ज्यादा खतरा रहता है. बारिश और उमस भरी गर्मी के इस मौसम में हमें खुद को डिहाइड्रेशन से भी बचाने की आवश्यकता है. ऐसे मौसम में बाहर के खानों से परहेज करना चाहिए. साथ ही बाहर का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए. पानी या तो घर का पीयें या फिल्टर किया हुआ. बारिश तो हमें राहत देती है लेकिन सेहत से जुड़ी परेशानियां भी साथ लाती है. वातावरण में नमी मौजूद होने की वजह वैक्टीरियल बिमारी होने की आशंका बनी रहती है. ऐसे मौसम में सर्दी-खांसी, लूज मोशन, बुखार, निमोनियां आदि होने का खतरा अधिक रहता है. सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें घर के खाने को ढ़ंक कर रखना चाहिए साथ ही अपने डाइट में फ्लूड मटेरियल को भी शामिल करना चाहिए. खाने में हमें फल में अमरूद, नारंगी, नाशपाती, आंवला और हरी सब्जी तो अवश्य लेना चाहिए. नाशपाती को अच्छी तरह धोकर और छिलका समेत चबा कर खाना चाहिए. इस मौसम में जलीय फलों जैसे तरबूजा और खरबूजा के सेवन से बचना चाहिए.

कटे हुए फलों से भी परहेज करना चाहिए. देखा जाता है कि लोग मानसून के मौसम में कम पानी पीते हैं लेकिन इस मौसम में मेटाबॉलिज्म के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है.

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

प्रस्तुति: शशि सागर

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE

NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिया स्वामी, राजस्थान

उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूँद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।

प्रश्न : डॉ साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द, देहरादून

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं काफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।

उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर

उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5X का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।

उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली

उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।

प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें। उपेन्द्र सिंह, कानपुर

उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरुष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर : मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटरः फोन : 9546943292, 9304018193, होमियों जोन, फोन : 9835409077
स्टॉकिस्ट पटना : स्टेशन : 6455163, 2221930, 2220946, 3205055, 9334103490, जी. एम. रोड : 9304303182, 9308138439, राजाबाजार : 9386805101, 9905014239, बोरिंग रोड : 9334110892, 9693059075, 9334313253, 2572795, दानापुर : 9386468122, पटना सिटी : 9835657262, 9939297200, फतुहा : 8102453554, बक्सर : 9334726944, 8873393515, हाजीपुर : 9905225067, 9835018193, 8084253810, मुजफ्फरपुर : 9430438987, 9835067754, बिहारशरीफ : 9334277766, 9334291096, 9835229796, 9304092021, नवादा : 9279573812, 9431297933, गया : 9135404090, 9430569851, 9934416652, 9835650351, 9798053280, 2222103, औरंगाबाद : 9386095201, सीवानः 9708753244, जमुई : 9135403344, लहेरियासराय : 7209818351, दरभंगा : 9334360159, 9471009191, भागलपुर : 9431214442, 9263130133, 9431213686, 9835086273, बेगूसराय : 9431693636, 9905407128, 9334186212, सीतामढ़ी : 9204307223, 9470449092, 9508167052, समस्तीपुर : 9934246416, 9835428107, 9708911940, रक्सौल : 9470045119, छपरा : 9430880950, बेतिया : 9931800635, 9835686250, कटिहार : 2244924, 9430945755, किशनगंज : 8986408629

अधर में लटका एयरपोर्ट का विस्तार

सुनील सौरभ

गया में बिहार-झारखंड का इकलौता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. केंद्र सरकार ने तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री शाहनवाज़ हुसैन के समय इस हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार कराकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन 2002 में किया था. शाहनवाज़ हुसैन ने इस हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए बिहार के हज यात्रियों को सीधे गया से जेद्दाह भेजने के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की थी. उसके कई वर्ष बाद भी बिहार के हज यात्री गया से ही सीधे उड़ान भर कर जेद्दाह जाते रहे हैं, लेकिन बाद में सरकार ने बिहार के हज यात्रियों के लिए व्यवस्था बदल दी. इससे पूर्व गया से बैंकाक के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत कर गया के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था.

उस पहली उड़ान में संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी, बिहार सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा पत्रकारों को सरकार की ओर से बैंकाक ले जाया गया था. इसके बाद पर्यटन सीज़न में विभिन्न बौद्ध देशों से गया के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई. चार्टर जहाज़ से भी बौद्ध श्रद्धालु सीधे गया हवाई अड्डा आने लगे. वर्तमान वर्ष में तो एयर ट्रैफिक के सर्वे में गया हवाई अड्डा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा के रूप में चिन्हित किया गया. गया हवाई अड्डा पर पर्यटन सीजन में हवाई जहाजों की सर्वाधिक आवा-जाही रही, लेकिन सही रूप में गया हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा नहीं मिल सका है. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए निर्धारित रनवे और भूमि की कमी है. भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है. कुछ ज़मीन को अधिग्रहित भी किया जा चुका है, लेकिन 61 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला अधर में लटक गया है. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिलने के लिए नाईट लैंडिंग की सुविधा होना ज़रूरी है. इसके लिए 100 एकड़ से अधिक भूमि की ज़रूरत इस हवाई अड्डे को थी. उनमें से क़रीब 30 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन हवाई अड्डा के निकट स्थित विशुनगंज गांव के 297 किसानों से क़रीब 70 एकड़ खेती की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है.

यहां के किसानों ने सरकार की ओर से निर्धारित मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया है. किसानों की मांग है कि बाज़ार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित ज़मीन का मुआवज़ा दिया जाए, 5 कट्ठे ज़मीन के बदले परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी दी जाए, जिस परिवार में नौकरी योग्य लोग नहीं हैं, उस परिवार को पेंशन की व्यवस्था हो, पुनर्वास की व्यवस्था की गारंटी दी जाए, आवासीय घरों को छोड़कर सिर्फ परती भूमि का अधिग्रहण किया जाए, विशुनगंज में निःशुल्क बिजली, पानी की सुविधा दी जाए, अधिग्रहित भूमि से प्राप्त आय में लाभांश का 25 फ़ीसदी किसानों को मिले, विशुनगंज गांव के पड़ोसी गांव का भूमि निबंधन शुल्क बढ़ाया जाए आदि. गया हवाई अड्डा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 2010 में शुरू किया गया था. इस वर्ष 21 फरवरी, 22 अप्रैल, 02 जून, 06 जून, 12 जून को ज़िला प्रशासन के साथ किसनों की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा विफल रहा. ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि सरकार 16000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से मुआवज़ा दे रही है, जबकि हमारी मांग 97000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से है. ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी प्रभात कुमार झा ने बताया कि गया हवाई अड्डा के विस्तार के लिए 2009-10 में अधिसूचना निकाली गई थी. उसके अनुसार ही विशुनगंज गांव के किसानों की खेती योग्य भूमि का दर सरकार ने निर्धारित कर दिया है. उसी के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन किसानों से बात-चीत हो रही है, मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. विशुनगंज गांव के किसानों ने भूमि का मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया तो ज़िला प्रशासन ने सरकार से मिले मुआवज़ा के 9,30,04,485 रुपये ज़िला कोषागार में जमा कर दिया, जब किसान मुआवज़ा राशि लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कोषागार से रुपये निकाल कर भुगतान कर दिया जाएगा. फिलहाल गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का विस्तार अधर में लटक गया है. पुनः पर्यटन सीज़न आरंभ होने वाला है. दिल्ली-वाराणसी-गया एयर इंडिया की नियमित उड़ान शुरू होने वाली है. उसी प्रकार थाई एयरवेज़, म्यांमार इंटरनेशनल एयरवेज़, मिहिन लंका एयरवेज़, ड्रुक एयरवेज़ समेत अनेक देशों से हवाई सेवा शुरू होने वाली है. चार्टर जहाज़ भी बड़ी संख्या में यहां आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल नाईट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण भारी दिक्कत हो रहा है. विस्तार के बाद ही उसे पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल सकेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुपरी

षड्यंत्र का शिकार हुआ रेफरल अस्पताल

गोविंद कुमार

तक़रीबन डेढ़ दशक पूर्व सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में रेफरल अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी. सरकारी राशि से दो मंजिला भवन का निर्माण कराया गया और कर्मियों की तैनाती भी की गई. जब आम-अवाम को स्वास्थ्य लाभ लेने का वक्त आया तो पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही मरीजों के इलाज के लिए कार्यरत है. यह सब महज राजनीतिक वर्चस्व और षड्यंत्र का नतीजा है. अब आलम यह है कि लाखों की लागत से निर्मित उक्त सरकारी भवन जहां खंडहर में तब्दील हो गई है, वहीं अस्पताल के जर्जर भवन से लेकर ज़मीन पर भी दबंगों ने क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया है. बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का सपना संजोने वाले क्षेत्र के लोग अब आह भर कर रह जाते हैं. मजे की बात तो यह कि उक्त निर्मित अस्पताल के कुशल संचालन की दिशा में अब तक न तो किसी जनप्रतिनिधि ने और न ही विभागीय महक़मा ने कोई प्रयास किया है. बताया जाता है कि वर्ष 1998 में इस रेफरल अस्पताल की आधारशिला सूबे के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रघुनाथ झा ने रखी थी, जिसका विधिवत उद्घाटन 17 फरवरी, 2002 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने किया था. अस्पताल परिसर में क़रीब आधा दर्जन भवन का निर्माण चिकित्सक व कर्मचारियों के लिए कराया गया था. विभागीय स्तर पर चिकित्सक व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी. शुरुआती दिनों में क़रीब दो माह तक अस्पताल का संचालन बेहतर तरीक़े से हुआ था. बाद में कतिपय कारणों से पदस्थापित चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई और अस्पताल को एएनएम के हवाले कर दिया गया. तब उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अस्पताल कार्यरत रहा. अस्पताल के एक हिस्से में कुष्ठ नियंत्रण इकाई का कार्यालय स्थापित किया गया, जिसमें डॉ. वेणु झा की प्रतिनियुक्ति की गई थी. समय गुजरने के साथ ही स्थानीय राजनीति ने अस्पताल के अस्तित्व पर संकट खड़ा करना शुरू कर दिया. इसकी दुर्गति के लिए राज्य सरकार व विभागीय महक़मा भी कम ज़िम्मेदार नहीं है. विधिवत कर्मियों की स्थायी प्रतिनियुक्ति के बिना ही आनन फानन में अस्पताल का उद्घाटन करा दिया गया. अस्पताल संचालन का दौर मंदा होने के साथ ही असामाजिक तत्वों ने इस पर नज़र गड़ाना शुरू कर दिया. महज चंद साल बाद ही अस्पताल भवन से लकडी की खिडकी व किवाड़ भी ग़ायब किये जाने लगे. इसके अलावा, अस्पताल से लाखों रुपये मूल्य के उपस्कर भी ग़ायब हो गए. अस्पताल के चारदिवारी की ईंट और परिसर में मौजूद चापाकल तक को ग़ायब कर दिया गया. अस्पताल की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का आलम यह है कि कोई भी इस मामले में कुछ भी पहल करना मुनासिब नहीं समझता. एक बार उक्त भवन में पॉलीटेक्निक कॉलेज संचालित करने की घोषणा की गई, लेकिन इस दिशा में भी कारगर पहल नहीं की जा सकी. समय रहते अगर उक्त भवन को स्वास्थ्य महक़मा अपने क़ब्ज़े में नहीं करता है, तो संभव है आने वाले महज कुछ सालों में यह किसी भू-माफ़िया के चंगूल में हो. ■

● जर्जर रेफरल अस्पताल भवन

feedback@chauthiduniya.com

बाजपट्टी

खंडहर में संचालित हो रहा है थाना

अभिलाषा द्विवेदी

बिहार में आम-अवाम को सुरक्षा मुहैया कराने की घोषणा करने वाली सरकार अब तक सुरक्षा कर्मियों को समुचित सुविधा मुहैया कराने में विफल रही है. सीतामढ़ी ज़िले में बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना भवन इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है. तक़रीबन 37 साल पूर्व स्थापित थाने का यह हाल है कि अब तक उसे अपना भवन तक नसीब नहीं हो सका है. पिछले साढ़े तीन दशक से यह थाना घुमंतू थाना बन कर रह गया है. वर्तमान में प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एक परित्यक्त आवासीय जर्जर भवन में येन-केन प्रकारेण थाने का संचालन किया जा रहा है. सरकारी अथवा प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि उक्त जर्जर भवन का मरम्मत भी वर्षों से नहीं हुआ है. नतीजतन एक ओर जहां कार्यरत कर्मियों को कार्य संपादन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों से भी जान को ख़तरा बना रहता है. सबसे अहम बात यह है कि किसी भी आरोपी को थाने में रखने का साहस कार्यरत कर्मी नहीं कर पाते. बरसात के दिनों में तो इस थाने का तमाशा ही बन कर रह जाता है. येन-केन प्रकारेण प्लास्टिक के सहारे आवश्यक काग़ज़ातों को बचाया जाता है. बताया जाता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से थाना का क्षेत्रफल 34486 एकड़ है. क़रीब 1 लाख, 14 हज़ार पुरुष एवं 1 लाख, 3 हज़ार महिलाओं की सुरक्षा की कमान इस थाने के हाथ में है. विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि चौकीदार का सृजित पद 60 में 47, दफादार सृजित पद 4 में 1 एवं एएसआई का 3 में महज 1 ही पद पर तैनाती है. आरक्षी का 8 एवं हवलदार का 1 पद सृजित है, लेकिन उक्त पद पिछले एक साल से खाली पड़े हैं. थाने के महत्वपूर्ण पद मुंशी का भी तबादला एक माह पूर्व हो गया है और अब तक कोई नया मुंशी नहीं रखा गया है. महिला पुलिस का तो कोई अता पता भी नहीं है. थाने का बेसिक फोन तो पिछले चार साल से बंद ही पड़ा है. थाना क्षेत्र के 19 पंचायतों के क़रीब 80 गांव की सवा 2 लाख जनसंख्या की सुरक्षा का ज़िम्मा यह थाना संभाल रहा है. विभागीय स्तर पर क़रीब ढाई साल पूर्व नये थाने भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया गया, लेकिन कतिपय कारणों से लंबे अर्से से निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है, जबकि थाने में दर्ज मामलों का आकड़ा भी कम नहीं है. सूत्रों की माने तो वर्ष 2011 में 195, 2012 में 194 एवं 2013 में अब तक क़रीब पौने दो सौ मामले दर्ज किए जा चुके हैं. थाने की बदहाली को लेकर अब क्षेत्र की जनता भी आंदोलन के मूड में नज़र आने लगी है. रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष मो नथुनी अंसारी, प्रखंड लोजपा अध्यक्ष सनोवर प्रवीण, भाकपा नेता मौजेलाल शर्मा व रामेश्वर मंडल, वनगांव उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया रेखा कुमारी समेत अन्य ने थाने के सवाल पर आंदोलन की चेतावनी दी है. साथ ही समस्या का अविलंब निदान नहीं होने की स्थिति में उच्च न्यायालय तक जाने की बात भी कही है. ■

● जर्जर भवन में थाना

feedback@chauthiduniya.com

नर्सों के 42 हज़ार पद खाली

बिहार सराकर के विकास के पोल खोलते हैं, यहां के अस्पताल. राज्य के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य केंद्रों में 42,000 हज़ार से अधिक नर्सों के पद रिक्त हैं, फिर भी बिहार सरकार सरकारी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजों की दशा में सुधार के लिए कोई काम नहीं कर रही है और न ही निजी संस्थानों को मान्यता दे रही है. यहां के सरकारी अस्पतालों में अप्रशिक्षु नर्सें काम कर रही हैं, इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों के जीवन पर बन आई है.

सुनील सौरभ

बिहार सरकार का दावा है कि देश में बिहार सर्वाधिक विकास करने वाला राज्य बन गया है, लेकिन हालात देखने से पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है. केवल काग़ज़ों और इंटरनेट पर विकास के आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता. हक़ीक़त कुछ और ही है, जिसका सामना लोग कर रहे हैं. बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. शिक्षा तथा स्वास्थ्य से ही जुड़ा है नर्सिंग शिक्षा. अफसोस की बात तो यह है कि नर्सिंग शिक्षा की ही बिहार में बेहद ख़राब स्थिति है. राज्य के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य केंदों में 42,000 से अधिक पद रिक्त हैं. निजी नर्सिंग होम में भी प्रशिक्षित नर्सों की ज़रूरत रहती है, लेकिन राज्य सरकार न तो सरकारी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजों की दशा में सुधार लाने के लिए काम कर रही है और न ही निजी संस्थानों को मान्यता दे रही है. नतीजा यह है कि राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किसी भी तरह काम चलाया जा रहा है. नर्सों के रिटायर होने से भी पद खाली हो रहे हैं. राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेश के बाद भी नर्सों को प्रशिक्षण देने वाले प्रस्तावित 17 संस्थानों को मान्यता नहीं दिया गया. मान्यता न देने के कारण अब हाईकोर्ट में अवमानना देने की भी चर्चा हो रही है. बिहार में प्रशिक्षित नर्सों की विभिन्न ग्रेडों में क़रीब 42,000 पद रिक्त है. बिहार सरकार यदि सरकारी तथा निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता भी देती है, तो प्रतिवर्ष कुल 9600 ही नर्सें ही ट्रेंड होंगी. इससे भी बिहार की आबादी तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ज़रूरत को देखते हुए प्रशिक्षित नर्सों के रिक्त पद नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हर महीने नर्सें रिटायर भी हो रही हैं और प्रतिदिन उनकी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है. इसके बावजूद नर्सिंग की शिक्षा व प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को सरकार मान्यता नहीं दे रही है. बिहार में मेडिकल की पढ़ाई के लिए क़रीब एक दर्जन कॉलेज-इन्स्टीट्यूट है. 38 ज़िला अस्पताल, 101 अनुमंडलीय अस्पताल, 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सैंकड़ों अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले इस सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित एन-एम के हज़ारों पद रिक्त पड़े हैं. इन दिनों सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन प्रशिक्षित एन.एम. के नहीं रहने से चिकित्सकों को काफ़ी परेशानी हो रही है. कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तो आशा कार्यकर्ताओं के सहारे चल रहे हैं. फिलहाल बिहार में 47 सरकारी-गैर सरकारी एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान हैं. इनमें प्रत्येक को 20 से लेकर 60 सीट स्वीकृत हैं. इन संस्थानों से प्रतिवर्ष मात्र 9600 एन.एम. ही प्रशिक्षण लेकर निकलते हैं. इनमें कई संस्थान ऐसे हैं, जिसे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ़ 2 वर्ष की ही मान्यता दी है. 17 एन.एम. प्रशिक्षण देने वाले संस्थान, जो सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं, मान्यता के लिए बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं. लेकिन बिहार सरकार मान्यता नहीं दे रही है. बिहार सरकार की शर्तें हैं कि इन संस्थानों के पास बीएससी (नर्सिंग) शिक्षक नहीं हैं. सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार का जो एनएम प्रशिक्षण केंद्र है, वहां भी बीएससी (नर्सिंग) डिग्रीधारी शिक्षक का अभाव है, जबकि सरकारी संस्थानों से बहुत ही अच्छी स्थिति में निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान बिहार-झारखंड में हैं. वहां एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है, जहां कि बीएससी (नर्सिंग) की पढ़ाई होती हो. नर्सिंग की पढ़ाई के प्रति बिहार सरकार की उपेक्षित नीति तथा मान्यता नहीं मिलने से निराश निजी नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थानों ने हाईकोर्ट की शरण ली. हाई कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को मान्यता प्रदान करने या फिर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का आदेश दिया. लेकिन बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग हाईकोर्ट के इस आदेश की भी अवहेलना कर रहा है. नियमतः बिहार सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के 6 महीने के अंदर ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल किसी एनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता प्रदान करता है. नर्सिंग की नौकरी करने के लिए वैसे भी महिलाएं काफ़ी कम आती हैं. दूसरे राज्य सरकार की उपेक्षित नीति ने नर्सिंग शिक्षा को और भी दयनीय स्थिति में ला दिया है. नतीजा यह हैं कि बिहार के अस्पतालों और नर्सिंग होमों में अप्रशिक्षित नर्सों के काम करने के कारण स्वास्थ्य सेवा की हालत और ख़राब हो रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

निर्देशिका का लोकार्पण

भाजपा चुनाव में उतरने से पहले हर स्तर पर अपने को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुट गई है. पार्टी के तेज तर्रार नेता व लोक सेवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह की मेहनत से एक निर्देशिका छपवाई गई है. इसकी खासियत यह है कि इसमें लोक सेवा अधिकार की बारीकियों के अलावा भाजपा के सभी सांसद व विधायक, पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय व ज़िला प्रभारी, मंच अध्यक्षों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं ताकि प्रत्येक नेता एक दूसरे के संपर्क में आसानी से रह सकें. इसके अलावा, प्रत्येक ज़िले के डीएम व एसपी के मोबाइल व फैक्स नंबर भी इस निर्देशिका में अंकित है, ताकि जनता की समस्याओं को उन अधिकारियों तक भाजपा के लोग पहुंचा सकें. अरविंद सिंह ने बताया कि यह निर्देशिका भाजपा के लोगों को एक दूसरे में पिरोने का काम कर रही है.

– चौथी दुनिया ब्यूरो

भवन निर्माण में धांधली

चतरा ज़िले में विद्यालय भवन निर्माण कार्य में लगातार अनियमिताएं सामने आ रही हैं. इस संबंध में ज़िला शिक्षा अधीक्षक गंदौरी मिस्त्री के पास ग्रामीणों व कनीय अभियंता नवीन कुमार सिंह ने लिखित रूप में सूचना भी दी है. इसके बावजूद पांडेयपुर मध्य विद्यालय भवन निर्माण कार्य निर्वाध रूप से जारी है. बताते चलें कि मध्य विद्यालय के भवन का निर्माण बंगाल से सस्ते दामों पर लाए गए घटिया किस्म के ईंट से और विद्यालय के ही भवन से ईंट तोड़कर उसका निर्माण किया जा रहा है. यह भी जान लें कि जिस भवन का निर्माण ज़मीन पर होना था, उसका निर्माण तीसरी मंजिल पर किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापक सुरेंद्र यादव और सचिव महेंद्र राम कि मिलीभगत से यह काम हो रहा है.

वन महोत्सव संपन्न

चतरा ज़िले के डीएवी स्कूल में 64वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक प्रदीप कुमार थे और अतिथि के रूप में चतरा पुलिस अधीक्षक अनुप, हजारीबाग़ के वन संरक्षक फतेह बहादुर सिंह, चतरा के वन संरक्षक एसके गुप्ता, डीएफओ पीआर नायडू व एसके मेहरोत्रा भी उपस्थित थे. मुख्य अतिथी ने कहा कि वन है तो जीवन है, इसलिए हमें अपने जीवन में कम से कम दस वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए.

– अमरेंद्र सिंह

संस्कार समाज का गहना

देश और सूबे में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को लेकर परशुराम चेतना मंच ने सीतामढ़ी ज़िले के मेजरगंज प्रखंड के बसबीट्टा स्थित ऐतिहासिक सुकेश्वरनाथ स्थान में गत दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बिहार में पहली बार ब्राह्मण समाज ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है. ऐतिहासिक मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया. आचार्य नीरज शास्त्री उर्फ नीरु झा के साथ सह पुरोहित के रूप में शंभुनाथ झा, इंद्रजीत झा, ललन झा, राज किशोर झा व विकास झा ने यजमान हृदय नारायण सिंह को सराहनीय सहयोग किया. प्रो. दिगंबर मिश्र ने कहा कि देश की ज़मीन से वेद को लेकर चले जाने वाले विदेशी वर्तमान में वैज्ञानिक बने बैठे हैं. संस्कारों में कमी का खामियाजा वर्तमान में समाज को भुगतना पड़ रहा है. विभिन्न स्थानों से ब्राह्मण समाज से पहुंचे हज़ारों लोगों के बीच शिवहर के विजय कुमार पांडेय ने कहा कि वर्तमान में भटकाव को छोड़कर खुद को रास्ते पर लाने की आवश्यकता है. कार्यक्रम में सुशील कुमार झा, मुन्ना झा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मुरलीधर मिश्र, चुनचुन झा के अलावा दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए.

– वाल्मीकि कुमार

अशरफ अस्थानवी सम्मानित

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार तथा कई पुस्तकों के लेखक अशरफ अस्थानवी को खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए मैन ऑफ द इयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. राज्यपाल डॉ. डी. वाई. पाटिल ने राजभवन में आयोजित एक सादा कार्यक्रम में अशरफ अस्थानवी को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिये उन्हें सम्मानित किया. डॉ. पाटिल ने श्री अस्थानवी को मोमेंटो, प्रशस्ती पत्र तथा अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी. अशरफ अस्थानवी ने बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी प्रो. अब्दुल बारी के संघर्षपूर्ण जीवन पर आधरित अपनी नई पुस्तक राज्यपाल को भेंट की.

मदर टेरेसा जयंती

मोतिहरी नगर स्थित मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और अनेक रंगा-रंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतिया विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा दी गई. मौक़े पर मदर टेरेसा की जंयती भी मनाई गई और केक काटे गए. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सीआरपीएफ के कमांडेंट परम शिवम व विद्यालय की प्राचार्या डॉ. आशा मिश्रा ने संयुक्त रूप से केक काटे और समारोह को कामयाब बनाया. कमांडेंट श्री शिवम ने मौके पर सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बनने की सलाह दी. इस अवसर पर डॉ. रीचा भारद्वाज, विद्यालय के निदेशक एसके मिश्रा एवं पूर्व ज़िला पार्षद गीता सिन्हा आदि उपस्थित थे.

– इंतेज़ारुल हक़

रंग ला रही है राघवन की मेहनत

चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्णियां को ढ़ेरों उपलब्धियां मिली है. पूर्णियां शहर स्थित माता अनुपमा देवी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इन दिनों ख़ासा चर्चित है. कलकत्ता के प्रसिद्ध पूरे विश्व में दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले चिकित्सक डॉ. बीएन चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना प्रसिद्ध टेस्ट ट्यूब बेबी चिकित्सक डॉ. विजय राघवन ने की है. क्लीनिक से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों में यहां से 2,000 से ज़्यादा उम्रदराज लोगों को संतान प्राप्त हुआ है. डॉ. विजय राघवन ने जानकारी दी कि आईवीएफ विधी द्वारा सिंहेश्वर के 55 साल के दंपत्ति को संतान प्राप्ति हुई. इसके अलावा, झारखंड, बंगाल के नक्सलबाड़ी रायगंज, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, भूटान, चीन, नेपाल बंगलादेश, अमेरिकन सिटीजन, पटना, दिल्ली, राजस्थान के हज़ारों उम्रदराज दंपत्तियों को इस अस्पताल में संतान प्राप्ति हुई.

– नीरज

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

09 सितंबर–15 सितंबर 2013

पूर्व उप–मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार और गुजरात के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि यदि गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो बिहार के देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बनते, यदि बिहार के जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो गुजरात के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन पाते.

सीमांचल में माफ़ियाराज

यहां के उपजाऊ ज़मीन पर लगातार ईंट माफ़िया का राज बढ़ता जा रहा है. इससे यह ज़मीन गड्ढों और तालाबों में तब्दील होती जा रही है. सरकार और स्थानीय ज़िला प्रशासन को बार-बार ईंट माफ़िया के ख़िलाफ़ आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नीरज/कूलभूषण

पूर्णियां का मतलब पूर्ण आरण्य है. पहले सीमांचल का यह इलाका उपजाऊ भूमि, वनों और नदियों के लिए जाना जाता था, लेकिन ये सब अब अतीत की बातें हो चुकी हैं. विकास के नाम पर सीमांचल के प्राकृतिक संसाधन का दोहन लगातार जारी है. यहां पर उत्पन्न पर्यावरण संकट की एक मुख्य वजह ईंट भट्ठों की बढ़ती तादात भी है. मिट्टी की खुदाई की वजह से यहां की हज़ारों एकड़ उपजाऊ ज़मीन तलाबों और जलाशयों में तब्दील होती जा रही हैं. बताते चलें कि सीमांचल में पिछले दो दशकों में ईंट भट्ठों पर नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के ईंट कारोबारियों का है. पूर्णियां के खनन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीमांचल के पूर्णियां में 165 ईंट भट्ठे किशनगंज में 105, अररिया में 101 और कटिहार में लगभग 104 ईंट भट्ठे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं. इनमें से अधिकतर ईंट भट्ठे बारसोई अनुमंडल बायसी अनुमंडल, ठाकुरगंज, पोठिया, बहादुरगंज, किशनगंज बंगाल–बिहार की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं. सीमांचल में सबसे अधिक 60 ईंट भट्ठे ठाकुरगंज प्रखंड में स्थित हैं.

सीमांचल में ईंट भट्ठों को दो श्रेणियों में रखा गया है. ए श्रेणी के भट्ठों के लिए खनन राजस्व 74,500 रुपया और बिक्री कर 80,000 रुपया है, जिसमें 25 लाख ईंट तक का निर्माण हो सकता है. वहीं बी श्रेणी के भट्ठे के लिए खनन राजस्व 1 लाख, 35 हज़ार रुपये और बिक्री कर 1 लाख, 40 हज़ार रुपये है, जिसमें 35 लाख ईंट का निर्माण किया जा सकता है. विभाग के अनुसार सीमांचल में बी श्रेणी के ईंट भट्ठों की संख्या लगभग 13 है. जानकारों के मुताबिक पिछले दशकों में ईंट का सबसे बड़ा बाज़ार बंगाल के सिलीगुड़ी के रूप में उभरा है, जहां ईंट 5,800 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति हज़ार के दर से बिकता है, वहीं बिहार सरकार द्वारा 3,200 रुपये प्रति हज़ार के दर से ईंट का सरकारी मूल्य निर्धारित किया गया है. इसलिए ही बंगाल में बिहार के ईंटों को बेचने का व्यवसाय लाभकारी बना हुआ है. दूसरी तरफ़ बंगाल से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जलिंग, कूच बिहार एवं उत्तर दिनाजपुर ज़िलों में नए ईंट भट्ठे स्थापित करना कठिन हो गया है. ऐसे में बंगाल के व्यवसायियों के लिए सीमांचल का इलाका वरदान साबित हो रहा है. जानकारों का कहना है कि बंगाल के ईंट व्यवसायी सीमांचल के लोगों से संबंध स्थापित कर पार्टनरशिप के तहत ईंट भट्ठे खोल रखे हैं. इससे स्थानीय व्यवसायियों को वित्तीय मदद तो मिलती ही है, साथ ही असम के कोयले की निर्वाध आपूर्ति भी की जाती है. मिली जानकारी के अनुसार जहां ईंट भट्ठों के मालिकों द्वारा उपजाऊ भूमि का दोहन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है, वहीं ऐसे भट्ठा मालिक बिहार सरकार, भूदान बंदोबस्ती ग़रीब आदिवासी, दलित समुदाय को धन का प्रलोभन देकर उनके भूमि से मिट्टी काटने एवं भट्ठा स्थापित करने में भी लगे हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ईंट माफ़िया द्वारा स्थानीय आदिवासियों, दलितों को धन, शराब आदि का प्रलोभन देकर ईंट के लिए उपजाऊ मिट्टी का लगातार दोहन किया जा रहा है.

दीपक अग्रवाल

ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुड़बाघी बेसरबाटी, पथरिया, चुरली, पौआखाली, पोठिया प्रखंड के गौरूखाल शीतलपुर पंचायतों में एवं पूर्णिया के रौटा, अमौर, बायसी प्रखंडों में ऐसे अनेक भट्ठे मिल जाएंगे, जहां मिट्टी की खुदाई से भूमि जलाशय बन गए हैं. ठाकुरगंज के नावडुब्बा में स्थिति और भी भयावह बन गई है. यहां भारत–नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहने वाली मेची नदी के किनारे मिट्टी का इतना अधिक कटाव किया गया है, इससे ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कुछ ही दिनों में भारत से होकर बहने लगेगी. ठाकुरगंज के समाजसेवी राजीव कुमार ने नावडुब्बा में मेची नदी की धारा और भट्ठों द्वारा बने जलाशय को दिखाते हुए बताया कि अब मेची का पानी इन जलाशयों से होकर भारत में नए नदी मार्ग निर्माण कर सकता है, वहीं चार भट्ठों के बीच भारत–नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों का कैंप स्थित है. ये जवान प्रदूषण के साए में रहने को विवश हैं. लोजपा नेता किशनबाबू, ठाकुरगंज कांग्रेस के नगर अध्यक्ष खालीक अंसारी, आदिवासी मंगल मूर्मू का कहना है कि हम लोगों ने भूदान बंदोबस्ती, आदिवासियों एवं दलितों की भूमि को लेकर बिहार सरकार और किशनगंज ज़िला प्रशासन को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. भूमि सुधार उपसमाहर्ता कमर आलम विगत चार वर्षों से किशनगंज में पदास्थापित हैं. सूत्र बताते हैं कि ये अधिकारी खुद भूदान, बंदोबस्ती, बिहार सरकार के भूमि के मामले में कथित भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. किशनगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता सह बिहार भाजपा के क्रीड़ा मंच के उपाध्यक्ष वरूण सिंह ने कहा कि यहां के उर्वरा मिट्टी का लगातार दोहन हो रहा है और पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है.

बहादुरगंज–ठाकुरगंज–गलगलिया बंगाल बॉर्डर पथ (राज्य उच्च पथ 63) ओवरलोडेड ट्रकों के चलते निर्माण के एक साल के अंदर ही टूट गई. जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के ईंट भट्ठा मालिक केदार प्रसाद साह यहां के ईंट भट्ठों के यूनियन के अध्यक्ष हैं और बिहार से ईंट सिलीगुड़ी ले जाकर मंहगे दामों पर बेचने के धंधे में लिप्त हैं. पूर्णियां के खनन निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी लक्ष्मण राय का कहना है कि बिहार में सरल खनन क़ानून का लाभ दूसरे जगह के व्यवसायी उठा रहे हैं. जहां तक प्रदूषण का सवाल है तो यह प्रदूषण विभाग को देखना है, जिसका कार्यालय बेगूसराय में स्थित है. हम शत–प्रतिशत खनन राजस्व वसूल रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

लेनिनग्राद फतह करने में जुटी भाजपा

कभी बेगूसराय को वामपंथ का लेनिनग्राद कहा जाता था. उसकी सातों विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर वामपंथियों का क़ब्ज़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे यहां से वामपंथियों का सफाया हो गया और अब यहां भाजपा का वर्चस्व कायम है.

सुरेश चौहान

बेगूसराय में भाजपाइयों को इस बात का दंभ है कि यहां उनकी चलती है. यही वजह है कि किसी भी आयोजन में यह कहना वे बिलकुल नहीं भूलते हैं कि हमने लेनिनग्राद पर फतह पा लिया है. हाल के दिनों में भाजपा की गतिविधियां ज़िले में लगातार बढ़ी हैं. पिछले दिनों भी ज़िले में भाजपा ने विश्वासघात रैली का आयोजन किया और अपनी ताक़त का अहसास कराया.

जदयू से अलग होने के बाद भाजपा नरेंद्र मोदी को लेकर ज़्यादा आक्रामक तेवर में दिख रही है. सूबे के किसी भी ज़िले में भाजपा का कोई भी आयोजन हो नमो का जाप ही ज़्यादा सुनाई देता है. यही हाल बेगूसराय की रैली के दौरान भी देखने को मिला. इस रैली के दौरान भी अटल–आडवाणी की जगह नरेंद्र मोदी ही छाए रहे. एक सुर में उपस्थित सारे नेताओं ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए सक्षम उम्मीदवार बताया. इस रैली के दौरान नेताओं ने नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा जाता है कि भाजपा द्वारा पूर्व में आयोजित सभी रैलियों में यह बड़ी रैली थी. कई लोगों ने इस दौरान पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. साथ ही पार्टी का अंतर्कलह भी सामने आया. विधान पार्षद रजनीश कुमार व जिलाध्यक्ष संजय कुमार के समर्थक आपस में भिड़ गए.

पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता एवं महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू के संचालन में चली रैली को पार्टी के विधायक ललन कुंवर, सुरेंद्र मेहता, रामानंद राम शिवेश जी, विधान पार्षद रजनीश कुमार, पार्टी नेता उपेंद्र प्रसाद सिंह राम लखन सिंह कुंदन, अमरेंद्र कुमार, अमर ललन प्रसाद सिंह, शंकर सिंह, वंदना सिंह, अरविंद सिंह सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया. साथ ही सभा के दौरान स्थानीय नेताओं ने वरीय नेताओं को भरोसा भी दिलाया कि अगामी लोकसभा चुनाव में ज़िले से जो भी उम्मीदवार होगा, उसे एकजुट होकर जिताने का काम करेंगे. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राम, नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, प्रदेश उपाध्याक्ष मिथिलेश तिवारी ने भी उपस्थित जनसमुह को संबोधित किया, साथ ही लोगों को अक्टूबर में होने वाली हुंकार रैली में आने का न्योता दिया. नेताओं ने यह बताना नहीं भूला कि हुंकार रैली को नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे. पूर्व उप–मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार और गुजरात के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि यदि गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो बिहार के देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बनते, यदि बिहार के जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो गुजरात के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन पाते. उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के मोहन दास करमचंद गांधी को बिहार के चंपारण ने ही महात्मा गांधी बनाया था. अब बिहार उसी का अनुशरण करते हुए गुजरात के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रखा है. जदयू से गठबंधन टूटने के सवाल पर मोदी ने कहा कि अकेले राज करने की मानसिकता से नीतीश जी ने गठबंधन तोड़कर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया. भाजपाई वामपंथ के गढ़ में नरेंद्र मोदी के नाम पर भी नैया पार करने की जीतोड़ कोशिश करते दिखे. जिलाध्यक्ष संजय कुमार, स्वागत समिति के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, संयोजक कुमार साहेब, महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू, मीडिया प्रभारी मृत्यूजंय कुमार वीरेश सहित सभी भाजपाई रैली को सफल बनाने में जुटे दिखे. सिमरिया के राजेंद्र पुल से लेकर गांधी स्टेडियम बेगूसराय तक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग एवं पार्टी झंडा से सजे दर्जनों तोरणद्वार एनएच पर बनाए गए थे.

सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार कार्यकर्ता नेताओं के काफिले आगे चल रहे थे. पूरा शहर केसरियामय दिख रहा था, लेकिन पूरी सभा के दौरान एक भी नेता ने अयोध्या के 84 कोसी यात्रा, श्री तोगड़िया एवं श्री सिंहल के गिरफ्तारी की चर्चा तक नहीं की.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

09 सितंबर–15 सितंबर 2013

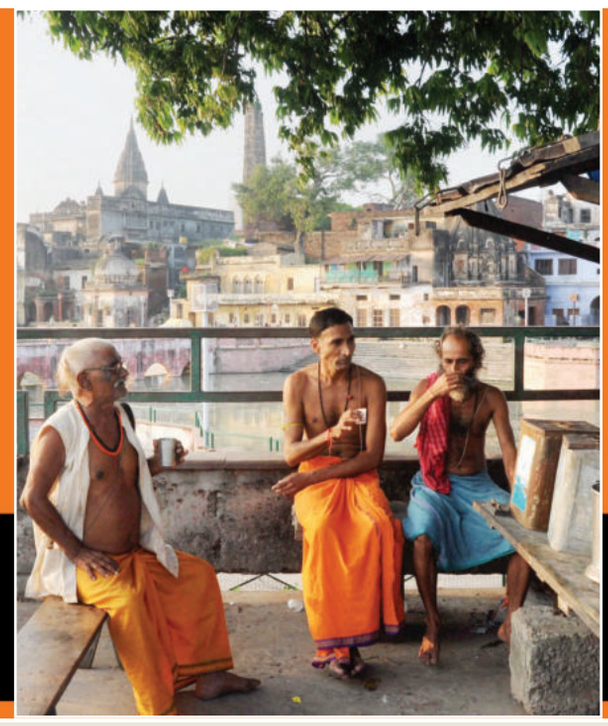

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

विधायकों की बलि पर साख़ बचाने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के तीखे तेवर देख सपा नेताओं में हड़कंप मच गया है. अखिलेश ने बदनामी का दाग धोने के लिए तीन दबंग, दुराचारी और दागी विधायकों–महेंद्र सिंह, राधेश्याम जायसवाल और रामलाल अकेला को निलंबित कर दिया है. दूसरी तरफ अपने को सुपर सीएम समझने वाले आजम खान को भी इशारों–इशारों में उनकी राजनीतिक हैसियत समझा दी है. अखिलेश के ये तेवर दर्शाते हैं कि अखिलेश अब अपनी छवि बदलना चाहते हैं.

संजय सक्सेना

बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए इसके समानांतर इससे बड़ी लकीर खींचने की चतुराई भरा कारनामा कहीं भी किसी वक्त किया जा सकता है. यह तर्कसंगत भले न हो, लेकिन इसको तर्कों के आधार पर मान्यता भी दिलाई जा सकती है. आजकल कुछ ऐसा ही कारनामा उत्तर प्रदेश के युवा मुंख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. तुनकमिजाज और सरकार तथा संगठन के लिए परेशानी बनने वाले सपा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा यह फार्मूला आजमाया जा रहा है. किसी नेता का कद छोटा किया जा रहा है तो किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. बदले–बदले से दिख रहे युवा मुख्यमंत्री का नया अंदाज और तीखे तेवर देखकर सपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. उन्होंने बदनामी का दाग धोने के लिए तीन दबंग, दुराचारी और दागी विधायकों–महेंद्र सिंह (सेवता, सीतापुर क्षेत्र), राधेश्याम जायसवाल (नगर सीतापुर, क्षेत्र) और रायबरेली के रामलाल अकेला को निलंबित कर दिया है. दूसरी तरफ अपने को सुपर सीएम समझने वाले आजम खान को इशारों–इशारों में उनकी राजनीतिक हैसियत समझाना यह दर्शाता है कि अखिलेश अब अपनी छवि बदलना चाहते हैं.

निलंबित विधायक महेंद्र कुमार सिंह, रोधेश्याम जायसवाल और रामलाल अकेला

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देर से ही सही, सख्ती के मूड में आ गए हैं, जो पार्टी और 2014 के चुनाव दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा. उन्होंने एक बार फिर हुंकार भरी है कि गुंडा भले आदमी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा. अपराधियों की जगह जेल में होगी. अखिलेश का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब इसकी जरूरत थी.

बात सपा से निकाले गए तीन विधायकों की कि जाए, इससे पहले डीपी यादव की चर्चा करना जरूरी है. आज भले ही मुख्यमंत्री के सामने दागी–दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर विश्वास का संकट हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय बाहुबली डीपी यादव को ऐन मौके पर सपा से दूर रखकर अखिलेश यादव ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. डीपी को आजम खान पार्टी में लाना चाहते थे. मुलायम भी इसके लिए लगभग सहमत हो गए थे लेकिन अखिलेश के अड़ जाने के कारण डीपी की सपा में इंट्री नहीं हो पाई थी. उक्त एक वाकये को छोड़ दिया जाये तो अखिलेश इसके बाद कभी भी सपा के दागी–दबंगों के खिलाफ सख्त नहीं दिखे थे. सत्ता हाथ में आते ही सपा विधायक इकबाल महमूद का स्टेशन पर घोड़ा दौड़ाना, कई विधायकों द्वारा हर्ष फायरिंग का मामला, पशु तस्करी के आरोप में घिरे गोंडा के विधायक और मंत्री केसी पांडेय, एक महिला आईएएस अधिकारी की तारीफ करके विवादों में आये राजाराम पांडेय, गोंडा के सीएमओ की पिटाई करने वाले राज्य मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, अवैध खनन के कारण बदनाम हुए विधायक और मंत्री भाटी, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त नटवर गोयल द्वारा लखनऊ में एक प्रेस फोटोग्राफर को मारने–पीटने समेत कई मामलों में सपा नेताओं के साथ वैसी सख्ती नहीं की गई, जैसी कि अबकी बार तीनों आरोपी विधायकों को निलंबित करके दिखाई गई. इन विधायकों के खिलाफ आरोप सामने आने के 24 घंटे के भीतर ही निलंबन की कार्रवाई कर दी गई.

बात आरोपों की करें तो सीतापुर के विधायक महेन्द्र सिंह गोवा में कॉल गर्ल्स के साथ पकड़े गए थे. इससे पूर्व भी वह कई बार बदमानी का दाग झेल चुके थे. वे सामूहिक बलात्कार के मामले में भी जेल जा चुके थे. कहा तो यह भी जाता है कि विधायक महेन्द्र सिंह का बेटा भी नकली नोटों के मामले में पकड़ा जा चुका था. बछरावां (रायबरेली) के विधायक रामलाल अकेला और सीतापुर नगर के विधायक राधेश्याम जायसवाल को अपने बेटों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ गई. रामलाल अकेला के दबंग बेटे ने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नसीर का निर्माणाधीन मकान बुलडोजर से गिराकर वहां लोहिया वाहिनी का बैनर टांग दिया था. इस मामले में विधायक अकेला का कहना था कि उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद ही बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को कह दिया था. जबकि सीतापुर नगर विधायक राधेश्याम के लड़कों ने किसानों की जमीन कब्जाने के लिए खुलेआम फायरिंग की थी. गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हो गए. राधेश्याम को भी निलंबित करने में सरकार ने काफी तेजी दिखाई. ऐसा लग रहा है कि सपा सरकार आम चुनाव से पूर्व संगठन और सरकार के स्तर पर सब कुछ ठीकठाक कर लेने को उतावली है.

तीन विधायकों पर गाज गिरने से सपा के इन विधायकों में भी खलबली मच गई है जो अपने कारनामों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं. यह और बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के इस रवैये से खुश नहीं हैं. माया ने एक बयान जारी करके कहा कि तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन कोई सजा नहीं है. गलत आचरण की वजह से तीनों को जेल भेजा जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि सपा के तो ज्यादातर विधायक आपराधिक रिकार्ड वाले हैं. माया की बात में तो दम है लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि जब वह सत्ता में थीं तो उन्होने भी तमाम मौकों पर ऐसा ही ढुलमुल रवैया अपनाया था. माया की बातों पर विश्वास न भी किया तो इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें भी ऐसे निलंबनों को कोई सजा नहीं मानती हैं. इससे माननीयों की सेहत व रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. वैसे भाजपा और कांग्रेस को भी तीन विधायकों को निलंबित करने की समाजवादी कार्रवाई ड्रामे से अधिक कुछ नहीं लग रही है.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौरासी कोसी परिक्रमा

सपा–भाजपा का मुनाफ़े का सौदा

चौरासी कोसी परिक्रमा के बहाने विहिप ने हिंदुत्व की भावना भड़काने की कोशिश की और वह अपने को इसमें सफल मान रही है. विहिप की ओर से कहा भी गया कि वह अपना संदेश देने में सफल रही है. सपा को भी इस पूरी कवायद में चुनावी फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों को कांग्रेस के पक्ष में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है. भाजपा भी प्रदेश में मुस्लिम मतों का रुख़ सपा की तरफ रखने में अपनी भलाई समझ रही है.

राकेश कुमार यादव

लोकसभा चुनाव–2014 तक हिंदुत्व की धार को तेज करने की रणनीति के तहत विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अयोध्या की नई चौरासी कोसी परिक्रमा भाजपा के साथ सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए भी मुनाफे का सौदा साबित हुई. परिक्रमा को विफल करने के लिए जहां पूरा प्रशासनिक अमला अयोध्या–फ़ैज़ाबाद को सुरक्षा घेरे में रखकर परिक्रमा आरंभ होने की घोषणा के पूर्व से ही हांफता रहा, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व की भावना भड़काने की कोशिश की और वह अपने को इसमें सफल मान रही है. विहिप की ओर से कहा भी गया कि वह अपना संदेश देने में सफल रही है. सपा को भी इस पूरी कवायद में चुनावी फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भावी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों को कांग्रेस के पक्ष में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है. भाजपा भी 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में मुस्लिम मतों का रुख सपा की तरफ रखने में अपनी भलाई समझ रही है. कांग्रेस

के पक्ष में मुस्लिम मतों का होना भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. गौरतलब है कि दो दशक पहले विहिप ने रामजन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा का आह्वान जब किया था, उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे. मुलायम ने ऐलान किया था कि कारसेवकों को किसी भी हाल में अयोध्या नहीं पहुंचने दिया जाएगा. इस दावे को अवकाश प्राप्त डीजीपी व संगठन के पदाधिकारी श्रीषचंद दीक्षित ने तार–तार कर दिया था. चौकसी तथा खुफिया व पुलिस की निगाहों को धोखा देते हुए दीक्षित विहिप के अशोक सिंघल को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे. सन 2003 में जब 17 अक्टूबर को अयोध्या कूच का आह्वान हुआ और एक बार फिर से सपा सरकार ने पाबंदियां लगाई, तब एक बार फिर विहिप के सामने अभेद्य किलेबंदी को भेदने की चुनौती खड़ी हुई. मौका आने पर अशोक सिंघल ने अयोध्या पहुंचकर पुराने तिलिस्म को बरकरार रखा. रामायणम भवन के पिछवाड़े से वह सामने आए और गिरफ्तार हुए. चौरासी कोसी परिक्रमा पर सपा सरकार के प्रतिबंध के बाद एकबार फिर दावा किया जा रहा था कि किसी विहिप पदाधिकारी को अयोध्या की सीमा तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा. इसी के चलते अशोक सिंघल को इलाहाबाद से दिल्ली भेज दिया गया. संगठन की रणनीति के तहत केंद्रीय महामंत्री डा. प्रवीण भाई तोगड़िया को अयोध्या पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई और सिंघल ने लखनऊ के मार्ग से अयोध्या पहुंचने की घोषणा की. एक–एक संत धर्माचार्य से लेकर विहिप के पदाधिकारियों की गतिविधि की टोह ले रही खुफिया टीम को पता भी नहीं

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

पृष्ठ 17 का शेष

विधायकों की बलि पर साख बचाने की कोशिश...

तीन विधायकों को निलंबित करके समाजवादी नेता भले ही फूले नहीं समा रहे हों, लेकिन इस पर गलत आचरण करने वाले कई नेताओं के खिलाफ अभी भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है. खासकर आजम खान के आचरण से समाज में काफी दुराव पैदा हो रहा है. वह दागी-दबंगों और दुराचारियों की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, लेकिन इनके श्रीमुख से निकले शब्दों में अच्छी-खासी दबंगई देखी जा सकती है. वह न तो मुलायम को कुछ समझते हैं न मुख्यमंत्री की कोई हैसियत उनके सामने है, परंतु एक ही झटके में अखिलेश यादव ने सभी भ्रम दूर कर दिया. काफी समय से उत्तर प्रदेश के चार अघोषित सुपर मुख्यमंत्रियों (मुलायम सिंह, आजम खान, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव) के रसूख के सामने दबे-दबे से महसूस कर रहे अखिलेश यादव में यह बदलाव लोगों को देखने में अच्छा लगा है. हां, आजम खान जैसे नेताओं को इससे जरूर धक्का लगेगा, जो समय-समय विवादित बयानों और आचरण से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं. अपने आप को मुलायम से भी बड़ा मुसलमानों का मसीहा समझने वाले आजम साहब की गलतफहमियों को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसा दिखा दिया है कि आजम खान की बोलती ही बंद हो गई. बात-बात पर इस्तीफा देना, अमेरिका को कोसना, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानने, वंदेमातरम का विरोध सहित तमाम अमर्यादित टिप्पणियां उनके खाते में दर्ज हैं. पूर्व सपा नेता अमर सिंह के कारण तो इन्हें सपा तक छोड़नी पड़ गई थी और अमर के सपा से जाने के बाद ही आजम की पार्टी में वापसी हो पाई थी. रामपुर के नवाब घराने से तो आजम का छत्तीस का आंकड़ा रहता है. दोनों ही एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. आजम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ एक ही तरफ से नहीं टूटा है. अदालत से भी उन्हें झटका मिला है. रामपुर की सीजेएम अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज मुकदमा वापस लेने से मना कर दिया. आजम के खिलाफ 2007 में स्वार टांडा विधानसभा उप चुनाव के दौरान आयोजित एक जनसभा में मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था.

पानी तब सिर से ऊपर चला गया, जब हाल में ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया. विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मुलायम की मुलाकात की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को काफी नागवार गुजरा. आजम अपने नेता मुलायम ही नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधने से नहीं चूके थे. वह खफा थे कि क्यों सीएम ने विहिप नेताओं से मुलाकात के लिए कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने के लिए मीडिया से मिलने का कार्यक्रम दो घंटे के लिए टाल दिया? इसके बाद ही एक आईएएस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कुमार को साम्प्रदायिक सोच का करार देकर नाराज चल रहे नगर विकास मंत्री आजम खान ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन पर निशाना साधा. आजम ने प्रवीर कुमार को साम्प्रदायिक विचारों वाला बताते हुए कहा कि प्रवीर के कारण ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं. आजम की बात मानने वाले 'सरकार' ने प्रवीर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन को ही आगे कर दिया. अहमद की गणना ईमानदार, अच्छी छवि वाले नेताओं में होती है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बातों-बातों में प्रवीर की तारीफ के पुल बांध दिए और कहा कि अच्छे कामों के लिए प्रमुख सचिव बधाई के पात्र हैं. जब अहमद हसन तारीफ कर रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. सीएम साहब तो पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तारीफ करते सुने जा चुके थे. उन्होंने भी प्रवीर की तारीफ को गलत नहीं ठहराया. इसी के बाद से यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या सपा पार्टी में एक नया मुस्लिम चेहरा उभर रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन की खासियत यह है कि वह अपने आप को मुख्यमंत्री की कैबिनेट का सदस्य मात्र समझते हैं. इनके विरोधियों की संख्या न के बराबर है. धार्मिक गुरुओं, पढ़े लिखे समाज और हिंदू-मुसलमानों सभी के बीच यह समान रूप से लोकप्रिय हैं, जबकि आजम खान खुद सीएम जैसा व्यवहार करते रहते हैं. आजम की पूरी राजनीति जौहर विवि के इर्द-गिर्द घूमती रहती है. कई मौलानाओं से उनके संबंध बेहद खराब हैं. हिंदू समाज में भी उनकी छवि अच्छी नहीं है. अबकी बार सपा के रोजा इफ्तार कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी आजम की जगह अहमद हसन के कंधों पर डाली गई थी, जो पहले के मुकाबले काफी हद तक सफल भी रहा था. आजम खान इस बात से भी खफा थे. अब अखिलेश के रुख से दिख रहा है कि आजम ने अति कर दी है और अब पार्टी उन्हें ज्यादा बरदाश्त करने के मूड में नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा-भाजपा का मुनाफे का सौदा

चल पाया और तमाम बैरियरों तथा निगाहों से बचते हुए डा. तोगड़िया अयोध्या पहुंच गए. गोलाघाट के सदगुरु शरण भवन मंदिर की घेराबंदी के बावजूद वहां से सरयू जल आचमन के लिए सरयू तट की ओर बढ़ निकले. रास्ते मे काफी कशमकश और धक्का-मुक्की के बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई. सोची-समझी रणनीति के तहत रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास के उत्तराधिकारी कमलनयन दास संतों समेत सरयू तट पर पहुंच गए और सरयू पूजन में सफल रहे. परंतु दूसरी तरफ विहिप के शीर्ष नेता अशोक सिंघल को लखनऊ में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया गया जिससे वे अयोध्या नहीं आ सके.

इस आंदोलन के दौरान विहिप ने बयान जारी कर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने संतों की अगुवाई में चौरासी कोसी परिक्रमा का 25 अगस्त रविवार को सरयू तट के गोलाघाट से श्रीगणेश किया है. श्रीरामजन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास को परिक्रमा की विधिवत शुरुआत करनी थी, परंतु उन्हें पहले ही मणिरामदास छावनी में नजरबंद कर दिया गया था. इसी के साथ छह जिलों में चलने वाली परिक्रमा का श्रीगणेश निर्धारित समय से एक घंटे बाद महंत कमलनयन दास ने सरयू का पूजन अर्चन व आचमन कर प्रतीकात्मक किया, उन्हें भी सरयू तट पर गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद एक साथ सभी पड़ाव स्थलों से पदयात्रियों के परिक्रमा में शामिल होने का दावा किया गया. परंतु इस दावे को खारिज करते हुए प्रशासन और पुलिस ने गोंडा, बस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बहराइच और फैजाबाद में विहिप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने घोषणा किया कि पदयात्रियों की गिरफ्तार से यात्रा को संत धर्माचार्यो के अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सरकार के मौलिक अधिकार हनन और धर्म विरोधी रवैये के खिलाफ देशभर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. परंतु धरना प्रदर्शन की कोशिश भी विफल करने में प्रशासन सफल रहा.

फिलहाल प्रशासन विहिप के चौरासी कोसी परिक्रमा को रोकने में भले सफल रहा हो और इसमें जनभागीदारी न रही हो, लेकिन हिंदू-मुस्लिम समुदायों में दूरिया बढ़ाने में विहिप का चौरासी परिक्रमा आंदोलन सफल रहा. जनमानस में दोनों सम्प्रदायों के मध्य एक दूसरे के प्रति दुराग्रह पनप गया है, जो गली कूचों और चौराहों पर चर्चाओं का विषय बन चुका है. माना जा रहा है कि आगामी मिशन 2014 में सपा व भाजपा के गुप्त समझौते का फायदा दोनों दलों को निश्चित रूप से मिलेगा और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनाने की राहें आसान नहीं रह पाएंगी. उत्तर प्रदेश की यदि 80 सीटों मे से 60 पर भी भाजपा और सपा कब्जा कर लेती हैं तो इसका असर कांग्रेस पर सीधे पड़ेगा. यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने और लंबा खींचने की योजना को गुपचुप ढंग से अमली जामा पहनाने में लगी है. अयोध्या में 18 अक्टूबर को पुन: हिंदुओं का जमावड़ा करने की घोषणा विश्व हिंदू परिषद ने कर दी है. सीधे-सीधे ऐलान किया गया है कि देश भर के हिंदू 18 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे और भव्य राम मंदिर का संकल्प लेंगे. इस आह्वान को लेकर भी अयोध्यावासियों की धड़कनें तेज होती दिख रही हैं क्योंकि किसी भी उग्र आंदोलन का असर सबसे पहले अयोध्यावासियों पर ही पड़ रहा है. बदले में उन्हें कर्फ्यू अथवा कर्फ्यू जैसे हालात से रूबरू होना पड़ता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महज वोट बैंक हैं पसमांदा मुसलमान

मुस्लिमों की कुल 44 जातियां हैं, जिसमें से चार उच्च जातियों-शेख, सैयद, मुगल, पठान को छोड़कर 40 जातियों की गिनती पसमांदा समाज में की जाती है. पसमांदा मुस्लिम बहुत पिछड़े हैं और अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं. राजनीतिक दलों में मुसलमानों का वोट बटोरने की होड़ तो लगी है, लेकिन उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर कोई नहीं दिखता. चुनाव नजदीक देख सभी दल मुसलमानों को लुभाने में लग गए हैं.

अजय कुमार

गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी काफी तौल कर बोलते हैं. उनकी आक्रामक शैली और बेबाक अंदाज के कारण बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आते दिख रहे हैं. उनके विरोधियों के लिए परेशानी यह है कि वह मोदी की बातों की काट नहीं खोज पा रहे हैं. परंतु मोदी के एक बयान पर खूब हाय-तौबा मची, जब वह मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए थोड़े उतावले दिखे. दरअसल, मोदी ने अपने बयान में पसमांदा मुस्लिम समाज को भाजपा के साथ जोड़ने की वकालत की थी.

गौरतलब है कि कुल मुसलमानों में पसमांदा समाज की आबादी करीब 85 प्रतिशत है. मुस्लिमों की 44 जातियां हैं जिसमें से चार उच्च जातियां शेख, सैयद, मुगल, पठान को छोड़कर 40 जातियों की गिनती पसमांदा समाज में की जाती है. पसमांदा मुस्लिम समाज की गिनती पिछड़े समाज में होती है और उन लोगों को आरक्षण का भी लाभ मिलता है. यह समाज काफी पिछड़ा हुआ है और अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है. विकास की लालसा इस समाज में भी अन्य लोगों की तरह ही हिलोरें मारती है, लेकिन सीमित संसाधन और अशिक्षा इसमें आड़े आ जाती है. इनका पिछड़ापन और अशिक्षित होना राजनीतिक दलों को खूब सुहाता है. पसमांदा समाज का दर्द है कि उस समाज की चालीस जातियों (यानी पिछड़े समाज) पर चार अगड़ी जातियां भारी पड़ रही हैं.

दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी दल उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं. चाहे सपा-बसपा हो या कांग्रेस अथवा राजद जैसे छोटे दल. सभी समय-समय पर उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाते हैं. इसी वोट बैंक को 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने पक्ष में खड़ा देखना चाहती है. भाजपा नेता नरेंद्र मोदी मानते हैं कि गुजरात में 20-25 फीसदी मुस्लिम भाजपा के लिये वोटिंग कर सकते हैं तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता. कट्टर हिंदू-वादी छवि वाले नरेंद्र मोदी के इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे तो पसमांदा समाज को भी समझते देर नहीं लगी कि मोदी को उनकी ताकत का एहसास है, लेकिन भाजपा के साथ जाने को लेकर पसमांदा समाज में थोड़ी सी भी सुगबुगाहट नहीं सुनाई देती है. पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी कहते हैं कि मोदी गलतबयानी कर रहे हैं. गुजरात विधान सभा चुनाव में 20-25 फीसदी मुसलमानों का भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने वाला मोदी का बयान भ्रामक है. हो सकता है कि एक-दो प्रतिशत मुस्लिम वोट उनके खाते में चले गए हों, लेकिन यह पसमांदा समाज के तो बिल्कुल नहीं होंगे और भाजपा के पक्ष में कुछ धनाड्य मुसलमानों ने अपने कारोबारी हित साधने के लिए मतदान कर दिया हो, लेकिन यह बात भी प्रमाणिकता के साथ नहीं कही जा सकती है.

फोटो-सुनील मल्होत्रा

पसमांदा समाज को आज भी यही लगता है कि विभिन्न पार्टियों में बैठे मुस्लिम नेता मुसलमानों और खासकर पसमांदा समाज की परवाह न कर सिर्फ अपने लिए कुर्सी हथियाने तथा अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते रहे हैं. पसमांदा मुसलमानो के खस्ताहाली के लिए केंद्र में सत्ताधारी पार्टियां तथा कथित मुस्लिम लीडर ही जिम्मेदार हैं. पसमांदा समाज की स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई है. केंद्र और राज्य सरकारों की उपेक्षा के चलते पिछड़ी जातियों कसगर, राईन, गूजर, गद्दी, घोसी, चिकवा, कुरैशी, छीपा, जोगी, झोजा, हाश्मी, तमोली, तेली, सामानी, अर्राक, इदरीसी, नायक, फकीर, मुकेरी, सैफी, बारी, मनिहार, अंसारी ,मिरासी, मुस्लिम कायस्थ, रहमानी, नद्दफा, धुनिया, मंसूरी, रंगरेज, सुनार, हला-लखोर, लालबेगी, हलवाई, सलमानी, अब्बासी, मशालची, धोबी, नानबाई, मीरशिकार, शेखर सरवरी, मेवाती, संगतराश, मोची ,माहीगीर, कलाल नट आदि के पुश्तैनी काराबोर समाप्त हो गए हैं, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया हैं. भीषण मंहगाई के चलते पसमांदा समाज के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा संभव नहीं हो पा रही है. उत्तर प्रदेश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पसमांदा मुसलमानों का कुटीर उद्योग मृत्यु शैया पर कराह रहा है, लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं दे रहा है.

गौरतलब हो, पसमांदा मुसलमानों की इस कड़वी सच्चाई का जिक्र राजेंद्र सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपने रिपोर्ट में किया था. पसमांदा मुसलमानों की आबादी मुसलमानों की कुल आबादी के 85 प्रतिशत से अधिक है. इस संख्याबल का एहसास सरकार एवं सभी राजनीतिक पार्टियों को है और वे इनका वोट पाने के लिए बेचैन हैं. पसमांदा समाज अक्सर पूछता रहता है कि एक तरफ हिंदू पिछड़ी जातियों को सभी क्षेत्रों में इनकी आबादी के अनुपात में समायोजित किया जाता है, लेकिन जब मुसलमानो की भागीदारी की बात आती है तो केवल मुसलमान के नाम पर ही क्यों उन्हें देखा जाता है? हिंदू पिछड़ी दलित जातियों की तर्ज पर पिछड़े दलित मुसलमानों को समायोजित किया जाना चाहिए ताकि पिछड़े दलित मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके. उसका लाभ 15 प्रतिशत मुसलमान ही उठाते हैं, जबकि 85 प्रतिशत पसामांदा मुसलमान इस लाभ से वंचित हो जाता है. इस अन्याय को पसमांदा मुसलमान किसी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेगा. पसमांदा समाज को इस बात का मलाल है कि अगड़े कहे जाने वाले मुसलमान भी उनके साथ नहीं खड़े होते हैं.

पसमांदा समाज की मांगें

पसमांदा समाज की कई मांगे वर्षों से पूरी नहीं हो पाई हैं. समाज के नेता अनीस अंसारी कहते हैं कि संविधान की धारा 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध समाप्त कर हिंदू, सिख एवं बौद्ध अनुसूचित जातियों को समस्त लाभ प्रदान किया जाए. पसमांदा ममुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार राजनीतिक पदों हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाए. सच्चर आयोग एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पसमांदा मुसलमानों की हालत हिंदू अनुसूचित जातियों से काफी बदतर है. अत: पसमांदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण कानून से बाहर रखा जाए, ताकि उनको उत्पीड़न से बचाया जा सके. पिछड़ी जातियों को मिल रहे 27 प्रतिशत आरक्षण में से पिछड़े मुसलमानों की आबादी के अनुसार 9 प्रतिशत आरक्षण अलग से निर्धारित किया जाए. सभी राजनीतिक क्षेत्रों मे पसमांदा मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी दी जाए. पसमांदा मुसलमानों के विकास हेतु पसमांदा मुस्लिम आयोग का गठन किया जाए. राज्य सरकार द्वारा गठित समस्त आयोगों बोर्ड व निगमों में पसमांदा मुस्लिम समाज का एक सदस्य अथवा अध्यक्ष नामित किया जाए. अधिकारी/कर्मचारी चयन आयोगों में पसमांदा मुस्लिम समाज का एक सदस्य नामित किया जाए. पसमांदा मुस्लिम समाज के पैतृक पेशों के उत्थान हेतु अनुदान की योजना में संचालित किया जाए. साथ ही पसमांदा मुसलमानों के उत्थान हेतु उद्योग-धंधों, व्यापार आदि करने हेतु ब्याज मुक्त सब्सिडी ऋण की योजना बनाई जाए. राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक मुस्लिम संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं की प्रबन्ध कमेटी में 50 प्रतिशत पसमांदा मुलसमानों का पद आरक्षित किया जाए. राज्य सरकार के अनुदान पर संचालित स्वैच्छिक मुस्लिम संस्थाओं में आबादी के अनुरूप पसमांदा मुस्लिम समाज के 85 प्रतिशत छात्रों/लाभार्थियों को प्रवेश दिलाने हेतु वरीयता प्रदान की जाए.

भाजपा-कांग्रेस दोनों से है नाराजगी

पसमांदा समाज की नाराजगी भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही नाराजगी है. भाजपा की मुस्लिम विरोधी सोच और कांग्रेस की मुसलमानों के प्रति अनदेखी दोनों ही पसमांदा समाज को रास नहीं आती है. यही वजह है जहां एक तरफ भाजपा को हाशिये पर रखने के लिए पसमांदा समाज कांग्रेस के साथ खड़े रहने मे ही अपनी भलाई समझता है, वहीं कांग्रेस के सामानांतर कोई विकल्प मिल जाने पर कांग्रेस को भी अनदेखा कर देता है. इसी के चलते उत्तर प्रदेश में पसंमादा समाज सपा और थोड़ा बहुत बसपा के साथ खड़ा नजर आता है. यही हाल बिहार का है. वहां भी समाज का रुझान जदयू की ओर पिछले विधान सभा चुनाव में रहा था. वहीं गुजरात जैसे राज्य में कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह कांग्रेस के साथ खड़ा रहने में ही भलाई समझता है. उड़ीसा में बीजू जनता दल, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों और ममता बनर्जी के साथ, तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि को पसमांदा मुसलमान अपना समर्थन देते रहे हैं.

बात लोकसभा चुनाव की करें तो यही इतिहास 2014 में भी दोहराए जाने की उम्मीद है. भाजपा को हराने के लिए ही पसमांदा समाज घरों से वोटिंग करने निकलेगा. सामने अन्य विकल्प हों तो ठीक, वरना कांग्रेस तो है ही. उप्र में सपा सरकार पसमांदा मुसलमानों को लुभाने के लिए तरह-तरह के पैंतरे आजमा रही है. अल्पसंख्यक कब्रिस्तानों के अवैध कब्जों को रोकने के लिए चहारदीवारी का निर्माण, दसवीं पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु तीस हजार रुपये का अनुदान, सरकारी योजनाओं तथा कमीशनों, बोर्डो और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि नामित करने का वादा पूरा करके फिलहाल सपा अल्पसंख्यकों, उसमें भी पसमांदा समाज के मुस्लिमों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन उर्दू पत्रकार हाजी नवी बक्श की राय जुदा है. वह कहते हैं कि सरकारी योजनाओं में बीस प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण सरकारी दिखावा है. सरकार को अगर सही में मुसलमानों की दशा सुधारनी है तो उसे उन तमाम आयोगों के अध्यक्ष पद भरने होंगे जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं. अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी, शिया वक्फ बोर्ड के पद सपा सरकार के 17 महीने के कार्यकाल के बाद भी खाली पड़े हैं, जबकि अन्य वर्गों के आयोगों के साथ ऐसा नहीं है. अध्यक्ष न रहने के कारण केंद्र का पैसा वापस चला जाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी और आज़म में धर्मनिरपेक्षता की होड़

दर्शन शर्मा

नरेंद्र मोदी का भूत केवल कांग्रेसियों को ही नहीं डराता, बल्कि सपा सरकार में भी उनके बढ़ते इकबाल से बेचैनी बढ़ने लगी है. स्थिति यह है कि गुजरात में मोदी जो कुछ भी करते या बोलते हैं, उसकी आहट उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगती है. क्योंकि मोदी के राजनीतिक कारनामे बरबस ही लोगों के बीच सुर्खियां बन जाते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री मोदी ने राखियां बंधवाईं तो एक अल्पसंख्यक तबके की बच्ची से. यह खबर खूब चर्चा का विषय बनी. इससे मानो मोदी के सदभावना उपवास के दौरान टोपी न पहनने का दाग मुस्लिम बच्ची से राखी बंधवाने से धुल गया हो. मुस्लिमों में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे मोदी के इस कारनामे की भनक जब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता आजम खान को पता चली तो उन्होंने भी जवाब में ऐसा कर दिखाने की ठानी. वे अचानक 21 अगस्त को हरिद्वार के कालीमठ में माथा टेकने पहुंच गए. मंदिर के महंत कैलाशनंद ब्रह्मचारी ने उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाई और प्रसाद ग्रहण कराया. एक कट्टर छवि के मुस्लिम नेता का मंदिर में आकर माथा टेकना और माला पहनना कुछ साधु संतों को नागवार गुजरा. महंत के सामने मुसीबत खड़ी हो गई. वे आजम के अचानक हरिद्वार आने का कारण समझ न पाए. वह भी तब जब अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर दहशत का माहौल हो और लखनऊ न छोड़ने की बात कह चुके हों, साधु संत यात्रा के लिए अड़े हों, अयोध्या के आसपास के जिले छावनी में बदल रहे हों. सरकार और विश्व हिंदू परिषद आमने-सामने हों. सरकार साधु संतों को नजरबंद करने पर आमादा हो. तब एक मुस्लिम नेता का अचानक किसी मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला पहनकर माथा टेकना हर किसी को हैरत में डालने वाला था. राजनीतिक जानकर आजम खान के इस हृदय परिवर्तन के पीछे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताते हैं. उनका मानना है कि मंदिर में माला पहनने का राज भले ही किसी को समझ में न आ रहा हो, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, वह है मोदी का खुद को धर्मनिरपेक्ष बनाकर पेश करना. दोनों में धर्मनिरपेक्ष दिखने की होड लगी है. चूंकि आजम समझते हैं कि यदि मोदी का उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों पर जादू चल गया तो वे और उनकी पार्टी कहीं की नहीं रह जाएगी. इसकी काट आजम को यही सूझी कि जब मोदी मुस्लिम बच्ची से राखी बंधवा सकते हैं तो क्या वह किसी मंदिर में जाकर रुद्राक्ष पहनकर मत्था भी नहीं टेक सकते? विदित हो कि आजम खान की मुलाकात इसके पहले महंत कैलाशानंद से इलाहाबाद में जून माह में हो चुकी है. कुल मिलाकर प्रदेश में वोटों की राजनीतिक बिसातें बिछाई जा रही हैं. जहां हिंदुत्ववादी मोदी मुस्लिमों पर डोरे डाल रहे हैं, वहीं मुस्लिम नेता आजम हिंदू वोटों के उनकी काट पेश करने में लगे हैं. ■

> **मुस्लिमों में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे मोदी ने जब मुस्लिम बच्ची से राखी बंधवाई तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता आजम खान ने भी इसके जवाब में ऐसा कर दिखाने की ठानी. वे अचानक 21 अगस्त को हरिद्वार के कालीमठ में माथा टेकने पहुंच गए. मंदिर के महंत कैलाशनंद ब्रह्मचारी ने उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाई और प्रसाद ग्रहण कराया.**

feedback@chauthiduniya.com

उम्मीदवारों के चयन पर भाजपा मुश्किल में

पूर्वी जिलों के आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर सहित अन्य जनपदों में सपा, बसपा और कांग्रेस के हालात बेहद खराब हैं. जो भी नेता हैं, उनमें से ज्यादातर हवा-हवाई हैं. जमीन से जुड़े नेता कम हैं. फिलहाल पूर्वांचल के जिलों में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर अभी तक चल रहा है, कहने को कोई कांग्रेस कहे या सपा, बसपा, का कहे पर हिंदुत्व के नाम पर ज्यादातर हिंदू अब मोदी को ही वोट करना चाहता है. पर क्या मोदी यहां के लोगों को रिझा पाएंगे?

शिवनाथ चतुर्वेदी

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर व इलाहाबाद मण्डल की 19 लोकसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर पिछड़ी जाति के मतदाताओं की तादाद 30 से 45 फीसदी तक है. इन सभी सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है. नरेंद्र मोदी के पार्टी में बढ़े बर्चस्व और दखल के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह अंदरूनी दबाव और गुटीय चालों के सामने लाचार और बेबस बने हैं. पिछड़ी बहुल इन सीटों के पिछले चुनाव नतीजों को देखा जाए तो वे भाजपा के लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषक गोरखपुर दिवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकारनाथ मेहता के अनुसार भाजपा जातीय संतुलन बनाकर, उनके बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाती है. भाजपा के लिए अगला लोकसभा चुनाव मुश्किल भरा साबित हो सकता है. मोदी पर छिड़ी बहस के बाद हर वर्ग में वे चर्चा में आ गए हैं. इसका सीधा नुकसान लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, और कांग्रेस को होता दिख रहा है. जहां तक सपा का सवाल है तो उसका सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग माने जाते हैं. सपा को गत चुनाव में ब्राह्मणों का पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार सपा के लिए ब्राह्मणों को रिझा पाना इतना आसान नहीं होगा. इस बार अल्पसंख्यकों के साथ यादव वोट भी सपा से खिसक रहा है. इसका कारण अल्प संख्यकों को तवज्जो देना और दूसरे लोगों को दरकिनार करना है. वैसे भी सपा नेताओं को अब अल्पसंख्यकों के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादव वोट भी इस बार मोदी की ओर नजरें टिकाए हुए हैं. ये वोट देंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा, पर जिस तरह यादव सपा के खिलाफ तीखे बोल रहे हैं, उससे साफ लगता है कि सपा लोकसभा चुनाव में उम्मीद से काफी पीछे नजर आ रही है. फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा ने जिन लोगों को टिकट दिया है वे भी दमदार नहीं हैं. बसपा का पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जनाधार माना जाता है वह 2014 लोकसभा चुनाव में कम नजर आएगा. इसका कारण बसपा नेताओं की करतूते हैं. दूसरा कारण है कि बसपा सरकार ने अरबों रुपये पत्थरों में लगा दिए, पर पूर्वांचल के विकास को दरकिनार कर दिया. उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार जाने के बाद जनता के बीच इसका खास कारण भी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो सांसद और विधायक चुने गए हैं, उनकी हालत बेहद नाजुक है. फोन न उठाना, लोगों की समस्याओं को नजरअदांज करना और विकास नहीं होने से जनता परेशान है.

मायावती के खिलाफ जो इस बार दलितों के तेवर नजर आ रहे हैं. वह तीखे हैं और इससे लगता है कि दलित भी मायावती से नाराज हैं. हालांकि पूर्व विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा को दलितों ने ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण, कुशवाहा, चौहान समेत दूसरे लोगों ने वोट किया था, पर आज ये सभी नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं. दलितों की सोच है कि मायावती प्रधानंत्री बन नहीं सकती. सपा केंद्र में सरकार बनाने से दूर है. कांग्रेस और भाजपा में से ही किसी की केंद्र में सरकार बन सकती है.

यदि देखा जाए तो पूर्वी जिलों के आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर सहित अन्य जनपदों में सपा, बसपा और कांग्रेस के हालात बेहद खराब हैं. जो भी नेता हैं उनमें से ज्यादातर हवा-हवाई हैं. जमीन से जुड़े नेता कम हैं. फिलहाल पूर्वांचल के जिलों में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर अभी तक चल रहा है, कहने को कोई कांग्रेस कहे या सपा, बसपा, का कहे पर हिंदुत्व के नाम पर ज्यादातर हिंदू अब मोदी को ही वोट करना चाहता है. पर क्या मोदी यहां के लोगों को रिझा पाएंगे?

फिलहाल तो जगह-2 आजकल मोदी को लेकर लोगों में बहस छिड़ी हुई है. पलड़ा किसका भारी रहेगा. इस पर तो कुछ कहा नहीं सकता, पर जो आज हालात है, वह किसी से छुपी नहीं है, अब तो हालात यह हो गई है कि विपक्षी भी मोदी के नाम पर चुप्पी साध जाते हैं. लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और मोदी के नाम पर चर्चा जोर पकड़ने लगी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी की मुहिम को रोक रही हैं विहिप और सपा

संजय सक्सेना

विहिप के मंदिर अभियान के आगे उत्तर प्रदेश में मोदी की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है. चुनावी मौसम में विश्व हिंदू परिषद जैसे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की अति तेजी और प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं की विहिप के समर्थन में बढ़-चढ़कर बयानबाजी से मोदी के चुनावी मिशन के मुद्दे हल्के पड़ते जा रहे हैं. मोदी टीम मंहगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असफलता, विदेशी जमीन से मिल रही चुनौतियों, किसानों की आर्थिक दुर्दशा, कालाबाजारी जैसी नाकामियों के सहारे केंद्र सरकार को तो कानून व्यवस्था, दागी-दबंगों को संरक्षण, ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न, भाई-भतीजावाद, खनन माफियाओं को सरकारी संरक्षण और तुष्टिकरण के बहाने समाजवादी सरकार को घेरना चाहती है. मोदी नहीं चाहते हैं कि उनकी हिन्दुत्ववादी छवि का ज्यादा प्रचार-प्रसार हो. वह विकासपुरुष के रूप में अपने को देश और दुनिया में पेश करना चाहते हैं. मोदी के करीबी अमित शाह भी प्रदेश भाजपा नेताओं की गुटबाजी के चलते अपने आका मोदी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि वह हिन्दुत्व की लड़ाई तो लड़ती है, लेकिन हिन्दुओं की मानसिकता को पढ़ नहीं पाती है, वहीं समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार मुसलमानों की मनोदशा को अच्छी तरह से जानती समझती है, और उसी के अनुसार फैसले लेती है. सब जानते हैं कि मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए ही अखिलेश सरकार ने अयोध्या की चौरासी कोसी परिक्रमा को हरी झंडी देने के चंद घंटों बाद राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस पर रोक लगाई. इस रोक को हाई कोर्ट ने सही ठहराया तो युवा सीएम की खुशी परवान चढ़ गई. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि विगत विधानसभा चुनावों में भाजपा मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई. उप-चुनावों में उसकी प्रतियोगिता कांग्रेस से तीसरे-चौथे पायदान पर आने की रही. अब लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को अपनी नैया पार होते नहीं दिख रही है. भाजपा के डूबने के डर के साथ उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साख पर भी ग्रहण लगने वाला है. चूंकि भाजपा के पास जनता को आकर्षित करने वाला कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आरएसएस ने इसके बचाव में संत महात्माओं को मोहरा बनाने और सांप्रदायिकता को उभारने की साजिश शुरू कर दी है.

सपा नेता अनीस मंसूरी कहते हैं कि विहिप, आरएसएस और भाजपा अयोध्या में जिस चौरासी कोसी परिक्रमा के बहाने सियासी साजिश रच रही हैं, उसके होने का कोई पूर्व प्रमाण नहीं मिलता है. सब जानते हैं कि अयोध्या में कोई परिक्रमा अगस्त-सितंबर में नहीं होती है. स्पष्ट है कि यह प्रस्तावित यात्रा धार्मिक नहीं सियासी है. संघ-भाजपा एक राजनीतिक एजेंडे के तहत यह मामला उछाल रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके. 1992 में भाजपा-संघ-विहिप इसी तरह एक जैसी भाषा बोल रहे थे, नतीजतन विवादित ढांचा ध्वंस हुआ था. उन दिनों केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसने ऐसी ही चुप्पी साध रखी थी. कांग्रेस को भाजपा की चाल में शायद अपना भी कुछ स्वार्थ सधता दिखाई दे रहा होगा.

सपा सरकार को डर सता रहा है कि कहीं प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, सरकार में अराजकता की स्थिति आदि सरकारी कमजोरियां चुनावी मुद्दा न बन जाएं, इसलिए इसकी तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा कर इधर-इधर बांटा जा सके. 84 कोसी परिक्रमा पर रोक से शुरू हुआ यह खेल आगे बढ़ता हुआ कोटे की राजनीति पर पहुंच गया. अखिलेश सरकार द्वारा हाल में ही मुलसमानों को खुश करने के लिए सरकार की योजनाओं में बीस प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटा लागू कर दिया गया. एक तरफ सपा ऐसे फैसले लेकर मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश सरकार के फैसलों को तुष्टिकरण से जोड़कर भाजपा हिंदुत्व की अलख जगा रही है. सपा सोची-समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है. वह नहीं चाहती है कि यूपी में लड़ाई कांग्रेस-भाजपा के बीच लड़ी जाए. केंद्र सरकार को जनहित के मुद्दों पर कम से कम समाजवादी पार्टी तो घेर नहीं सकती है, क्योंकि वह भी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही समस्याओं से रूबरू हो रही है, इसलिए सपा अलग ढर्रे पर चल रही है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, उसी के आधार पर राजनीतिक पंडित आम चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं. यही सब राजनीतिक स्थितियां और माहौल आरएसएस के माथे पर बल डाले हुए है. उसको उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिस्थितियों में 'मिशन मोदी' सफल होता नहीं दिख रहा.

मोदी नहीं चाहते हैं कि उनकी हिन्दुत्ववादी छवि का ज्यादा प्रचार-प्रसार हो. वह विकास पुरुष के रूप में अपने को देश और दुनिया में पेश करना चाहते हैं, लेकिन विहिप और सपा के चौरासी कोसी प्रक्रिमा के गणित ने मुद्दा ही बदल दिया. राजनीतिक दलों के नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, उसके आधार पर राजनीतिक पंडित आम चुनाव में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं. यह सब स्थितियां और माहौल आरएसएस के माथे पर बल डाले हुए है. उसको उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिस्थितियों में मिशन मोदी सफल होता नहीं दिख रहा.

उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा और उसकी काट के लिए संघ-भाजपा की बैठकों का दौर चल रहा हैं. पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ओमप्रकाश सिंह, सूर्यप्रताप शाही, विनय कटियार, लालजी टंडन और रमापति राम त्रिपाठी जैसे तमाम नेताओं को इन बैठकों में देखा जा सकता है. ऐसी बैठकों में संघ के सह-सरकार्यवाह सुरेश सोनी उक्त नेताओं से बस एक ही बात कहते हैं. चारों ओर नरेंद्र भाई मोदी की हवा है, लेकिन इसे वोट में कैसे बदला जाएगा. संगठन नहीं होगा तो वोटर घर से निकल कर बूथ तक पहुंचेगा कैसे? उसके भीतर बटन दबाने के लिए जरूरी ऊर्जा कौन भरेगा. एक बूथ पर दस यूथ कैसे तैनात किए जाएंगे. यह चिंता सोनी की ही नहीं है. संघ और दिल्ली में बैठे बड़े भाजपा नेता और सोनी की तरह ही प्रदेश भाजपा के प्रभारी अमित शाह का भी सबसे अधिक जोर बूथ कमेटियां बनाने और नये युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर है. इसके लिए शाह ने केंद्रीय आलाकमान से दोगुना आगे बढ़कर एक बूथ पर 10 की जगह 20 यूथ का लक्ष्य रखा गया है. एक हजार युवाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले कर्मयोगियों को नरेंद्र मोदी के साथ चाय पिलाने और हाथ मिलाने का मौका ईनाम के तौर पर मिलेगा. भाजपा की समस्या यहीं से हल नहीं हो जाएगी, इसके लिए उसे अपने नेताओं की अति महत्वाकांक्षा पर लगाम लगानी होगी. भाजपा नेताओं को गुटबाजी और व्यक्तिगत हितों से ऊपर जाकर संगठन मजबूत करना होगा.भाजपा की सोच तो काफी बढ़ी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है. अभी ज्यादातर जिलों मे बूथ कमेटियां ही नहीं बन पाई हैं, जब इस संबंध में सवाल खड़ा किया जाता है तो पार्टी के बड़े नेता कोई जल्दबाजी नहीं करने की बात करते हुए कहते हैं, कि पहले टिकट बंट जाए फिर उम्मीदरवारों से राय मशविरा करके इस काम को पूरा कर लिया जाएगा. टिकट को लेकर अभी तक आलाकमान कोई गाइड लाइन नहीं तय कर पाया है.

सपा और बसपा ने जहां इस मामले में काफी बढ़त बना ली है, वहीं कांग्रेस और भाजपा फंसी हुई हैं. कांग्रेस को तो कई सीटों पर अच्छे दावेदार तक नहीं मिल रहे हैं. कांग्रेस और भाजपा को यूपी से काफी इम्मीदें हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों (सपा-बसपा) से मिल रही चुनौती उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. जीत के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जनता को बांटने का जतन किया जा रहा है. वहीं राजनीतिक पंडितों को लगता है कि जाने-अनजाने भाजपा सपा के बुने जाल में फंसती जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

09 सितंबर–15 सितंबर 2013

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल ताजमहल की गिनती देश के अग्रणी स्मारकों में की जाती है. पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती और बनावट को देख कर वाह–वाह करने लगते हैं, लेकिन जब उनकी नजर आस–पास की गंदगी, अव्यवस्था आदि पर जाती है तो आह निकल जाती है. मगर अब ऐसा नहीं होगा. सरकार यहां पर निर्माण कार्य कराने जा रही है.

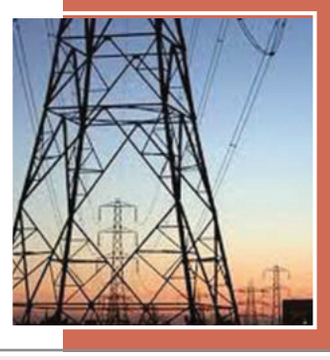

उत्तराखंड डायरी

प्रकृति से छेड़छाड़ बनी आपदा का कारण

राज्य की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं यह मानती हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही दैवी आपदा का कारण है. ढाई माह पहले उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा हर किसी पर बिपदा बनकर आई है. आपदा के चलते हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं. आपदा ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि आपदा प्रभावित इलाकों में लोग अब जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. महिलाओं पर भी आपदा की मार भारी पड़ी है. कई महिलाओं का सुहाग उजड़ चुका है. उत्तराखंड महिला मंच व प्रगतिशील महिला मंच से जुड़ी जागरूक महिलाओं ने आपदा के बाद उपजे ऐसे ही हालातों पर चर्चा की. रेसकोर्स स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में आयोजित विचार गोष्ठी में महिलाओं का कहना था कि प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ ही इस तरह की भयावह प्राकृतिक आपदा का कारण है. उत्तराखंड में आई आपदा, महिलाएं एवं वर्तमान स्थिति विषयक विचार गोष्ठी में महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा कि उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग संवेदनशील है. भूस्खलन, भूकंप, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं कुछ-कुछ अंतराल बाद राज्य में कहर बरपा रहीं हैं. बावजूद इसके सरकारी तंत्र की तंद्रा टूट नहीं रही है. संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित विकास हो रहा है. नदी घाटियों पर धड़ल्ले से बांध परियोजनाएं बन रहीं हैं. बाहरी शक्तियां जल, जंगल व जमीन पर कब्जा जमा रहीं हैं. नतीजतन प्रकृति में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है. प्रगतिशील महिला मंच की संयोजक विमला बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से हजारों लोग बेघर हो गए हैं. सड़क व संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है. महिलाओं को चारे व लकड़ी के लिए कई किमी दूर जाना पड़ रहा है. रसोई गैस का भारी संकट बना हुआ है. महिला समाख्या की परियोजना निदेशक गीता गैरोला ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सभी को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए. निर्मला बिष्ट ने कहा कि आपदा से पहले ही नहीं बल्कि आपदा के बाद भी आपदा प्रबंधन के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. पुनर्निर्माण व पुनर्विकास के लिए वैज्ञानिक तौर-तरीकों को अमल में लाया जाना चाहिए.

नंदा राजजात यात्रा अगले वर्ष 17 अगस्त से

श्री नंदादेवी राजजात यात्रा अगले वर्ष 17 अगस्त 2014 से प्रारंभ होगी. नौटी में नंदादेवी राजजात समिति के अध्यक्ष कुंवर डॉ. राकेश सिंह ने इस वर्ष राजजात स्थगित होने पर क्षमा याचना शांति पाठ यज्ञ के पश्चात इस आशय की घोषणा की. नंदा देवी सिद्धपीठ नौटी में इस वर्ष स्थगित हुई राजजात यात्रा के लिए क्षमा याचना शांति पाठ यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस मौके पर लोगों ने मां नंदा देवी से यात्रा स्थगित होने पर क्षमा याचना करते हुए लोक कल्याण के निमित शांति पाठ यज्ञ में प्रतिभाग किया. इसके पश्चात राजजात समिति के अध्यक्ष राकेश सिंह ने 2014 में राजजात यात्रा संचालित किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि रविवार को नौटी में बारह थोकी ब्राह्मणों, चौदह सयानों के प्रतिनिधियों के साथ ही नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ के पुजारियों तथा समिति के विद्वत पीठ के विद्वानों तथा समिति के पदाधिकारियों से अनुमति लेने के पश्चात अगले वर्ष 17 अगस्त से नंदा देवी राजजात यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. 2014 में 17 अगस्त को गढ़वाल के राजवंशी कांसुवा के राजकुंवर कांसुवा से राज छंतोली व चौसिंघा मेंढे को लेकर सिद्धपीठ नौटी पहुंचेंगे. 18 अगस्त को नौटी से यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा. 24 अगस्त को कुलसारी में अमावस्या की पूजा होगी. एक सितंबर को बेदनीकुंड में सप्तमी की पूजा अर्चना क्रियाएं संपन्न की जाएंगी. 3 सितंबर को होमकुंड में नंदा राजजात की पूजा अर्चना संपन्न होने के पश्चात 6 सितंबर को यह यात्रा नौटी पहुंचेगी. 7 सितंबर को नौटी में श्रीमद्देवी भागवत के साथ राजकुंवरों की विदाई होगी. राजजात यात्रा का विधिवत कार्यक्रम 2014 में बसंत पंचमी के दिन नौटी में जारी किया जाएगा.

बच्चों की तस्करी रोकने को गंभीर प्रयास हो: अयोग

आपदा में सबकुछ खो चुके बच्चों को झांसा देकर मानव तस्कर फंसा सकते हैं. यह चिंता इन दिनों देवभूमि के लोगों को सता रही है. उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि प्रदेश सरकार आपदा में हुए लापता बच्चों का जो आंकड़ा पेश कर रही है, राज्य में इससे कहीं ज्यादा बच्चे लापता हैं. आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया का कहना है कि सरकार केवल 474 लापता बच्चों का आंकड़ा दे रही है, जिस किस्म की रिपोर्टे सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि यह संख्या ज्यादा होगी. बच्चों की तस्करी रोकने के लिए प्रदेश सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि बिना वेरिफिकेशन के बाहरी लोग आपदाग्रस्त गांवों में प्रवेश न कर सकें. अजय सेतिया का कहना है कि आयोग को चिंता है कि कहीं ये बच्चे मानव तस्करों के हाथ न पड़ जाएं. आयोग की चिंता है कि आपदा प्रभावित बच्चों की देखभाल कैसे की जाए. प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार आपदा के दौरान तीर्थयात्रियों के ही 287 बच्चे लापता हो गए हैं. जिलों से जो रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार, रुद्रप्रयाग में 181 बच्चे लापता हैं, जिला प्रशासन 146 बता रहा है. मामला केवल आंकड़ों का नहीं है. आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, जिस कारण बच्चे घरों में में अकेले हैं. सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि आपदा प्रभावित बच्चों की सुरक्षा की जा सके.

औद्योगिक क्षेत्र पर बिजली की आपदा

उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र पर बिजली संकट मंडरा रहा है. देहरादून समेत प्रदेश के उद्योगों के लिए दूसरा माह भी घाटे का रहा. राज्य में आई दैवीय आपदा के बाद अब औद्योगिक क्षेत्र भी बिजली की आपदा से जूझ रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे में मात्र आठ से दस घंटे ही बिजली मुहैया हो पा रही है. इसका खमियाजा न सिर्फ कंपनियों को उठाना पड़ रहा है, बल्कि इन कंम्पनियों में रोजगार पर लगे हजारों कर्मचारियों के साथ ही लाखों मजदूरों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादन कम होने व सरकार एवं निगम की औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ठोस नीति न होने से यह स्थिति पैदा हुई है. औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली न मिलने के कारण कंपनियों को रोज करीब 80 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. एक दिन में राज्य को बिजली के कारण अकेले जनपद देहरादून में स्थापित उद्योगों को लगभग 30 से 35 करोड़ की चपत लगी. पिछले दो माह से आपदा के नाम पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन द्धारा औद्योगिक क्षेत्रों को जरूरी बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। जिसका खमियाजा कंपनियों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है. प्रदेश की 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में करीब छह लाख कर्मचारी रोज ड्यूटी पर तो आ रहे हैं, बिजली न होने की वजह से काम नहीं हैं. औद्योगिक क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल होने से उद्य-ोगपतियों के चेहरों पर मायूसी छाने लगी है. उत्तराखंड इंडस्ट्री बेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का आरोप है कि ऊर्जा निगम के अधिकारियों द्धारा बिजली कटौती को लेकर पूर्व सूचनाएं नहीं दी जा रही है. कटौती की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है. निगम द्धारा पहले बताया गया कि आपदा के कारण कुछ दिनों तक बिजली की कमी रहेगी, लेकिन अब स्थिति में सुधार होने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है. औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले कर्मचारियों में भी अपने रोजगार को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. औद्योगिक संगठनों ने दावा किया है कि बिजली कटौती के कारण इन्हे रोज 80 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है. समय रहते कंपनियों को बिजली मुहैया नहीं कराई गई तो कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फिर पयर्टक कहेंगे 'वाह ताज'

उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में आगरा में ताजमहल के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से विकसित करने की योजना बना रही है. बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत ताजमहल के इर्द-गिर्द सड़कें दुरुस्त होंगी. फुटपाथ साफ-सुथरे होंगे. सीवरेज की बेहतर व्यवस्था होगी. मलिन बस्तियों में सुधार कार्य किए जाएंगे, ताकि ताज नगरी को अधिक से अधिक आकर्षित बनाया जा सके.

संदीप कश्यप

विश्व प्रसिद्ध मुहब्बत की निशानी ताजमहल उत्तर प्रदेश की धरोहरों में शामिल है. यह किसी भी प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन ताजमहल का रख–रखाव इस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा की किसी धरोहर का रखा जाता है. वैसे तो पूरे राज्य में फैली तमाम ऐतिहासिक धरोहरें अपनी बेबसी पर रो रही हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहा है. अब जनता में अपने इतिहास को सवांरने और ऐतिहासिक इमारतों को सहेजने के प्रति पहले जैसी बेरुखी नहीं दिखती है. अच्छी बात यह भी है की उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार आगरा में ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को पर्यटकों के हिसाब से विकसित करने की योजना बना रही है. बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत ताजमहल के इर्द–गिर्द सड़कें दुरुस्त, फुटपाथ साफ–सुथरे, सीवरेज की व्यवस्था, साफ–सफाई तथा मलिन बस्तियों में सुधार कार्यों के माध्यम से ताज क्षेत्र को अधिक से अधिक आकर्षित बनाया जाए. ताकि यहां आने वाले पयर्टक खुशी से झूमते हुए बोलें, 'वाह ताज.'

ताजमहल न केवल खूबसूरती का प्रतीक है, बल्कि यहां के लोगों के लिए कमाई का भी एक बड़ा जरिया है. उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक ताजमहल की गिनती देश के अग्रणी स्मारकों में की जाती है. ताजमहल को अपने देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से भी लोग देखने आते हैं. विश्व के कई हिस्सों में तो हिन्दुस्तान की पहचान ही ताजमहल से होती है. पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती और बनावट को देख कर वाह–वाह करने लगते हैं, लेकिन जब इनकी नजर आस–पास की गंदगी, अव्यवस्था आदि पर जाती है तो वाह की जगह इनके मुंह से आह निकलने लगती है. मगर शायद अब ऐसा न हो. राज्य सरकार संरक्षित स्मारक ताजमहल को देखने वाले पर्यटकों को सभी जरूरी और वह भी इनके स्टैंडर्ड की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ताजगंज क्षेत्र एवं ताजगंज स्थित 15 मलिन बस्तियों के सुधार के अंतर्गत सड़कों को सीसी रोड तथा गलियों को इंटर लौकिंग के माध्यम से सुधार करने की योजना बना रही है. जेपी क्रासिंग से ताजमहल पूर्वी द्वार तक पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा ताजमहल पश्चिमी द्वार से पश्चिमी गेट पार्किंग तक पर्यटन सुविधाओं के विकास सहित इस परियोजना की नियोजन विभाग द्वारा 13649 करोड़ के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय से भी इसे 15 जुलाई 2013 को अनुमति मिल गई है. वहीं इस योजना के लिए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने भी 2495 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें ताजमहल पूर्वी द्वार की तरफ के कार्य (लागत 1473 करोड़ रुपये) तथा पश्चिमी द्वार की तरफ कार्य (लागत 1001 करोड़ रुपये) पूरे किए जाएंगें.

ताजगंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 झुग्गी बस्तियों के सुधार की योजना के अंतर्गत 912 हाइस होल्ड टॉयलेट्स बनाए जाने का प्रावधान किया गया है. सैंपल टॉयलेट का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा शिल्पग्राम में तैयार किया गया है. ताजगंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत ओवर हेड विद्युत तारों को अंडर ग्राउंड केबिलिंग के कार्य टोरंट पावर लिमिटेड द्वारा अपने स्रोतों से एचटी लाइन्स को अंडर ग्राउंड किया जाएंगा. इस कार्य के लिए टोरंट पावर लि. को आदेश दिया गया है कि वह इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराए. आगरा में म्यूजियम प्रोजेक्ट स्थापित कराने के प्रस्ताव पर भी सरकार गंभीर है. इससे मुगलकालीन इतिहास तथा ताजमहल संबंधित जानकारी पर्यटकों को बिना किसी गाइड आदि के आसानी से उपलब्ध हो जाएगी. ताजगंज प्रोजेक्ट को कारपोरेट लुक भी दिया जाएगा. इसलिए उद्योग जगत के लोगों से भी सरकार विचार–विमर्श कर रही है, जिससे भविष्य में इस योजना का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन कराया जा सके.

गौरतलब हो औद्योगिक घराने के लोगों को सम्मिलित करने से यह योजना केवल सरकारी योजना नहीं रह जाएगी, बल्कि कारपोरेट वर्ग के सहयोग से बहुत अच्छा नतीजा आने की उम्मीद की जाएगी. ताज महोत्सव जिसमें भारी संख्या में लोग देश–विदेश से भाग लेने आते हैं, उसका भी स्वरूप बदला जाएगा. ताज महोत्सव को दिल्ली हाट की तर्ज पर आयोजित कराने का विचार राज्य सरकार कर रही है. कुल मिलाकर सरकार पर्यटकों के मुंह से बस दो ही शब्द सुनना चाहती है. वह है 'वाह ताज'. ■

feedback@chauthiduniya.com

मधुसूदन मिस्त्री से नहीं संभल रही कांग्रेस

दर्शन शर्मा

नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपने खास सिपहसालार अमित शाह को चुनाव प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा, आनन–फानन में कांग्रेस के थिंक टैंक ने गुजरात के जुझारू कांग्रेसी नेता मधुसूदन मिस्त्री को प्रभारी बनाकर उतार दिया. इससे मिस्त्री का कद और ऊंचा हो गया. अमित शाह और मधुसूदन के बीच प्रथमदृष्टया ऐसा लगा कि दोनों राजनीतिक योद्धा एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाले हैं. इसे लेकर कांग्रेसियों और भाजपाइयों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई. दोनों अपनी–अपनी पार्टी में सांगठनिक ढांचा मजबूत करने में लग गए. राजनीति के जानकार मानते हैं कि दोनों राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा की स्थिति एक जैसी है. जहां कांग्रेस में गुटबाजी और भाई भतीजावाद हावी है, वहीं भाजपा में भी आपसी कलह कम नहीं है. मोदी लहर को परखते हुए भाजपाइयों को अपनी जुबान बंद रखने की हिदायत दिल्ली भाजपा हाईकमान से मिली है, जिससे काफी हद तक भाजपा में गुटबंदी पर लगाम लगी है. संघ परिवार भी सख्ती बरत रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में राहुल का करिश्मा उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है. उनके नेता एसी में बैठकर राजनीति करने के आदी हो गए हैं. और कुछ बड़े नेताओं के अटपटे बयान कांग्रेस की साख को धूल–धूसरित कर रहे हैं. कांग्रेस के मिस्त्री की सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर बढ़ गई है कि 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जहां सपा और भाजपा के वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ रहा है. वहीं कांग्रेस के वोट पर चोट लग रही है. इससे मोदी और मुलायम मौज में हैं, लेकिन मिस्त्री मुश्किल में हैं. मिस्त्री कांग्रेस की गाड़ी को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस में बढ़ती अनुशासनहीनता और आंतरिक घमासान से जूझ रहे मिस्त्री का जहां यूपी से मोहभंग होता जा रहा है, वहीं आम कांग्रेसी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं दिखते. प्रदेश के बड़े नेता अपनी–अपनी ढपली, अपना–अपना राग अलापने में लगे हैं. ऐसे में मिस्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह क्या करें. वह कांग्रेस की गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं. इसी असहजता के कारण मिस्त्री लखनऊ में कम दिल्ली में प्रवास ज्यादा कर रहे हैं. प्रदेश कांग्रेसियों का मानना है कि मिस्त्री साहब भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, उनकी मानसिकता संघ जैसी है. जब वह गुजरात में अपनी सीट नहीं निकाल सके तो उत्तर प्रदेश में वह कितने कारगर रहेंगे. बहरहाल इससे साफ है कि मिस्त्री के प्रति अविश्वास की भावना प्रदेश कांग्रेसियों में व्याप्त है. वहीं मिस्त्री इसे लेकर पशो–पेश में हैं. अनुशासनहीनता से वह आजिज आ चुके हैं. वह प्रदेश के बड़े नेताओं के आगे अपने को बौना समझ रहे हैं. अब अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि अमित शाह को टक्कर देने आए मिस्त्री को प्रभारी पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है. ■

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366